



सत्यमेव जयते

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

### सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की आईटी लेखापरीक्षा

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

2023 की प्रतिवेदन संख्या 3

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन  
की आईटी लेखापरीक्षा**

संघ सरकार  
राजस्व विभाग  
(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)  
2023 की प्रतिवेदन संख्या 3

\_\_\_\_\_ को लोकसभा तथा राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया



## विषय सूची

सामग्री	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
<b>अध्याय I: विहंगावलोकन</b>	<b>1 - 9</b>
1.1 सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के बारे में	2
1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य	4
1.3 लेखापरीक्षा मानदंड	4
1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	4
1.5 लेखापरीक्षा पद्धति	5
1.6 लेखापरीक्षा की बाधाएं	6
<b>अध्याय II: आईटी शासन और आईटी सुरक्षा</b>	<b>11 - 54</b>
2.1 सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की शुरुआत	11
2.2 अधिग्रहण और अधिप्राप्ति	12
2.3 सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की तकनीकी आवश्यकताएं	16
2.4 विक्रेता के लिए काम का कार्यक्षेत्र	17
2.5 आईटी शासन और प्रबंधन	17
2.6 निकास प्रबंधन	32
2.7 सेवा स्तर करार (एसएलए) और परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति	33
2.8 परिवर्तन प्रबंधन	47
2.9 आईटी संरक्षा	50

<b>अध्याय III: कार्यात्मकताओं का कार्यान्वयन</b>	<b>55 - 137</b>
3.1 पंजीकरण मॉड्यूल	56
3.2 रिटर्न मॉड्यूल	95
3.3 भुगतान मॉड्यूल	103
3.4 एसीईएस से डेटा प्रवासन (माइग्रेशन)	106
3.5 प्रतिदाय मॉड्यूल	109
3.6 जांच मॉड्यूल	116
3.7 विवाद निपटान और समाधान (डीएसआर) मॉड्यूल	119
3.8 निर्यात मॉड्यूल	130
3.9 लेखापरीक्षा मॉड्यूल	131
3.10 करदाता- एक नज़र में - टीएजी	131
3.11 मोबाइल एप्लीकेशन	132
3.12 क्रॉस कटिंग के मुद्दे	133
<b>अध्याय IV: अन्य आईटी एप्लीकेशन के साथ इंटरफ़ेस</b>	<b>139 - 147</b>
4.1 इंटरफ़ेस से संबंधित मुद्दे जो विभाग के प्रमुख निर्णयों को प्रभावित करते हैं	140
4.2 अन्य आईटी एप्लीकेशन के साथ इंटरफ़ेस	146
<b>शब्दावली</b>	<b>149</b>

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्व विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। प्रतिवेदन में आईटी शासन और आईटी सुरक्षा, कार्यात्मकताओं के कार्यान्वयन और अन्य आईटी एप्लीकेशन के साथ इंटरफेस से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित मामले वे हैं, जो दिसंबर 2020 से अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



## कार्यकारी सार

सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की इस आईटी लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना था कि क्या:

- (i) आईटी शासन और आईटी सुरक्षा पर्याप्त और प्रभावी है;
- (ii) सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की कार्यात्मकताओं को परिकल्पित रूप में विकसित किया गया है और कर प्रशासन में आसानी सहित इच्छित लाभ प्राप्त किए गए हैं; और
- (iii) एप्लीकेशन में अन्य आईटी एप्लीकेशन के साथ प्रभावी इंटरफेस हैं।

लेखापरीक्षा में अगस्त 2015 से मार्च 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में विभिन्न मॉड्यूल और उनकी कार्यात्मकताओं, जीएसटीएन इंटरफेस और अन्य इंटरफेस, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन का अधिग्रहण, आईटी शासन, परिवर्तन प्रबंधन और एसएलए मापदंडों के अनुपालन को शामिल किया गया था।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार नीचे सूचीबद्ध है:

### अधिग्रहण और अधिप्राप्ति

कुल 12 संभावित बोलीदाताओं ने आरएफपी खरीदा, लेकिन सीबीआईसी के अप्रत्यक्ष कर एप्लीकेशन (जीएसटी और एसीईएस) के विकास और रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के चयन और प्रशिक्षण और हेल्पडेस्क सेवाओं के प्रावधान के लिए बोली प्रक्रिया में केवल एक बोलीदाता ने भाग लिया। इस प्रकार संभावित बोलीदाताओं से पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की कमी का संकेत मिला। **भविष्य में, विभाग को पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करके वेंडर लॉक-इन को कम करना चाहिए कि अगले अनुबंध के लिए निविदा में अधिक बोली लगाने वाले भाग लें। यह संभावित बोलीदाताओं और मौजूदा प्रणाली समेकक (एसआई) के बीच यथासंभव समतुल्य अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को तैयार करके किया जाए। साथ ही, इस निविदा को समय से शुरू किया जाए ताकि केवल एक बोली प्राप्त होने**

की स्थिति में, यदि आवश्यक हो तो, विभाग के पास पुनः निविदा के लिए पर्याप्त समय हो। मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।

### आईटी शासन और प्रबंधन

अभिलेखों की सीमित प्रस्तुति के कारण लेखापरीक्षा इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकी कि क्या परियोजना प्रबंधन कार्यालय और संचालन समिति परिकल्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। **विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएमओ और संचालन समिति परिकल्पित रूप से कार्य कर रहे हैं, ताकि परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जा सके।** एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय ने कहा कि सभी उपलब्ध कार्यालय अभिलेख लेखापरीक्षा टीम के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और इसे दोबारा लेखापरीक्षा के साथ साझा करने के लिए भी कहा गया था; हालाँकि, यह प्रतीक्षित था।

जांच और पंजीकरण मॉड्यूल में कतिपय सांविधिक आवश्यकताएं थीं जिन्हें एसआरएस में शामिल नहीं किया गया था। **विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं में निर्धारित सभी प्रावधानों, जिनमें अलग-अलग समय पर शुरू किए गए परिवर्तन शामिल हैं, को कार्यात्मकताओं के विकास के लिए एसआरएस में सटीक रूप से दर्शाया और अद्यतित किया जाए।** मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और कहा कि इन मॉड्यूलों में सुझाई गई कार्यात्मकताओं को विकसित किया जाएगा।

### मॉड्यूल का विकास और उपयोग

लेखापरीक्षा के समय तक मोबाइल एप्लीकेशन, निर्यात, लेखापरीक्षा और करदाता एक नजर में जैसे मॉड्यूल विकसित नहीं किए गए थे। अधिनिर्णयन, जांच और अपील के लिए मॉड्यूल की कार्यात्मकताओं का उपयोग केवल एक सीमित सीमा तक किया जा रहा था। **विभाग को आईटी शासन और प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना की समयसीमा का पालन किया जा रहा है और शुरू किए गए मॉड्यूल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है जैसी परिकल्पना की गई थी।** मंत्रालय ने कहा कि लेखापरीक्षा मॉड्यूल को 1 अप्रैल 2022 को शुरू किया

गया है और शेष मॉड्यूल के विकास और परिनियोजन में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

### **सेवा स्तरीय करार (एसएलए) और परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (एलडी)**

पांच एसएलए से संबंधित 32 मापदंडों में से, विभाग ने केवल 14 मापदंडों के लिए एसएलए अभिलेख प्रदान किए। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण एसएलए मापदंड में कहा गया कि 95 प्रतिशत व्यावसायिक संव्यवहारों का प्रतिक्रिया समय डेटा सेंटर में दो सेकंड की सीमा के भीतर होना था। प्रणाली समेकक (एसआई) विक्रेता द्वारा नियमित रूप से विभाग को इसके बारे में सूचित करने के बावजूद, इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि एप्लीकेशन विक्रेता की ओर से एप्लीकेशन बेसलाइनिंग लंबित थी। इस तरह की बेसलाइनिंग की अनुपस्थिति में, लक्षित निष्पादन तक पहुंचने में विफलता के लिए किसी विक्रेता को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। **विभाग को सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के एप्लीकेशन निष्पादन की बेसलाइनिंग के लिए जल्द से जल्द दोनों विक्रेताओं (एसआई और एप्लीकेशन विक्रेताओं) के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करना चाहिए।** मंत्रालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।

अन्य एसएलए मापदंडों के संबंध में, जिनके लिए अभिलेख प्रदान किए गए थे, विक्रेता द्वारा संसाधन परिनियोजन संभालने और हेल्पडेस्क परिचालन योजना (स्तर-1) प्रस्तुत करने में विलम्ब के मुद्दे थे। इसके अलावा, प्रतिदाय शिकायतों के आंकड़ों से पता चला कि संबंधित निर्धारित समय सीमा के बाद मामलों का समाधान किया गया था और कई मामले असमाधित रहे। **विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा स्तर समझौते के सभी पहलुओं के कार्यान्वयन की प्रभावी ढंग से निगरानी की जाए; विभाग और विक्रेता संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार अपनी-अपनी भूमिका निभाएं और गैर/विलंब से निष्पादन की प्रभावी ढंग से समीक्षा की जाए और सहमत समयसीमा के भीतर इसका समाधान किया जाए।** मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और कहा कि विभाग ने जुलाई-सितंबर 2021 तक किए गए सभी त्रैमासिक भुगतानों में अधिकतम 20 प्रतिशत एलडी की कटौती की है।

## पंजीकरण माँड्यूल

लेखापरीक्षा में व्यावसायिक परिसरों के अनिवार्य भौतिक सत्यापन (पीवी) के बिना पंजीकरण के डीम्ड अनुमोदन के उदाहरण पाए गए, जहां करदाताओं ने अपने आधार को प्रमाणित नहीं किया था। **विभाग को उन मामलों के लिए परिसर का पश्च भौतिक सत्यापन करना चाहिए जहां आधार प्रमाणित नहीं किया गया था। सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी प्रणाली में असत्यापित आधार स्थिति वाले करदाताओं के अनिवार्य भौतिक सत्यापन के बिना पंजीकरण की अनुमति नहीं देने का प्रावधान होना चाहिए। विभाग को उन मामलों के लिए अपवाद रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान करना चाहिए जहां करदाता के आधार सत्यापन और अनिवार्य भौतिक सत्यापन स्थिति की निगरानी और उचित कार्रवाई करने के लिए 'एन' के रूप में चिह्नित किया गया है।** मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए कहा कि जीएसटीएन द्वारा अगस्त 2020 से आधार प्रमाणीकरण सक्रिय किया गया था और इसे सीबीआईसी द्वारा 5 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया था और सिफारिश को नीति विंग को सूचित किया जा रहा था। तथ्य यह है कि आधार प्रमाणीकरण के स्थान पर भौतिक सत्यापन का प्रावधान 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होना चाहिए था।

उन मामलों में भी पंजीकरण को मंजूरी दी गई थी जहां पीवी रिपोर्ट में पंजीकरण आवेदनों को अस्वीकार करने की मांग की गई थी। **विभाग को एक अलर्ट विकसित करना चाहिए जिसके द्वारा सीपीसी अधिकारी प्रतिकूल/नकारात्मक टिप्पणियों की पहचान कर सकें। उसे ऐसे मामलों की एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने पर भी विचार करना चाहिए।** मंत्रालय ने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट किया।

अनिवार्य भौतिक सत्यापन के बिना एमसीए पोर्टल (स्पाइस-एजाइल फॉर्म) के माध्यम से दायर किए गए आवेदनों के मामले में पंजीकरण स्वीकृत किए गए थे, जहां करदाता ने या तो आधार प्रमाणीकरण को नहीं चुना था या आधार प्रमाणीकरण विफल हो गया था। **विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एमसीए पोर्टल के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में अनुमोदित नहीं किया जाता है, जब तक कि**

**इसे आधार प्रमाणित नहीं किया जाता, या भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हो जाता।** मंत्रालय ने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट किया और कहा कि प्रदत्त आवेदनों के लिए भौतिक सत्यापन की आवश्यकता है या नहीं, यह निर्णय जीएसटीएन प्रणाली द्वारा इंगित और सूचित किया जाता है। तथ्य यह है कि एमसीए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण आवेदनों के मामले में डीमड पंजीकरण से बचने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है।

पंजीकरण के लिए कतिपय आवेदनों को कर अधिकारी द्वारा न तो अनुमोदित किया गया और न ही अस्वीकार किया गया और उन मामलों में जहां आरईजी-03 के माध्यम से कर अधिकारी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, कर अधिकारी द्वारा पंजीकरण का अनुमोदन या डीमड अनुमोदन पाया गया। मंत्रालय ने कहा कि नियम 9 उन मामलों के लिए कोई समयसीमा प्रदान नहीं करता है जहां करदाता ने उत्तर नहीं दिया है और इसलिए सिस्टम में स्वतः-अस्वीकृति विकल्प नहीं बनाया गया है। **विभाग सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 9 के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकता है ताकि उन मामलों में पंजीकरण के लिए आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए एक समयसीमा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जा सके, जहां आवेदक सात दिनों के भीतर फॉर्म जीएसटी आरईजी -03 का उत्तर देने में विफल रहता है।**

पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन या कर अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्दीकरण के मामलों में निलंबन कार्यात्मकता लागू नहीं की गई थी। ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों को निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी कर योग्य आपूर्ति करने और परिणामस्वरूप क्रेडिट के हस्तांतरण से प्रतिबंधित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। **विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निलंबन कार्यात्मकता सीजीएसटी नियमों के अनुरूप सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में लागू की जाए।** मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए कहा कि निलंबन की प्रभावी तिथि को जीएसटीएन द्वारा एपीआई के माध्यम से सूचित किया जाना था और इसे एकीकरण के लिए लिया जाएगा। स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्दीकरण के मामले में, संवर्द्धन को कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा।

संयोजन उदग्रहण योजना (सीएलएस) के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के मामले में एकल पैन के तहत कुल कारोबार की गणना करने के लिए तंत्र का अभाव देखा गया था। **विभाग को रिटर्न से कुल कारोबार की गणना करने के लिए वैधीकरण को लागू करने और संयोजन उदग्रहण योजना के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित कारोबार सीमा को पार करने के बाद सामान्य करदाता स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए जीएसटीएन के साथ मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए कर अधिकारी के लिए अलर्ट को भी शामिल किया जा सकता है जहां करदाता संयोजन उदग्रहण योजना के लिए कारोबार सीमा को पार करते हैं। विभाग को ऐसे सभी पिछले मामलों की पहचान करनी चाहिए ताकि उन्हें सामान्य करदाता श्रेणी में लाया जा सके।** मंत्रालय ने पैरा स्वीकार करते हुए कहा कि विभाग ने पहले ही जीएसटीएन सीआर को प्राथमिकता दे दी है, जिसमें कुल कारोबार सीमा से अधिक वाले करदाताओं के लिए संयोजन विकल्प को प्रतिबंधित किया गया है।

संयोजन उदग्रहण योजना (सीएलएस) के अंतर्गत पंजीकृत एक ही पैन पर सामान्य करदाताओं के साथ-साथ कई पंजीकरणों की पहचान करने के लिए वैधीकरण एप्लीकेशन में नहीं बनाए गए थे। **विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रणाली में वैधीकरण मौजूद है ताकि एक ही समय पर सामान्य पंजीकरण के तहत करदाता को संयोजन उदग्रहण योजना के तहत एक ही पैन के साथ और इसके प्रतिकूल में पंजीकरण की अनुमति ना दी जाए। विभाग को ऐसे सभी पिछले मामलों की पहचान करनी चाहिए ताकि उन्हें सामान्य करदाता श्रेणी में लाया जा सके।** मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट किया और कहा कि जीएसटीएन डेटा बेस के साथ सभी पंजीकरण डेटा बेस का सुधार हेतु मिलान किया जाता है।

संयोजन करदाताओं के लिए प्रासंगिक कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्रों के कार्यान्वयन में देरी और संयोजन उदग्रहण योजना के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए पात्रता शर्तों को मान्य करने के लिए अपर्याप्त जांच पाई गई। इसके परिणामस्वरूप अपात्र करदाताओं जैसे कि संयोजन और सामान्य करदाताओं के रूप में मौजूद समान पैन करदाताओं की पहचान नहीं की गई। **विभाग को सीएमपी-5, सीएमपी-6 और सीएमपी-7 प्रपत्रों का शीघ्र विकास**

**सुनिश्चित करना चाहिए और वैधीकरण जांच अलर्ट सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उचित अधिकारी उन करदाताओं के विरुद्ध निर्धारित कार्रवाई शुरू कर सकें जो अब सीएलएस से संबंधित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।** मंत्रालय ने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट किया और कहा कि विभाग ने इसे लागू करने को प्राथमिकता दी है।

सामान्य करदाता जहां पिछली बार जीएसटीआर 3बी रिटर्न जनवरी 2020 से पहले फाइल किया गया था या जहां जनवरी 2020 से पहले एक भी जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, वे सक्रिय पाए गए। स्वतः संज्ञान रद्दीकरण कार्यात्मकता का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कई गैर-फाइलर पंजीकरण सक्रिय रहते हैं। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटीएन ने गैर-फाइलर की कार्यात्मकता के केंद्रीकृत विस्तृत निलंबन (निरस्तीकरण) को लागू किया है। **विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फाइल नहीं करने वालों के केंद्रीकृत विस्तृत निलंबन (निरस्तीकरण) की कार्यात्मकता का जीएसटीएन द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।**

जीएसटीआईएन प्राप्त करने के बाद पैंतालीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत नहीं करने वाले करदाताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, कर अधिकारियों को ऐसे करदाताओं की पहचान करने या ऐसे मामलों में रद्दीकरण की कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए कोई अलर्ट तंत्र नहीं था। **विभाग को नियम 21 और 21ए के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 10 और 10ए का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक खाता विवरण फाइल नहीं करने की स्थिति में कर अधिकारी के डैशबोर्ड पर अलर्ट कार्यात्मकता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।** मंत्रालय ने कहा कि इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा।

जहां कोई करदाता रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए आरईजी-17 में जारी एससीएन (कारण बताओ नोटिस) के उत्तर में रिटर्न फाइल करता है, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में कर अधिकारी को यह सचेत करने का कोई प्रावधान नहीं है कि रिटर्न फाइल कर दिया गया है। पंजीकरण

और रिटर्न मॉड्यूल के बीच सहबद्धता प्रदान नहीं की गई। **विभाग को पंजीकरण और रिटर्न मॉड्यूल के बीच एक लिंक प्रदान करना चाहिए ताकि रिटर्न फाइल करने और आरईजी -17 में नोटिस के उत्तर में करों का भुगतान करने पर कर अधिकारी को सचेत किया जा सके। सीजीएसटी नियमों के प्रावधानों के अनुसार समयसीमा के संबंध में प्रभावी वैधीकरण/अलर्ट प्रदान करने के लिए भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।** मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार कर लिया और कहा कि करदाताओं को नोटिस का उत्तर देने का अवसर प्रदान किया जाता है और इसलिए यदि उन्होंने फाइल किया है, तो इसे उचित अधिकारी को बहुत अच्छी तरह से सूचित किया जा सकता है।

जीएसटी प्रैक्टिशनर (जीएसटीपी) के नामांकन में संशोधन के लिए अधिनियम में प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण, सामान्य पंजीकरण के लिए प्रपत्र आरईजी -14 का उपयोग जीएसटी प्रैक्टिशनर पंजीकरण में मुख्य संशोधन के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि यह सुविधा केवल एक सुविधाजनक/सक्षम तंत्र है जिसका कोई राजस्व निहितार्थ नहीं है। **विभाग को जीएसटीपी संशोधनों की प्रक्रिया के लिए जीएसटी परिषद/जीएसटीएन विधि समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।**

### रिटर्न मॉड्यूल

प्रपत्र जीएसटीआर-4 को अभी भी लागू नहीं किया गया था, हालांकि बोर्ड ने अप्रैल 2019 में इसे अधिसूचित किया था। **विभाग को संशोधित फॉर्म जीएसटीआर-4 की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।** मंत्रालय ने स्वीकार किया कि कार्यात्मकता के विकास में देरी हुई है और कहा कि 17 फरवरी 2022 को विक्रेता के साथ मौजूदा अनुबंध में एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अनुसार सभी लंबित कार्यों को दक्ष प्रणाली के अंतर्गत टी एंड एम (समय और सामग्री) आधार पर किया जाएगा।

करदाता प्रकार के बेमेल होने के उदाहरण देखे गए; एप्लीकेशन में सामान्य करदाताओं को संयोजन करदाताओं के रूप में दर्शाया गया था। **विभाग को सीबीआईसी में डेटा को जीएसटीएन के आंकड़ों के साथ मिलाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और दिए हुए पंजीकरण के साथ सही**

**रिटर्न प्रकार को मैप करना चाहिए।** मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार किया और कहा कि जीएसटीएन और सीबीआईसी के बीच पंजीकरण डेटाबेस के संबंध में एक मिलान प्रक्रिया शुरू की गई है और सीबीआईसी डेटाबेस में इसे सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

संयोजन गैर-फाइलर्स के लिए "गैर-फाइलर्स देखें" कार्यात्मकता सक्रिय नहीं की गई थी। यहां तक कि जीएसटीआर-4 और सीएमपी-08 रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पर भी बल्क स्वतः संज्ञान रद्दीकरण की कार्यात्मकता लागू नहीं की गई थी। **विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जीएसटीआर-04 और सीएमपी-08 सहित सभी प्रकार के रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को सामान्य पोर्टल के माध्यम से जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी किया जाए।** मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

रिटर्न की संवीक्षा, सार और अनंतिम निर्धारण, जोखिम निर्धारण इंजन, खाता बही रखरखाव इत्यादि जैसी कार्यात्मकताओं को विकसित नहीं किया गया है और विकास के लिए समय सीमा को तय नहीं किया गया है। **विभाग को प्रभावी निगरानी के लिए कार्यात्मकताओं के विकास और परिनियोजन के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।** विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संवीक्षा और निर्धारण, जोखिम निर्धारण इंजन, खाता बही रखरखाव आदि जैसी महत्वपूर्ण कार्यात्मकताओं को समयानुसार विकसित और परिनियोजित किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि कार्यात्मकताएं विकास के अधीन हैं या जल्द ही एजाइल मोड के अंतर्गत शुरू की जाएंगी।

### प्रतिदाय मॉड्यूल

सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के माध्यम से अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा फाइल प्रतिदाय आवेदनों को संसाधित करने की कार्यात्मकता को "भविष्य में अनुसरण किए जाने के लिए" टिप्पणियों के साथ रोक दिया गया था। **विभाग को एसआरएस में यथा परिकल्पित अधिसूचित व्यक्तियों के लिए यूआईएन श्रेणी के प्रतिदाय आवेदनों को प्रसंस्कृत करने के लिए कार्यात्मकता विकसित करने के लिए जीएसटीएन के साथ मामले का अनुसरण करना चाहिए।** मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए कहा कि एक बार

जीएसटीएन फ्रंटएंड पर इस कार्यात्मकता को विकसित कर लेता है, तो इसे बैकएंड पर भी विकसित किया जाएगा।

अंतिम प्रतिदाय आदेश (आरएफडी-04) में अधिनियम के अंतर्गत या किसी मौजूदा कानून के अंतर्गत बकाया मांग के समायोजन की कार्यात्मकता को न तो एसआरएस में शामिल किया गया था और न ही विकसित किया गया था, हालांकि अधिनियम में इसका प्रावधान है। इसकी वजह से सरकारी राजस्व को जोखिम था। **विभाग को बकाया मांग के समायोजन के लिए कार्यात्मकता विकसित करने के लिए जीएसटीएन के साथ मामले का अनुसरण करना या अंतिम प्रतिदाय को स्वीकृति देते समय उचित अधिकारी को कम से कम ऐसी बकाया मांग के बारे में सचेत करना चाहिए।** मंत्रालय ने पैरा स्वीकार करते हुए कहा कि यदि जीएसटीएन, जीएसटीएन पोर्टल में कोई कार्यात्मकता विकसित करता है, तो उसे बैकएंड में भी विकसित किया जाएगा।

बकाया मांग के भुगतान पर, उठाई गई मांग की तिथि (मांग आईडी तिथि) से अंतिम प्रतिदाय से देय प्रतिदाय तक समायोजित राशि की तिथि तक ब्याज की वसूली/समायोजन का कोई प्रावधान नहीं था। **विभाग को जीएसटीएन के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बकाया मांग पर ब्याज की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में एक कार्यात्मकता विकसित और परिनियोजित की जाए।** मंत्रालय ने कहा कि ब्याज लघु शीर्ष के अंतर्गत देयता को कर लघु शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत राशि के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता है। तथापि, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए इस मुद्दे को जीएसटीएन के साथ उठाया गया था। मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है। प्रतिदाय आदेश में देय प्रतिदाय के विरुद्ध बकाया ब्याज देयता को समायोजित करने का प्रावधान है। तथापि, प्रणाली में मांग की तिथि (मांग आईडी तिथि) से अंतिम प्रतिदाय देय राशि से समायोजित राशि की तिथि तक की अवधि के लिए बकाया मांग के विलंब से समायोजन पर अर्जित ब्याज को समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

## विवाद निपटान और समाधान (डीएसआर) मॉड्यूल

### अधिनिर्णयन मॉड्यूल

डीएसआर मॉड्यूल के भाग के रूप में परिकल्पित विवाद जीवनकाल रजिस्टर का विकास न होना देखा गया, जिसमें जीवनकाल परिदृश्य के बिना मामलों के डेटा का सिस्टम में जमा होने का अंतर्निहित जोखिम है। **विभाग को डीएसआर (अधिनिर्णयन) मॉड्यूल के अंतर्गत विवाद जीवनकाल रजिस्टर का विकास सुनिश्चित करना चाहिए।** मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए कहा कि विभिन्न मॉड्यूल में सभी कार्यात्मकताओं के विकास के बाद विवाद जीवनकाल रजिस्टर विकसित किया जाएगा।

रिटर्न फाइल करने के लिए नियत तिथियों को संशोधित/अद्यतन करने के लिए कोई अंतर्निहित तंत्र नहीं था, जिसमें कानून/जीएसटी कौंसिल द्वारा अनिवार्य संशोधन/विस्तार भी शामिल था। **विभाग को रिटर्न मॉड्यूल के साथ एकीकरण में तिथियों को संशोधित/अद्यतित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की तकनीकी व्यवहार्यता पर चर्चा करनी चाहिए और मॉड्यूल में इसके लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।** मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार किया और कहा कि नियत तिथियों को स्वचालित करने के लिए रिटर्न मॉड्यूल के साथ डीआरसी -01 कार्यात्मकता को एकीकृत करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा।

### अन्य मॉड्यूल

निर्यात मॉड्यूल, करदाता-एक नजर में और मोबाइल एप्लीकेशन का विकास या तो शुरू नहीं हुआ था या विकास के प्रारंभिक चरण में था। **विभाग को समय पर निर्यात मॉड्यूल और मोबाइल एप्लीकेशन का विकास और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।** अनुपालन के लिए सिफारिशों को नोट करते हुए मंत्रालय ने कहा कि टीएजी के विकास की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी क्योंकि महानिदेशक (सिस्टम्स) के अंतर्गत अद्वैत परियोजना ने पहले ही एक समान डैशबोर्ड "अपने करदाता को जानें" लागू किया था।

## क्रॉस-कटिंग मुद्दे

प्रारूप चरण में पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर प्रपत्रों में किए गए व्यक्तिगत परिवर्तनों की सामग्री को रिकार्ड और संग्रहीत नहीं किया जा रहा है। संस्करण नियंत्रण सुविधा कार्यप्रवाह गतिविधि में अनुपस्थित पाई गयी। **विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोर्टल उपयोगकर्ता गतिविधि विवरण के हिस्से के रूप में कार्यप्रवाह में प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों/संशोधनों या कम से कम महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अभिग्रहित कर सकता है।** मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि सुझाई गई संस्करण नियंत्रण कार्यात्मकता का कार्यान्वयन तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन किया जाएगा।

नियमों द्वारा अधिदेशित उचित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर/ई-सत्यापन कोड पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर उपलब्ध नहीं थे। ऐसे डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर को किसी भी मॉड्यूल में शामिल और अपनाया नहीं गया है। **विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एकल अधिकारी द्वारा गैर-अस्वीकार्य तरीके से वैधानिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए उचित डिजिटल हस्ताक्षर कार्यात्मकता को सभी मॉड्यूल में शामिल किया और अपनाया जाए।**

इनपुट के रूप में प्रदान किए जा रहे देय कर, अवधि और ब्याज दर के अपेक्षित विवरण के साथ ब्याज की गणना को स्वचालित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सभी मॉड्यूल में ब्याज की गणना मैनुअल गणना के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे गणना की त्रुटियों के जोखिम की संभावना है। **विभाग को यथापरिकल्पित ब्याज की स्वचालित गणना के लिए कार्यात्मकता के विकास में तेजी लानी चाहिए।** मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार किया और कहा कि इस मुद्दे को जीएसटीएन के साथ उठाया जा रहा है।

## जीएसटीएन के साथ इंटरफेस

क्षेत्राधिकार के साथ अस्थायी संदर्भ संख्या को जोड़ने के लिए एक कार्यविधि का अभाव था। करदाता द्वारा स्वतः संज्ञान आदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं, इसकी निगरानी करने के लिए कर अधिकारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। **विभाग को इस मामले पर जीएसटीएन और पॉलिसी**

**विंग के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि क्षेत्राधिकार को टीआरएन के साथ जोड़ने के लिए एक उपयुक्त कार्यविधि तैयार की जा सके।** मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया है।

जीएसटी सामान्य पोर्टल और सीबीआईसी डेटाबेस के बीच डेटा के बेमेल होने के उदाहरण थे। साथ ही, बहीखाता में प्रविष्टियाँ अद्यतित नहीं हो रही थीं। डेटा का बेमेल होना डेटा की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता है जिससे आगे गलत एमआईएस रिपोर्टिंग होती है। **विभाग को सभी माँड्यूल के लिए दिन के अंत में मिलान तंत्र (इंटरफेस आधारित) लागू करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीबीआईसी डेटाबेस में डेटा हमेशा जीएसटीएन डेटाबेस के अनुरूप है।** मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया है।

सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन और जीएसटीएन पोर्टल में उपलब्ध स्थायी खाता संख्या (पैन) के बीच विसंगतियाँ पाई गईं। कुछ मामलों में, सीबीआईसी डेटाबेस में उपलब्ध कानूनी नाम जीएसटीआईएन के साथ मेल नहीं खा रहे थे। **विभाग को पैन में बेमेल होने, आरसी में गलत कानूनी नामों की मौजूदगी और सही पैन के विवरण, जिसके आधार पर आरसी जारी किए गए थे, के मामलों का मिलान करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।** मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया है।

### **अन्य आईटी एप्लीकेशन के साथ इंटरफेस**

सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन का उद्देश्य सीबीआईसी के भीतर विभिन्न एप्लीकेशन के साथ और बाहरी एजेंसियों जैसे आईसीईगेट, एसीईएस, आईसीईएस, सीपीजीआरएएमएस, एनएसडीएल, आरबीआई, एमसीए 21, राज्य स्तरीय एप्लीकेशन आदि के साथ इंटरफेस करना था। अन्य बाह्य प्रणालियों और एजेंसियों के साथ इंटरफेस कार्यविधि का विकास अभी तक शुरू नहीं किया गया है। **विभाग को अन्य एप्लीकेशन के साथ सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के इंटरफेस के विकास की शुरुआत करनी चाहिए।** मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट किया है।



## अध्याय I: विहंगावलोकन

भारत के संविधान के 101 वें संशोधन के कार्यान्वयन के माध्यम से 1 जुलाई, 2017 से माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था। जीएसटी न केवल कर ढांचे का सरलीकरण था, बल्कि करों के कार्यान्वयन और प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और गति पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक प्रणालीगत सुधार भी था। प्रौद्योगिकी इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए समाधान का एक प्रमुख घटक था। यह तभी संभव हो सकता था जब एक मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा और सेवा का मूल आधार हो जो हितधारकों के बीच सूचना के अभिग्रहण, प्रसंस्करण और आदान-प्रदान को सक्षम बनाता हो। इसके लिए एक विशेष उद्देश्य प्रणाली (स्पेशल पर्पस व्हीकल), माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) बनाया गया था। जीएसटीएन द्वारा विकसित जीएसटी पोर्टल पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान और प्रतिदाय मॉड्यूल हेतु करदाताओं के लिए फ्रंट-एंड पोर्टल है।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और राज्य जीएसटी प्राधिकरणों को यह विकल्प दिया गया था कि वे पंजीकरण, रिटर्न और भुगतान डेटा को बैक-एंड प्रक्रिया के रूप में संसाधित करने के लिए अपनी आईटी प्रणालियों और एप्लीकेशन को विकसित करें और करदाताओं को प्रतिदाय, जांच, लेखापरीक्षा, निर्यात, अधिनिर्णयन/अपील इत्यादि जैसी अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं या जीएसटीएन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाएं।

कुल 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने अपने करदाताओं और उनके कर अधिकारियों की फ्रंट-एंड और बैक-एंड गतिविधियों के लिए जीएसटीएन प्रणाली को उपयोग करने का विकल्प चुना है (जिन्हे मॉडल-1। राज्यों<sup>1</sup> के रूप में भी जाना जाता है)। दूसरी ओर, सीबीआईसी और नौ राज्यों/केंद्र

---

<sup>1</sup> अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

शासित प्रदेशों ने (जिन्हे मॉडल - 1 राज्यों<sup>2</sup> के रूप में जाना जाता है) बैक-एंड प्रक्रिया के रूप में पंजीकरण, रिटर्न और भुगतान डेटा को संसाधित करने के लिए कर प्रशासन हेतु अपने विभागीय कर अधिकारियों के लिए अपनी प्रणालियों और एप्लीकेशन को विकसित करने और करदाताओं और अपने विभागीय कार्मिक को व्यवसाय से संबंधित अन्य गतिविधियों अर्थात् प्रतिदाय, जांच, लेखापरीक्षा, निर्यात, अधिनिर्णयन/अपील आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करने का विकल्प चुना।

इस प्रकार, जहां तक सीबीआईसी का संबंध है, जीएसटीएन एक पास-थ्रू पोर्टल है, जो पंजीकरण, रिटर्न और भुगतान के लिए फ्रंट-एंड सुविधा प्रदान करता है और कुछ सत्यापन करने के बाद, जीएसटीएन आगे की कारवाई के लिए करदाताओं द्वारा अपने सिस्टम पर अपलोड किए गए या अन्य राज्य कर प्रशासनों और हितधारकों से प्राप्त दस्तावेजों की जानकारी और स्कैन की गई छवियाँ सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के साथ साझा करता है।

सीबीआईसी के संबद्ध कार्यालय, महानिदेशालय (सिस्टम और डेटा प्रबंधन) (डीजी (सिस्टम्स)) को इस बैक-एंड आईटी परियोजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। कुल मिलाकर, डीजी (सिस्टम्स) सीबीआईसी के अंतर्गत स्वचालित प्रणालियों के अभिकल्प, विकास, प्रोग्रामिंग, जांच, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए, और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सीबीआईसी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

### 1.1 सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के बारे में

सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन मुख्य रूप से सीबीआईसी कर अधिकारियों द्वारा प्रतिदाय, जांच, अधिनिर्णयन आदि जैसी विभिन्न जीएसटी कार्यात्मकताओं के बैक-एंड संसाधन के लिए है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क

---

<sup>2</sup> आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम और तमिलनाडु

और सेवा कर (एसीईएस<sup>3</sup>) एप्लीकेशन (केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर के लिए पूर्ववर्ती आईटी प्रणाली) के स्वचालन के प्रासंगिक मॉड्यूल को एप्लीकेशन में शामिल किया गया था। इस विकास के लिए अंतिम कार्यक्षेत्र जीएसटी व्यवस्था में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए लागू व्यावसायिक प्रक्रियाओं की स्थिति के अधीन था।

सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में एक्सेस कंट्रोल, पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान, प्रतिदाय/छूट, निर्यात, लेखापरीक्षा, विवाद निपटान (जांच, अधिनिर्णयन और अपील), करदाता-एक नजर में (टीएजी), एसीईएस स्थानान्तरण, मोबाइल ऐप जैसे 11 मॉड्यूल शामिल हैं। सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन का उद्देश्य आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से अन्य प्रणालियों/एप्लीकेशन के साथ इंटरफेस प्रदान करना है। बाहरी इंटरफेस जीएसटीएन, स्टेट बैकएंड सिस्टम्स, आरबीआई, बैंक, डीजीएफटी, एमसीए 21, सीबीडीटी, यूआईडीएआई, आईसीईजीएटीई, आईसीईएस, आरएमएस, एसीईएस, सीबीआईसी के ईडीडब्ल्यू आदि के साथ होना है। आंतरिक रूप से, इंटरफेस एप्लीकेशन के विभिन्न मॉड्यूल के भीतर होना चाहिए।

इस प्रकार, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी आईटी प्रणाली जीएसटी व्यवस्था में कर प्रशासन के लिए सीबीआईसी द्वारा लागू की गई एक नई प्रणाली है। हालांकि यह मुख्य रूप से जीएसटी व्यवस्था में विभागीय अधिकारियों द्वारा

---

<sup>3</sup> एसीईएस को 2009 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। यह एक केंद्रीकृत वेब आधारित और कार्य-प्रवाह आधारित प्रणाली है। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के प्रशासन के लिए सभी प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है। एसीईएस में विभाग और करदाताओं की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को संसाधित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के नौ मॉड्यूल और सेवा कर के छह मॉड्यूल हैं। एसीईएस निम्नलिखित प्रणालियों के साथ इंटरफेस करता है: i) पैन के ऑनलाइन सत्यापन के लिए आयकर; (ii) बैंकों से भुगतान (चालान) के सत्यापन के लिए ईएसआईईएसटी; और iii) आईईसी और निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए आईसीईएस। एसीईएस के कार्यात्मक मॉड्यूल को सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी अनुप्रयोग के साथ एकीकृत किया गया था। जीएसटी व्यवस्था के तहत, मौजूदा एसीईएस प्रणाली को कुछ वर्षों के लिए जारी रखा जाना है क्योंकि कुछ वस्तुओं के लिए एसीईएस प्रणाली की आवश्यकता होगी जो जीएसटी के कार्यक्षेत्र से बाहर रहे। इसके अलावा, मौजूदा करदाताओं द्वारा पिछली अवधियों/दायित्वों से संबंधित गतिविधियों जैसे कि पिछले रिटर्न फाइल करना, बकाया राशि का भुगतान, प्रतिदाय का दावा करना आदि को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, विवाद निपटान (पिछली अवधि), आदि के लिए प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है।

बैंक-ऑफिस संसाधन के लिए है, लेकिन इसमें कुछ करदाता इंटरफेस भी हैं जो मुख्य रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क करदाताओं से संबंधित हैं।

## 1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की इस आईटी लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आश्वासन लेना था कि क्या:

- (i) आईटी शासन विधि और आईटी सुरक्षा पर्याप्त और प्रभावी है;
- (ii) सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की कार्यात्मकताओं को परिकल्पित रूप में विकसित किया गया है और कर प्रशासन में आसानी सहित इच्छित लाभ प्राप्त किए गए हैं; और
- (iii) एप्लीकेशन में अन्य आईटी एप्लीकेशन के साथ प्रभावी इंटरफेस हैं।

## 1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

इस लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोत निम्नलिखित हैं:

- (i) केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017
- (ii) केंद्रीय जीएसटी नियमावली, 2017
- (iii) एकीकृत जीएसटी अधिनियम, 2017
- (iv) एकीकृत जीएसटी नियमावली, 2017
- (v) सीबीआईसी द्वारा जारी अधिसूचना और परिपत्र
- (vi) सिस्टम आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस)
- (vii) सामान्य वित्तीय नियम, 2005 और 2017
- (viii) प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)
- (ix) प्रधान सेवा समझौता (एमएसए)

## 1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की आईटी लेखापरीक्षा दिसंबर 2020-अप्रैल 2022 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा में अगस्त 2015 से

मार्च 2021 तक की अवधि को कवर किया गया था। लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में शामिल है:

- (i) मॉड्यूल और उनकी कार्यात्मकताओं का विकास
- (ii) जीएसटीएन इंटरफेस और अन्य इंटरफेस
- (iii) सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन का अधिग्रहण और अधिप्राप्ति
- (iv) आईटी शासन विधि
- (v) परिवर्तन प्रबंधन
- (vi) एसएलए मापदंडों के साथ अनुपालन

### 1.5 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा पद्धति संक्षेप में निम्नानुसार थी:

- (i) लेखापरीक्षा ने नवंबर 2020 में एक एंटी कॉन्फ्रेंस की।
- (ii) विभाग द्वारा वॉकथ्रू/प्रस्तुतियां साझा की गईं।
- (iii) एसआरएस और विभिन्न मॉड्यूल, परिवर्तन प्रबंधन से संबंधित अन्य दस्तावेजों की समीक्षा और विश्लेषण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था।
- (iv) सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूलों की कार्यात्मकताओं से संबंधित सत्यापन/लेखापरीक्षा जांच की जांच करने के लिए उपयोगकर्ता स्वीकृति जांच (यूएटी) वातावरण में जांच की गई थी।
- (v) सीबीआईसी डेटाबेस पर सीबीआईसी के माध्यम से प्रश्नों द्वारा डेटा का निष्कर्षण और ऐसे डेटा का आगे विश्लेषण किया।
- (vi) एसएलए निगरानी रिपोर्टों की समीक्षा और विश्लेषण और उस पर परिणामी कार्रवाई।

- (vii) लेखापरीक्षा को प्रदान की हुई एसएसओआईडी के माध्यम से सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की जांच करना।
- (viii) इस लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) के तीन क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् दिल्ली, चेन्नई और बंगलुरु ने सिस्टम महानिदेशालय (डीजी (सिस्टम्स)) की संबंधित शाखाओं में लेखापरीक्षा में भाग लिया था।
- (ix) लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों वाली मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट 13 जुलाई 2022 को टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी की गई थी।
- (x) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर मंत्रालय के उत्तर 30 अगस्त 2022 को प्राप्त हुए थे।
- (xi) 2 सितंबर 2022 को आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय के साथ मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की गई थी।
- (xii) एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय के उत्तरों और प्रस्तुतियों को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

## 1.6 लेखापरीक्षा में बाधाएं

जांच वातावरण और लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख प्रस्तुति वांछित स्तर तक नहीं था। इस परिलेखन में व्यक्त किये गए लेखापरीक्षा के विचार प्रदान की गई जानकारी की सीमा तक सीमित है, जो लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में खंडित थी।

परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ) और संचालन समिति की स्थापना और कार्यकरण, परियोजना की समय-सीमा और माइलस्टोन और इसके कार्यान्वयन, परिवर्तन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख की मांग के संबंध में, अभिलेख प्रस्तुति आंशिक थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा नमूना जांच क्षेत्रों के लगभग आधे के लिए जांच वातावरण प्रदान नहीं करने के कारण, लेखापरीक्षा मॉडलों में कार्यात्मकताओं के विकास को सत्यापित

नहीं कर सका। इस प्रकार, लेखापरीक्षा परिकल्पित एप्लीकेशन के विकास के बारे में पूर्ण आश्वासन प्रदान नहीं कर सकी।

विषय-वार बाधाएं नीचे उल्लिखित हैं:

### 1.6.1 आईटी शासन और प्रबंधन

परियोजना प्रबंधन कार्यालय और संचालन समिति की स्थापना और उनके कामकाज और बैठकों के ब्यौरे से संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसलिए, लेखापरीक्षा इस बात का आश्वासन नहीं दे सकी कि क्या आईटी शासन संरचना और परियोजना के प्रबंधन की देखरेख के लिए मंडलों/समितियों की भूमिका/कार्यकरण पर्याप्त और प्रभावी थे।

आरएफपी के अनुसार, घटनाओं की निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, निष्पादन जांच और उनके समय पर समाधान के लिए विक्रेता द्वारा एक घटना प्रबंधन टीम का गठन किया जाना था। तथापि, संगत दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या ऐसे समूह का गठन किया गया था और यदि नहीं, तो इन उत्तरदायित्वों को कैसे और किसके द्वारा निभाया गया था। इसके अलावा, आरएफपी में जोखिम प्रबंधन योजना की आवश्यकता थी जिसे भी लेखापरीक्षा के प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसलिए, लेखापरीक्षा यह जांच नहीं कर सकी कि क्या जोखिम प्रबंधन उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, इन्हें किसे सौंपा गया था और क्या मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) रिपोर्ट विक्रेता द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई थीं और सीबीआईसी द्वारा निगरानी और समीक्षा की गई थी।

### 1.6.2 सेवा स्तर समझौते

5 एसएलए से संबंधित 32 मापदंडों में से, लेखापरीक्षा को केवल 14 एसएलए मापदंडों से संबंधित दस्तावेज प्रदान किए गए थे। सहायता डेस्क और तकनीकी सहायता घटना/टिकट समाधान (एल2 और एल3) और सुरक्षा (भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण) से संबंधित किसी भी एसएलए मापदंड के लिए कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा इन मापदंडों के संबंध में कार्यप्रणाली और सेवा पर कोई राय नहीं बना सकी।

### 1.6.3 परिवर्तन के लिए अनुरोध

कुछ परिवर्तन अनुरोधों पर अलग-अलग दस्तावेजों के अलावा, विभाग ने परिवर्तन नियंत्रण बोर्ड (सीएबी) की स्थापना, परिवर्तन नियंत्रण विवरणिका, किसी भी परिवर्तन अनुरोध को लागू करने से पहले रद्द करने की प्रक्रिया (बैकऑउट प्रोसेस) के विकास, सिस्टम में आपातकालीन परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रियाओं, परिवर्तन आदेश प्रलेखन आदि से संबंधित अभिलेख प्रदान नहीं किए।

### 1.6.4 पंजीकरण मॉड्यूल

जांच वातावरण का प्रावधान न होने के कारण, लेखापरीक्षा सामान्य करयोग्य व्यक्ति या एनआरटीपी द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम कर की प्रक्रियाओं और क्या वह अनुमानित कर देयता के बराबर है, व्यवसाय के मूल स्थान में परिवर्तन की कार्यात्मकता और पंजीकरण को गलत तरीके से रद्द होने की जांच नहीं कर सकी।

### 1.6.5 रिटर्न मॉड्यूल

लेखापरीक्षा कतिपय महत्वपूर्ण कार्यात्मकताओं का परिनियोजन न किए जाने के कारणों की पुष्टि नहीं कर सकी (इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.2 को देखें) और क्या ऐसी कार्यात्मकताओं के कार्यक्षेत्र कम करने/गैर-विकास के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, 21 परामर्शी के माध्यम से जारी रिपोर्टों की शुद्धता की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग ने जांच वातावरण (यूएटी) प्रदान नहीं किया था।

### 1.6.6 भुगतान मॉड्यूल

एपीआई के वॉकथ्रू की सुविधा नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि भुगतान किए गए चालानों का प्राथमिक डेटा जीएसटीएन द्वारा वास्तविक समय के आधार पर प्रेषित किया गया था या नहीं, जैसा कि एसआरएस में निर्दिष्ट किया गया था। जांच वातावरण की सुविधा न होने के कारण एमआईएस रिपोर्ट की जांच नहीं की जा सकी।

### 1.6.7 डेटा प्रवासन मॉड्यूल

जांच वातावरण की सुविधा न होने के कारण जीएसटी के अंतर्गत समाहित नहीं किए गए उत्पादों के लिए व्यवसाय की निरंतरता को सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में जांचा नहीं जा सका।

### 1.6.8 प्रतिदाय मॉड्यूल

लेखापरीक्षा, भुगतान सलाह जारी करने की प्रक्रिया और विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की जांच नहीं कर सका क्योंकि विभाग ने इन पहलुओं के लिए यूएटी वातावरण में जांच प्रदान नहीं की थी। इनपुट टैक्स जमा (आईटीसी) को खाता बही में फिर से जमा करने की प्रक्रिया और आर 1 और आर 2 रिपोर्ट जिनके लिए अन्य हितधारकों (बैंक, पीएफएमएस आदि) के साथ एकीकरण की आवश्यकता होती है, को भी सत्यापित नहीं किया जा सका।

### 1.6.9 अधिनिर्णयन मॉड्यूल

जब लेखापरीक्षा प्रक्रिया में थी, तब छह कार्यात्मकताएं यूएटी के अंतर्गत थीं, और इन कार्यात्मकताओं को बाद में शुरू किया गया था। छह कार्यात्मकताओं में से, लेखापरीक्षा यूएटी वातावरण में दो कार्यात्मकताओं को सत्यापित कर सकी है - 'ओआईओ जारी करना' जिसमें हमने देखा कि अनुमोदन फंक्शन 'फ्रंट-एंड' में काम नहीं कर रहा था और 'अपवंचन-रोधी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना' में जिसमें हमने देखा कि 'फ्रंट-एंड' में कार्यप्रवाह में प्रस्तुत अभिलेख गायब था। जीएसटीएन के अंत पर जांच वातावरण में कार्यात्मकता की प्रतिकृति न होने के कारण दो कार्यात्मकताओं - पीएच रिपोर्टिंग और प्रतिदाय के लिए कारण बताओ नोटिस की जांच नहीं की जा सकी। शेष दो कार्यात्मकताओं - डीआरसी 08 और कॉल बुक का लेखापरीक्षा को दिए गए क्रेडेंशियल के काम न करने के कारण जांच नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा, इस लेखापरीक्षा के दौरान सीबीआईसी और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग को स्वीकार करता है।



## अध्याय II: आईटी शासन और आईटी सुरक्षा

लेखापरीक्षा ने सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के समग्र आईटी शासन और आईटी सुरक्षा की जांच की और आश्वासन प्राप्त करने का प्रयास किया। लेखापरीक्षा का केन्द्रबिन्दु अधिग्रहण प्रक्रिया, बोर्डों/समितियों की भूमिका और कामकाज, सेवा स्तर समझौतों, परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया और आईएस सुरक्षा पर था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि कुल 12 संभावित बोलीदाताओं ने आरएफपी खरीदा, लेकिन केवल एक बोलीदाता ने बोली में भाग लिया। अधिनियम/नियमावली में दिए गए प्रावधानों की तुलना में विभिन्न मॉड्यूलों के एसआरएस की संवीक्षा के दौरान कतिपय कमियां पाई गई थीं।

निकास प्रबंधन योजना और हेल्पडेस्क परिचालन योजना विक्रेता से देरी से प्राप्त की गई थी। एसएलए की उपलब्धि न होने पर परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण किया गया था।

### 2.1 सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की शुरुआत

राजस्व विभाग का केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) माल एवं सेवा कर के उद्ग्रहण और संग्रह से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य देखता है। सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी (सिस्टम्स)) को सीबीआईसी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है।

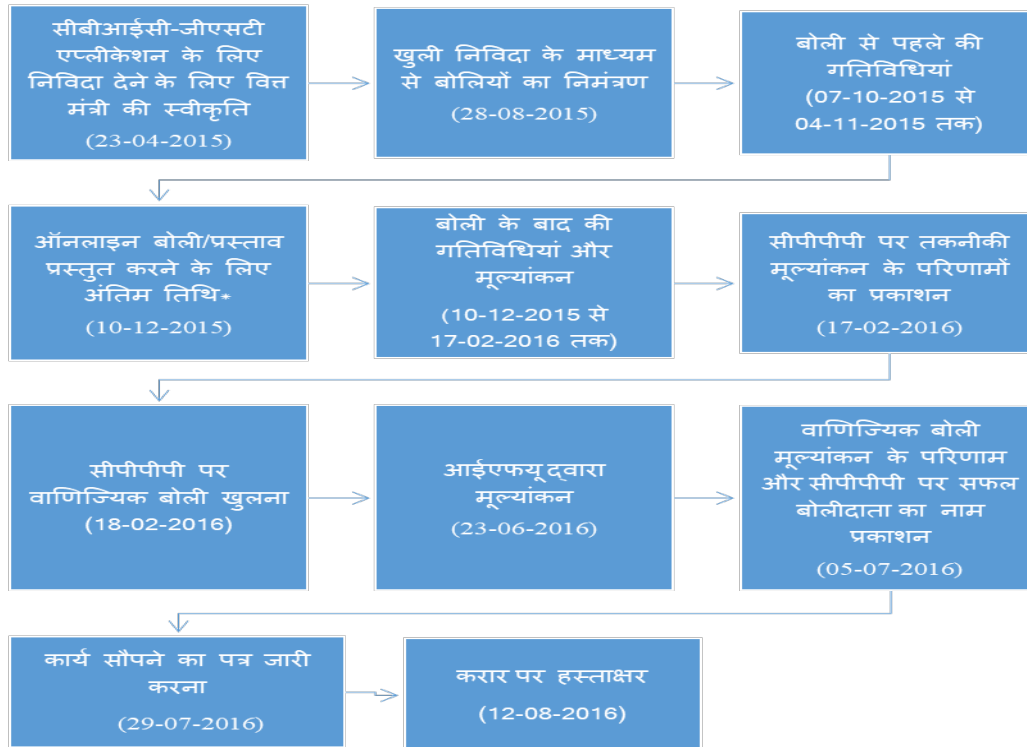
चूंकि सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की परिकल्पना और कार्यान्वयन के समय, जीएसटी कानून अधिनियमित नहीं किए गए थे और जीएसटी में अपनाई जाने वाली व्यावसायिक प्रक्रियाओं के विवरण को पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था, इसलिए आरएफपी संख्या IV (39)/4/आरएफपी जीएसटी 01/2015 के माध्यम से "सीबीआईसी के अप्रत्यक्ष

कर एप्लीकेशन (जीएसटी और एसीईएस) के विकास और रखरखाव के लिए विक्रेता की नियुक्ति और प्रशिक्षण और हेल्पडेस्क सेवाओं के प्रावधान" के लिए जारी प्रस्ताव निवेदन में व्यावसायिक प्रक्रियाओं के एक व्यापक कार्यक्षेत्र का प्रावधान था जिसे जीएसटी व्यवस्था में अपनाया जाना था।

कराधान एक गतिशील अवधारणा होने के नाते, यह समझा गया कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं और केंद्र, राज्यों और जीएसटीएन द्वारा कम से कम संभव समय अवधि में स्वचालित होने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी हितधारकों के साथ नियमित, समय पर और प्रभावी बातचीत और प्रणाली में आवधिक संशोधनों, एप्लीकेशन, नई कार्यात्मकताओं को जोड़ने और नई आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी जो नई कर व्यवस्था में एक सुचारु बदलाव सुनिश्चित करेंगे।

## 2.2 अधिग्रहण और अधिप्राप्ति

### कालक्रम चार्ट - विक्रेता के अधिग्रहण और अधिप्राप्ति के लिए समयसीमा



\* बोली जमा करने की अंतिम तिथि 28.10.2015, 18.11.2015, 26.11.2015 और 10.12.2015 तक बढ़ा दी गई थी।

पूर्ववर्ती सीबीईसी (वर्तमान सीबीआईसी) ने 2011 में जीएसटी प्राथमिक प्रयोग शुरू किया था और जीएसटीएन का गठन 2014 में किया गया था। अप्रैल 2015 में, जीएसटी की तैयारियों पर विचार-विमर्श के भाग के रूप में, विभाग ने जीएसटी पोर्टल से अलग एक एप्लीकेशन विकसित करने का प्रस्ताव दिया, जो सीबीईसी विभागीय उपयोगकर्ताओं के लिए जीएसटीएन पोर्टल द्वारा कैप्चर किए गए पंजीकरण, रिटर्न और भुगतान डेटा को संसाधित करने के लिए बैक-ऑफिस समाधान के रूप में काम करेगा। एप्लीकेशन और रोल-आउट के विकास के लिए 10 अगस्त 2015 से 1 अप्रैल 2016 तक और रखरखाव के लिए 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2021 के बीच विभाग द्वारा नियोजित समय सीमा पांच वर्ष की अवधि के लिए थी। सीबीईसी ने इस एप्लीकेशन के विकास के लिए 'जीएसटी 01.04.2016 के लिए तैयारी' प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के समक्ष 10.04.2015 को रखा था।

प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था कि पीएमयू (मैसर्स पीडब्ल्यूसी) ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी और सीबीईसी के मौजूदा आईटी बुनियादी ढांचे की 'जैसा है' क्षमता और 2016 तक आवश्यक बुनियादी ढांचे की 'होने की' स्थिति की तुलना के आधार पर अंतर विश्लेषण किया था। पीएमयू ने परियोजना के लिए ₹163.58 करोड़ से ₹202.44 करोड़ के बीच लागत का अनुमान तैयार किया था।

23 अप्रैल 2015 को वित्त मंत्री ने जीएसटी की एप्लीकेशन के विकास के लिए निविदा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

अगस्त 2015 में, महानिदेशालय सिस्टमस (डीजी (सिस्टम्स)) ने सीबीआईसी की अप्रत्यक्ष कर एप्लीकेशन (जीएसटी और एसीईएस) के विकास एवं रखरखाव तथा प्रशिक्षण और हेल्पडेस्क सेवाओं के प्रावधान के लिए कार्यान्वयन संस्था के चयन हेतु आरएफपी के माध्यम से एक खुली निविदा आमंत्रित की। विक्रेता का चयन लागत-आधारित चयन के अंतर्गत किया जाना था।

कुल 12 संभावित बोलीदाताओं ने आरएफपी खरीदा था। सितंबर और अक्टूबर 2015 में संभावित बोलीदाताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए बोली-

पूर्व कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। संभावित बोलीदाताओं के अनुरोध पर विभाग द्वारा बोली जमा करने की तिथि चार चरणों में 71 दिनों अर्थात् 30 सितंबर से 10 दिसंबर 2015 तक बढ़ा दी गई थी। तथापि, नियत तिथि तक केवल एक ही बोली मैसर्स विप्रो लिमिटेड से प्राप्त हुई थी, जबकि 12 संभावित बोलीदाताओं ने आरएफपी को खरीदा था और संभावित बोलीदाताओं के अनुरोध पर बोली प्रस्तुत करने की तिथि बढ़ा दी गई थी। निविदा खोलने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2015 को शुरू हुई थी।

बोली का प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया था और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान कवर 1 (सत्यनिष्ठा संधि, प्राधिकरण पत्र और ईएमडी) और कवर 2 (पूर्व-योग्यता बोली) की जांच की गई थी।

पीएमयू (जीएसटी) और डीजी सिस्टम अधिकारियों की सहायता से तकनीकी मूल्यांकन समूह (टीईजी) द्वारा जनवरी 2016 और फरवरी 2016 में तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया गया था। मैसर्स विप्रो लिमिटेड ने इस चरण के लिए 70 के कट-ऑफ अंकों के प्रति 80.6 के स्कोर के साथ इस चरण में अर्हता प्राप्त की, जैसा की नीचे विस्तृत है।

**तालिका 2.1 - बोली का प्रारंभिक मूल्यांकन**

क्र. सं.	मूल्यांकन मापदंड	कुल अंक	न्यूनतम कट-ऑफ (60%)	प्राप्त अंक	अर्हता स्थिति
1.	बोलीदाता की साख	15	>=9	15	अर्हता प्राप्त
2.	दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली	10	>=6	7.6	अर्हता प्राप्त
3.	समाधान आर्किटेक्चर	23	>=14	16.1	अर्हता प्राप्त
4.	प्रमुख संसाधन	40	>=24	32.9	अर्हता प्राप्त
5.	प्रस्तुति और प्रदर्शन	12	>=7	9	अर्हता प्राप्त
<b>कुल</b>		<b>100</b>	<b>70 (70%)</b>	<b>80.6</b>	<b>अर्हता प्राप्त</b>

तकनीकी बोली चरण को अर्हता प्राप्त करने के बाद, बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के लिए गठित (मार्च 2016) दो अलग-अलग कीमत मूल्यांकन समितियों (पीईसी) द्वारा वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन किया गया था। दोनों समितियों ने पाया कि मूल बोली (₹190.17

करोड़) में बोलीदाता द्वारा उद्धृत कुल कीमत, पीजीएमए<sup>4</sup> (जिसे पहले पीएमयू<sup>5</sup> के रूप में जाना जाता था) द्वारा अनुमानित लागत सीमा (₹163.58 करोड़ से ₹202.44 करोड़) के औसत मूल्य (₹183.01 करोड़) के काफी करीब थी। हालांकि, बोलीदाता ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बोली राशि घटाकर कर सहित ₹184.00 करोड़ करने की पेशकश की।

डीजी (सिस्टम्स) ने मूल बोली के साथ साथ संशोधित वाणिज्यिक बोली को अनुमोदन के लिए 23 जून 2016 को आईएफयू<sup>6</sup> को भेजा। राजस्व सचिव ने स्थायी वित्त समिति (एसएफसी), राजस्व विभाग की मूल्यांकन बैठक (24 जून 2016) के दौरान एनआईसी, सीबीडीटी, डीआईटीवाई और आईएफयू के अधिकारियों की एक स्वतंत्र कीमत मूल्यांकन समिति (पीईसी) द्वारा कीमत मूल्यांकन की तर्कसंगतता पता लगाने का सुझाव दिया गया। स्वतंत्र पीईसी ने 05 जुलाई 2016 को डीजी (सिस्टम्स) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और मैसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा उद्धृत ₹184 करोड़ की कीमत, को उचित मानकर, की सिफारिश की। वित्त मंत्री से 01 अगस्त 2016 को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी। डीजी (सिस्टम्स) ने 29 जुलाई 2016 को मैसर्स विप्रो को कार्य सौंपने का पत्र जारी किया और 12 अगस्त 2016 को डीजी (सिस्टम्स) और विक्रेता के बीच प्रमुख सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मैसर्स विप्रो लिमिटेड जिसे यह संविदा प्रदान की गई थी, एसीईएस विरासत प्रणाली का डेवलपर और रखरखावकर्ता था और अन्य 11 संभावित बोलीदाताओं की तुलना में इसकी कर प्रशासन के कार्यप्रवाह के साथ बेहतर परिचित होने की संभावना थी। ₹184 करोड़ की एकल बोली संविदा मैसर्स विप्रो लिमिटेड को प्रदान की गई थी, जिसमें सीबीआईसी की टिप्पणियों में अपनाई गई उचित प्रक्रिया की वैधता और अनुमानित कीमत सीमा का औसत मूल्य होने के कारण प्रदान किए गए कार्य के मूल्य की तर्कसंगतता का हवाला दिया गया था और यह भी कि आवश्यक जीएसटी एप्लीकेशन को विकसित करने और मौजूदा अनुबंध की

<sup>4</sup> कार्यक्रम शासन और निगरानी एजेंसी; पीडब्ल्यूसी प्राइवेट लिमिटेड

<sup>5</sup> कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

<sup>6</sup> एकीकृत वित्तीय इकाई

समाप्ति पर एसीईएस प्रणाली को संभालने के लिए पुनर्निविदा के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2022)।

**सिफारिश 1: भविष्य में, विभाग को पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करके वेंडर लॉक-इन को कम करना चाहिए कि अगले अनुबंध के लिए निविदा में अधिक बोली लगाने वाले भाग लें। यह संभावित बोलीदाताओं और मौजूदा प्रणाली समेकक (एसआई) के बीच यथासंभव समतुल्य अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को तैयार करके किया जाए। साथ ही, इस निविदा को समय से शुरू किया जाए ताकि केवल एक बोली प्राप्त होने की स्थिति में, यदि आवश्यक हो तो, विभाग के पास पुनः निविदा के लिए पर्याप्त समय हो।**

### 2.3 सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की तकनीकी आवश्यकताएं

विक्रेता से उच्च-स्तरीय समाधान आर्किटेक्चर के अनुरूप एप्लीकेशन को डिजाइन, विकसित और परिनियोजित करने और वांछित सेवा स्तरों को पूरा करते हुए आरएफपी में उल्लिखित सभी कार्यात्मकताओं, तकनीकी और परिचालन सुविधाओं को प्रदाय करने में सक्षम होने की उम्मीद थी। इस एप्लीकेशन को अत्यधिक विघटित, मॉड्यूलर, स्केलेबल और एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के रूप में परिकल्पित किया गया था, जिसे सीबीआईसी (अब सीबीआईसी) के डेटा सेंटर (डीसी) और आपदा रिकवरी साइट पर केंद्रीय रूप से परिनियोजित किया जाना था, जिसमें उपयुक्त चैनलों के माध्यम से सभी हितधारकों के लिए आवश्यक इंटरफेस उपलब्ध होने थे।

एप्लीकेशन वेब-आधारित होगी और प्रभावी डेटा पुनः प्राप्ति और भंडारण के लिए तार्किक विभाजन के साथ बैकएण्ड डेटाबेस में एकीकृत होगी। यह भी प्रस्तावित किया गया था कि संपूर्ण एप्लीकेशन में 'एप्लीकेशन लेयर' और 'डेटाबेस लेयर' के बीच डेटा और बिजनेस लॉजिक के कुशल संचालन का समर्थन करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित 'बिजनेस लॉजिक लेयर'

और 'डेटा एक्सेस लेयर' के साथ लचीला और स्केलेबल आर्किटेक्चर होना चाहिए। एप्लीकेशन को 'एंटरप्राइज़ सर्विस बस' द्वारा समर्थित किया जाएगा, जो विभिन्न इंटरफेसिंग निकायों के बीच प्रभावी डेटा विनिमय और बातचीत को सक्षम करेगा।

यह देखते हुए कि जीएसटी विनियमों की गतिशील प्रकृति के कारण, समय के साथ व्यावसायिक आवश्यकताएं तरल रह सकती हैं, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी प्रणाली की कार्यात्मकताओं और विशेषताओं को इतना गैनुलर और मॉड्यूलर होने की परिकल्पना की गई थी कि प्रशासक आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय, एक डेवलपर/कोड स्तर परिवर्तन/कस्टम यूआई परिवर्तन की आवश्यकता के बिना किसी विशेष कार्यात्मकता को सक्षम या अक्षम बना सकें। जबकि प्रमुख मॉड्यूल निर्दिष्ट किए जा चुके थे, यह एक प्रमुख आवश्यकता थी कि एप्लीकेशन को कार्य प्रवाह के निर्माण को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न मॉड्यूल के बीच संपूर्ण एकीकरण को सक्षम बनाना चाहिए जिससे कि सभी मॉड्यूल में जानकारी का लाभ उठाया जा सके।

## 2.4 विक्रेता के लिए कार्य का दायरा

कार्य के दायरे को कई चरणों में लागू किया जाना था:

चरण 1: एसीईएस का अधिग्रहण एवं संचालन तथा रखरखाव

चरण 2: सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी प्रणाली का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन

चरण 3: सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी प्रणाली का संचालन तथा रखरखाव

चरण 4: सीबीआईसी अधिकारियों का प्रशिक्षण

चरण 5: हेल्पडेस्क कार्य

## 2.5 आईटी प्रशासन और प्रबंधन

आईटी प्रशासन, संगठनों को अपने आईटी जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह वर्तमान व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करता है और इसमें भविष्य की

जरूरतों और विकास के लिए योजनाएं शामिल हैं। यह उद्यम प्रशासन का एक अभिन्न अंग है और इसमें संगठनात्मक नेतृत्व, संस्थागत संरचनाएं और प्रक्रियाएं, और अन्य तंत्र (रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया, प्रवर्तन, संसाधन आदि) शामिल हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आईटी प्रणाली, जोखिमों को संतुलित करते हुए और संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हुए संगठनात्मक लक्ष्यों और रणनीति को बनाए रखें।

तालिका 2.2 - सारांशित लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

क्र. सं.	उप-उद्देश्य	लेखापरीक्षा जांच का सारांश	स्थिति	निष्कर्ष
1	संगठन कैसे नई / पुरानी व्यावसायिक आवश्यकताओं की पहचान और अनुमोदन या अस्वीकार करता है?	परियोजना प्रबंधन कार्यालय	न्यूनतम अभिलेख प्रस्तुतिकरण	2.5.1 2.5.3
2	नेतृत्व कैसे परियोजना के प्रदर्शन को निर्देशित और निगरानी करता है?	संचालन समिति, पाक्षिक और मासिक बैठकें, लागत में भिन्नता, अनुसूची और योजना के अनुसार प्रदर्शन संकेतक, उचित अनुमोदन, परियोजना संगमिल	न्यूनतम अभिलेख प्रस्तुतिकरण	2.5.2 2.5.4 2.5.4.1 2.5.4.2 2.5.4.3 2.5.5
3	सीबीआईसी कैसे उनके जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करता है?	घटना प्रबंधन दल, असुरक्षित क्षेत्र, निष्पादन जांच, जोखिम प्रबंधन योजना, जोखिम कम करना, मूल कारण विश्लेषण (आरसीए)	सीमा प्रतिबन्ध	-

परियोजना के निष्पादन को निर्देशित और निगरानी करने के लिए, आरएफपी में एक परियोजना प्रबंधन कार्यालय और एक संचालन समिति के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

### 2.5.1 परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ)

परियोजना की शुरुआत के दौरान विक्रेता की ओर से एक नामित पूर्णकालिक परियोजना प्रबंधक और क्रेता के अधिकारियों और आमंत्रित अन्य प्रतिनिधियों सहित अन्य प्रासंगिक हितधारकों के प्रमुख व्यक्तियों के साथ एक परियोजना प्रबंधन कार्यालय स्थापित किया जाना था।

पीएमओ को साप्ताहिक स्थिति, बैठकों के कार्यवृत्त, साप्ताहिक/मासिक/परियोजना योजनाओं आदि को बनाए रखना अपेक्षित था। पीएमओ को साप्ताहिक आधार पर औपचारिक रूप से बैठक करनी थी, जिसमें कम से कम निम्नलिखित कार्यसूची मद शामिल किए जाने थे:

- परियोजना की प्रगति
- मुद्दे और चिंताएं
- अनसुलझे और बढ़े हुए मुद्दे
- परिवर्तन प्रबंधन - प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हो
- कोई अन्य मुद्दे जिसे कोई भी पक्ष कार्यसूची में जोड़ना चाहता था।

लेखापरीक्षा ने परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ) की स्थापना से संबंधित दस्तावेज मांगे थे (जुलाई 2021); हालाँकि, दस्तावेजों को प्रदान नहीं किया गया था। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर लेखापरीक्षा में परियोजना प्रबंधन कार्यालय की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं मिल सका जिसमें विक्रेता से एक नामित पूर्णकालिक परियोजना प्रबंधक और क्रेता के अधिकारियों और अन्य प्रतिनिधियों सहित अन्य प्रासंगिक हितधारकों के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रण द्वारा शामिल किया जाना था।

### 2.5.2 संचालन समिति

संचालन समिति की परिकल्पना बड़े परिवर्तनों पर परियोजना निर्णय लेने और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी, जिसमें

क्रेता, इसकी नामित एजेंसियों, क्रेता और विक्रेता के लिए सलाहकारों के वरिष्ठ हितधारक शामिल थे। विक्रेता को संचालन समिति की बैठकों में भाग लेना था और परियोजना की प्रगति, जोखिम मापदंडों (यदि कोई हो), संसाधन परिनियोजन और योजना, तत्काल कार्यों और परियोजना में किसी भी बाधा पर संचालन समिति को अपडेट करना था। परियोजना के विकास और कार्यान्वयन चरण के दौरान, संचालन समिति की बैठकें अर्धमासिक तौर पर आयोजित की जानी थीं। संचालन और रखरखाव चरण के दौरान, बैठकें महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संचालन समिति का गठन किया गया था, लेकिन इसकी संरचना और इसके कार्यकाज का विवरण लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह समिति कार्य करती है, जैसा कि आरएफपी में परिकल्पित है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को जारी किया गया था (अप्रैल 2022) और मंत्रालय ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कहा (सितंबर 2022) कि सभी उपलब्ध कार्यालय अभिलेख लेखापरीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। पीएमओ कार्य कर रहा है और परियोजना की शुरुआत से ही साप्ताहिक/आवधिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और इन्हें फिर से लेखापरीक्षा के साथ साझा करने के लिए भी कहा; हालाँकि, उक्त की प्रतीक्षा की जा रही थी (दिसंबर 2022)।

**सिफारिश 2: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएमओ और संचालन समिति परिकल्पित रूप से कार्य कर रहे हैं, ताकि परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जा सके।**

### 2.5.3 सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) में कमियाँ

एसआरएस सभी मॉड्यूल के लिए तैयार किए गए थे, जिसने मॉड्यूल के विकास के लिए आधार तैयार किया था। लेखापरीक्षा ने अधिनियम/नियमों

की तुलना में सभी मॉड्यूलों के एसआरएस की नमूना जांच की ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि एसआरएस तैयार करते समय सभी प्रावधानों पर विचार किया गया था या नहीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित कमियों के अतिरिक्त अधिकांश प्रावधानों को एसआरएस में संबोधित किया गया है:

**तालिका 2.3 - एसआरएस में कमियों का मॉड्यूल वार विवरण**

मॉड्यूल का नाम	सत्यापन प्रावधान एसआरएस में शामिल नहीं हैं	संदर्भ
निरीक्षण	नोटिस जारी होने के तीस दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों/बहियों या वस्तुओं को वापस करने की शर्त को सत्यापित करना	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 67 (3)
	यदि तलाशी के उपरांत कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है तो माल की वापसी का विवरण कैप्चर करना	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 67 (7)
	अधिनियम में उल्लिखित माल की वापसी के लिए समय सीमा और समय सीमा का विस्तार सुनिश्चित करना	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 67 (7)
पंजीकरण	फाइल किए गए रिटर्न से कुल कारोबार की गणना करने के लिए सत्यापन का अभाव	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 14/2019-केन्द्रीय कर दिनांक: 07.03.2019
	रिटर्न फाइल न करने के लिए एससीएन को उत्तर देने के बजाय करदाता द्वारा सभी लंबित रिटर्न फाइल किए जाने और निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण भुगतान किए जाने पर कर अधिकारी को सतर्क(अलर्ट) करने के लिए एसआरएस में प्रावधान का अभाव।	सीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 22 (1), नियम 22 (4) का परंतुक
	एसआरएस में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान का अभाव कि माने गए अनुमोदित पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित किए गए हैं।	सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 10 (5) के साथ पठित नियम 9 (5)
	हस्तांतरण, उत्तराधिकार, डिमर्जर, समामेलन के परिणामस्वरूप प्राप्त पंजीकरण के संबंध में दायित्व की प्रभावी तिथि का पता लगाने के लिए वैधीकरण का अभाव।	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 (3), 22 (4)
	पंजीकृत करदाताओं को कर योग्य आपूर्ति करने और क्रेडिट को आगे पारित होने से प्रतिबंधित करने के लिए निलंबन कार्यात्मकता और वैधीकरण का अभाव।	सीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 21 (ए) (आई)

यह देखते हुए कि इन आवश्यकताओं को कानून में निर्धारित किया गया है, कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में निर्मित एक वैधीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता है।

**सिफारिश 3: विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं में निर्धारित सभी प्रावधानों, जिनमें अलग-अलग समय पर शुरू किए गए परिवर्तन शामिल हैं, को कार्यात्मकताओं के विकास के लिए एसआरएस में सटीक रूप से दर्शाया और अद्यतित किया जाए।**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (सितंबर 2021), मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और कहा (अगस्त 2022) कि दोनों मॉड्यूल में सुझाई गई कार्यात्मकताएं विकसित की जाएंगी।

#### 2.5.4 परियोजना संगमील

आरएफपी (खंड 9.1) के अनुसार, परियोजना के संगमील को परियोजना प्रारंभ तिथि (जिसे "टी" <sup>7</sup> कहा जाता है) से मापा जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह निर्धारण करने के लिए कि क्या परियोजना को सहमत योजना और समयसीमा के अनुसार विकसित और कार्यान्वित किया गया था, सीबीआईसी को प्रत्येक मॉड्यूल के विकास और कार्यान्वयन के लिए नियोजित तिथि और वास्तविक तिथि इंगित करने के लिए कहा गया था। उत्तर में, विभाग ने पंजीकरण, रिटर्न, एसीएल, एसीईएस जीएसटी माइग्रेशन, प्रतिदाय मॉड्यूल के संबंध में जानकारी प्रदान की। शेष मॉड्यूल के लिए, विभाग ने कहा कि डीएसआर (अधिनिर्णय, वसूली और अपील), जांच मॉड्यूल परिवर्तन अनुरोधों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। मोबाइल ऐप और लेखापरीक्षा मॉड्यूल, एसआरएस साइनऑफ चरण में थे जैसा कि बाद के पैरा में चर्चा की गई है। इसके अलावा, करदाता- एक नज़र में (टीएजी) और निर्यात मॉड्यूल चर्चा के चरण में थे।

---

<sup>7</sup> कार्य प्रदान करने के स्वीकृति पत्र की प्राप्ति की तिथि या सीबीआईसी द्वारा कार्य पत्र जारी करने के सात (7) दिनों के रूप में परिभाषित किया गया है।

### 2.5.4.1 मॉड्यूल का विकास और उपयोग

करार के पांच वर्षों (सितंबर 2021) के बाद सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के मॉड्यूल की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 2.4 - मॉड्यूल के विकास की स्थिति

मॉड्यूल का नाम	क्रियान्वित की गई कार्यात्मकताएं	कार्यात्मकताएं जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है
पंजीकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>करदाताओं के पंजीकरण प्रपत्र और सहायक दस्तावेज़ देखें</li> <li>अधिक जानकारी के लिए पंजीकरण अनुमोदित/पूछताछ/अस्वीकृत करें</li> <li>पंजीकरण में संशोधन</li> <li>पंजीकरण का समर्पण</li> <li>पंजीकरण निरस्त करना</li> <li>पंजीकरण रद्द करना</li> <li>आधार लिंकिंग और भौतिक सत्यापन</li> <li>क्षेत्राधिकार आवंटन लॉजिक (टीसीएस और यूआईएन)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>संबद्ध जोखिम (पैन धारक के प्रति दर्ज मामलों की संख्या के आधार पर)</li> <li>निलंबन कार्यात्मकता</li> <li>संयोजन प्रपत्र और संयोजन वैधीकरण</li> </ul>
रिटर्न्स	<ul style="list-style-type: none"> <li>डाउनलोड करने योग्य विकल्प के साथ सभी प्रपत्र देखें</li> <li>संक्रमणकालीन प्रावधान - गैर फाइलर्स के लिए कार्यात्मकता (आंशिक रूप से परिनिर्णयित)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन</li> <li>रिटर्न्स की संवीक्षा</li> <li>एसएमटी- 01 से एसएमटी- 18 से संबंधित प्रपत्रों के लिए सारांश निर्धारण</li> <li>जीएसटीआर- 4 वार्षिक रिटर्न्स</li> <li>आईटीसी- 02 ए</li> </ul>
भुगतान	<ul style="list-style-type: none"> <li>भुगतान रसीद</li> <li>पावती सृजन (पीएमटी- 01)</li> <li>लेज़र देखें (आईटीसी और देयता रजिस्टर) - जीएसटीएन के साथ सिंक करें</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>लेखा प्राधिकारियों से मिलान किये हुए डेटा का संचरण</li> <li>भुगतान विवरण का सत्यापन</li> <li>सिक्रनाइज़ेशन रिपोर्ट</li> <li>अन्य मॉड्यूल के साथ डेटा का एकीकरण</li> </ul>
एसीईएस माइग्रेशन	लागू नहीं है	
निर्यात	निर्यात मॉड्यूल चर्चा के चरण में था और अभी तक विकसित नहीं किया गया था। मॉड्यूल, मसौदा एसआरएस चरण में था।	
करदाता नज़र में	केवल चर्चा का चरण। विक्रेता से मसौदा एसआरएस प्रतीक्षित था	
प्रतिदाय	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिदाय एप्लीकेशन</li> <li>पावती</li> <li>कमी ज़ापन</li> <li>अस्थायी प्रतिदाय आदेश</li> <li>भुगतान आदेश</li> <li>प्रतिदाय स्वीकृति आदेश</li> <li>दायित्व का पूर्ण और आंशिक समायोजन</li> <li>अस्वीकृति के लिए नोटिस (एससीएन)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>यूआईएन प्रतिदाय के लिए आरएफडी- 10 एप्लीकेशन</li> <li>प्रतिदाय को रोकने और जारी करने के लिए आरएफडी- 7 (भाग-बी) आदेश</li> <li>आरएफडी- 01 सी - आरएफडी- 01 बी में की गई गलती का सुधार</li> </ul>

मॉड्यूल का नाम	क्रियान्वित की गई कार्यात्मकताएं	कार्यात्मकताएं जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है
	<ul style="list-style-type: none"> <li>एससीएन देखें विकल्प का उत्तर</li> <li>एलयूटी (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सीडब्ल्यूएफ को भुगतान</li> <li>आरएफडी 10 ए सीएसडी</li> <li>आरएफडी- 10 बी ड्यूटी फ्री शॉप</li> </ul>
जांच	<ul style="list-style-type: none"> <li>पहला चरण पूरा- सभी जांच गतिविधियाँ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पहले चरण की जांच के बाद की गतिविधियाँ</li> <li>चरण II - कंपाउंडिंग, अवरोधन, पारगमन में माल का अभियोजन</li> </ul>
अधिनिर्णयन	<ul style="list-style-type: none"> <li>पहला चरण- प्रतिदाय और अपवंचन-रोधी, अधिनिर्णय प्रक्रिया के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करना</li> <li>ओआईओ जारी करना (फॉर्म डीआरसी 01 और 3 से 8)</li> <li>व्यक्तिगत सुनवाई तय करने और कॉल बुक से मामलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीआरसी<sup>8</sup> -02</li> <li>एससीएन जारी करना</li> <li>सारांश निर्धारण</li> <li>रिटर्न की संवीक्षा</li> <li>लेखापरीक्षा और विशेष लेखापरीक्षा</li> </ul>
अपील, समीक्षा और संशोधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>चरण I कार्यात्मकताएं (एपीएल<sup>9</sup> प्रपत्र 1 से 4 तक)</li> <li>अधिनिर्णय आदेशों की समीक्षा</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>चरण II कार्यात्मकता - 21 उपयोग के मामले</li> <li>रिमांड आदेश (प्रपत्र एपीएल 5 से 8, आरवीएन 01)</li> </ul>
वसूली	<ul style="list-style-type: none"> <li>विरासत बकाया की वसूली</li> <li>किशतों में भुगतान (प्रपत्र डीआरसी 7 ए, 8 ए, 20,21)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अन्य स्रोतों से निकलने वाली वसूली प्रक्रिया (डीआरसी प्रपत्र 9 से 19, 22 से 25)</li> <li>वसूली रजिस्टर</li> </ul>
ई-वे बिल-अनब्लॉकिंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>पूरी तरह से कार्यान्वित</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>शून्य</li> </ul>
लेखापरीक्षा	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसआरएस साइन ऑफ किया</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>संपूर्ण मॉड्यूल का विकास</li> </ul>
मोबाइल एप्लीकेशन	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसआरएस - चरण I पर साइन ऑफ किया</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसआरएस - चरण II और संपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन का विकास</li> </ul>

ई-वे बिल की अनब्लॉकिंग कार्यात्मकता के अलावा, जिसे पूरी तरह से विकसित किया गया था, पंजीकरण, भुगतान, प्रतिदाय, जांच, अधिनिर्णयन, अपील, समीक्षा और संशोधन प्रक्रियाओं के लिए मॉड्यूल काफी हद तक पूरे हो गए थे और स्वतंत्र रूप से कार्यात्मक थे, हालांकि, कुछ कार्यात्मकताएं अभी तक विकसित नहीं की गई थीं। वसूली मॉड्यूल केवल आंशिक रूप से पूर्ण किया गया था। महत्वपूर्ण वसूली रजिस्टर अभी तक विकसित नहीं

<sup>8</sup> मांग और वसूली प्रपत्र

<sup>9</sup> अपील प्रपत्र

किया गया था और विकास के वर्तमान चरण में अंतर्निहित कार्य प्रवाह प्रक्रियाओं के केवल दो खंड शामिल थे। निर्यात, करदाता-एक नज़र में और मोबाइल एप्लीकेशन मॉड्यूल का विकास प्रारंभिक चरण में था।

इस पृष्ठभूमि में, क्षेत्र संरचनाओं द्वारा मॉड्यूल के उपयोग की हमारी समीक्षा में यह पाया गया कि अधिनिर्णय, जांच, अपील के लिए मॉड्यूल के कार्यात्मक भाग का उपयोग केवल बहुत सीमित सीमा तक किया जा रहा था।

(i) जहां तक अधिनिर्णयन मॉड्यूल का संबंध है, बेंगलुरु जोन के लिए 2020-21 के लिए एमआईएस रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि एससीएन के प्रति भुगतान जीएसटी फ्रंट-एंड से किया गया था और फॉर्म डीआरसी -03 (करदाता द्वारा किए गए भुगतान की सूचना) 2020-21 के दौरान 29,527 मामलों में फाइल किया गया था, सिस्टम के माध्यम से किसी भी मामले को संसाधित नहीं किया गया था। एमआईएस रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि डीआरसी-05 (कार्यवाही के समापन की सूचना) या डीआरसी-07 (आदेशों का सारांश) को किसी भी मामले के लिए जारी नहीं किया गया था। जहां करदाताओं ने डीआरसी-03 का उपयोग करके स्वेच्छा से भुगतान किया था, वहाँ भुगतान की स्वीकृति की पावती केवल 53 मामलों में फॉर्म डीआरसी-04 में जारी की गई थी। इसी तरह, अखिल भारतीय आधार पर, एक महीने (जुलाई 2021) के लिए एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि डीआरसी -07 जारी करके सिस्टम के माध्यम से केवल 44 मामलों को संसाधित किया गया है और अब तक केवल 3,029 मामलों को संचयी रूप से संसाधित किया गया है।

(ii) जांच मॉड्यूल का भी उपयोग नहीं किया जा रहा था। एक आयुक्तालय (बेंगलुरु पूर्व) के दौरे करने पर संकेत मिला कि सिस्टम के माध्यम से किसी भी मामले को संसाधित नहीं किया गया था। जांच मामलों के लिए रजिस्टर (335 जे) का मैनुअल रूप से रखरखाव किया गया था। एक समीक्षा से संकेत मिला है कि मामलों

को मुख्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से संसाधित किया जा रहा था।

- (iii) अपील रजिस्टर (जिसे अभी तक विकसित नहीं किया गया था) की अनुपस्थिति में, अपील मॉड्यूल के उपयोग की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सका। बेंगलुरु-1 अपील आयुक्तालय में लेखापरीक्षा ने पाया कि दो रैंजों की अपील संग्रह सूची में कोई मामला नहीं था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (सितंबर 2021) के उत्तर में, विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि विभिन्न आउटरीच उपाय शुरू किए गए थे, जिसमें सीबीआईसी अधिकारियों को भेजे जाने वाले विभिन्न संचार, ऑनलाइन प्रशिक्षण और परिचय कार्यक्रम, आयुक्त स्तर पर कार्यशाला आयोजित करना और निर्देश कि ई-ऑफिस का उपयोग करना सीबीआईएस जीएसटी एप्लीकेशन का प्रतिस्थापन नहीं था, शामिल थे। इसमें यह भी कहा गया है कि आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम न केवल नियमित आधार पर बल्कि आवश्यकता के आधार पर भी आयोजित किए गए थे। हालांकि, उपयोग की कमी के मामलों को सख्ती से अनुसरण किया जा रहा था।

#### 2.5.4.2 मोबाइल एप्लीकेशन मॉड्यूल के विकास में विलंब

एमएसए के अनुसार, विक्रेता को एंड्रॉइड, आईओएस और विंडोज प्लेटफार्मों के लिए एक हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करना था, जो सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के चरण -1 विकास के हिस्से के रूप में टैबलेट और स्मार्टफोन पर सुलभ हो। इसे प्लेटफॉर्म स्वतंत्र होने और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया जाना था। मोबाइल एप्लीकेशन को एकत्र किए गए राजस्व, फाइल रिटर्न आदि पर विशिष्ट रिपोर्टों के अलावा भौतिक सत्यापन (पीवी) आदि की पूर्णता पर अपनी रिपोर्ट बनाने और ऑनलाइन अपलोड करने के लिए फील्ड/साइट दौरे पर अधिकारियों तक विस्तारित किया जाना था। वेब एप्लीकेशन में उपलब्ध सभी 14 एमआईएस रिपोर्टों पर मोबाइल एप्लीकेशन विकास के लिए विचार किया जाना था।

प्रस्तुतिकरण में मोबाइल ऐप की परिनियोजन के लिए एमएसए में परिकल्पित सांकेतिक समय सीमा 31 मई 2017 थी। हालांकि, जनवरी 2019 तक मोबाइल ऐप के विकास पर कोई प्रगति नहीं हुई थी, जब सीबीआईसी के 13 अधिकारियों के एक कार्यकारी समूह का गठन व्यावसायिक आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करने और अंतिम रूप देने के लिए किया गया था। प्रारंभ में, मोबाइल उपकरणों का सीबीआईसी द्वारा अपने सभी 24,612 अधिकारियों के लिए प्रावधान करने का इरादा था, लेकिन बाद में, मार्च/अप्रैल 2019 के दौरान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकता चर्चाओं के आधार पर, मई 2019 के दौरान, अपने स्वयं के डिवाइस लाने (बीवाईओडी) की अवधारणा को अपनाने का निर्णय लिया गया था।

विक्रेता ने चरण-I के लिए संशोधित एसआरएस साइन-ऑफ तिथि 30 सितंबर 2019 और गो-लाइव तिथि 30 नवंबर 2019 के साथ दो चरणों में मोबाइल एप्लीकेशन की डिलीवरी के लिए प्रतिबद्धता जताई (11 सितंबर 2019)। चरण-I में एमआईएस रिपोर्टों के साथ-साथ कुछ मॉड्यूल और कार्यात्मकताओं को शामिल करने की परिकल्पना की गई थी, जबकि शेष की परिकल्पना चरण-II के लिए की गई थी। हालांकि, पुनरावृत्तियों के बाद, विक्रेता ने फ़ील्ड साइट दौरा (एफएसवी) डैशबोर्ड और प्रोटोटाइप के बिना एसआरएस संस्करण 2.0 साझा किया (14 जनवरी 2020), जिसे अलग से प्रस्तुत और पुनरीक्षित किया जाना था। सीबीआईसी ने 16 जनवरी 2020 को यूआई स्क्रीन (मेसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन में एमआईएस रिपोर्ट विकसित करने की लंबित तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट) के बिना एसआरएस संस्करण 2.0 पर आंशिक रूप से साइन आफ किया और सभी रिपोर्टों और यूआई स्क्रीन के साथ एसआरएस- चरण-I के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2021)।

कार्यकारी समूह की बैठकों और सुझावों (जून-जुलाई 2020) के आधार पर, मोबाइल एप्लीकेशन के चरण-II के संबंध में दिसंबर 2020 में व्यवसाय आवश्यकता दस्तावेज़ (बीआरडी) को अंतिम रूप दिया गया था और बीआरडी को अंतिम रूप देने से परे कोई आगामी प्रगति नहीं हुई है। सीबीआईसी ने

मोबाइल एप्लीकेशन के दो चरणों की प्रगति की स्थिति की समीक्षा की (नवंबर - दिसंबर 2020) और पहचान की गई बाधाओं के आधार पर, आगे के विकास को तब तक रोकने का फैसला किया जब तक कि विक्रेता अतिरिक्त विकास संसाधनों को परिनियोजित नहीं करता है और एमआईएस रिपोर्ट (डेटा की मात्रा, ग्राफिकल प्रतिनिधित्व और हाइपरलिंक के संदर्भ में) विकसित करने की तकनीकी व्यवहार्यता पर उत्तर नहीं देता है।

इसलिए, एक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से, पर्याप्त मात्रा में समय और प्रयास किए जाने के बावजूद, मोबाइल एप्लीकेशन के पहले चरण के विकास के लिए केवल एसआरएस को साइन ऑफ किया गया था और अभी भी प्रारंभिक स्क्रीन ही प्रदर्शित की जा रही थी। सीबीआईसी-जीएसटी एप्लीकेशन के पहले चरण के रूप में परिकल्पित मोबाइल एप्लीकेशन के विकास को पहले ही तीन वर्ष से अधिक समय की देरी का सामना करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त, परिकल्पित तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन के विकास की संभावना नहीं लगती है, यह देखते हुए कि आगे के विकास को रोक दिया गया था क्योंकि एमआईएस कार्यात्मकताओं की तकनीकी व्यवहार्यता अभी तक स्थापित नहीं की गई थी और विक्रेता तकनीकी संसाधन प्रदान करने में असमर्थ था।

इसके विषय में बताए जाने पर (सितंबर 2021), मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि मोबाइल एप्लीकेशन के विकास और परिनियोजन में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

#### **2.5.4.3 लेखापरीक्षा मॉड्यूल के विकास में विलंब**

एमएसए के अनुसार, विक्रेता को मई 2017 तक सीबीआईसी की लेखापरीक्षा संरचनाओं द्वारा उपयोग के लिए एक लेखापरीक्षा मॉड्यूल शुरू करना था। लेखापरीक्षा मॉड्यूल के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की पहचान की गई थी, उनमें लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का वार्षिक चयन, लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर का निर्माण, त्रैमासिक लेखापरीक्षा अनुसूची और आवंटन, प्रारंभिक/डेस्क समीक्षा, डेटा विश्लेषण, आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन, सत्यापन रिपोर्ट, बाद का सत्यापन और मसौदा लेखापरीक्षा और अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना महत्वपूर्ण था। डीजी (सिस्टम्स) ने पहचान की कि

तकनीकी/ सिस्टम बाधा के कारण व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सिस्टम डिजाइन और कार्यान्वयन में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण कठिनाई व्याप्त थी। एसआरएस की तैयारी मई 2017 में शुरू हुई और इसमें कई संशोधन किए गए। विभाग ने आरएफपी के संदर्भ में लेखापरीक्षा मॉड्यूल के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने और एसआरएस में कमियों के लिए विक्रेता के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया था।

अंत में, डीजी (सिस्टम्स) ने जनवरी 2020 में लेखापरीक्षा एसआरएस को साइन ऑफ किया। हालांकि, विक्रेता ने कहा कि साइन ऑफ एसआरएस में शामिल निम्नलिखित कार्यात्मकताओं को आरएफपी में शामिल नहीं किया गया था और इन्हें 'कार्य क्षेत्र से बाहर' i) एडीटी -03 जारी करना ii) एडीटी -04 जारी करना iii) लेखापरीक्षा रजिस्टर iv) प्रसारण (बुलेटिन बोर्ड) v) डेस्क समीक्षा विश्लेषण, माना जाएगा। विचार-विमर्श के बाद, यह सहमति बनी कि ब्रॉडकास्ट (बुलेटिन बोर्ड) को छोड़कर, अन्य सभी मुद्दे कार्यक्षेत्र का हिस्सा थे।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा मॉड्यूल के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने और सहमत होने में देरी, एसआरएस में शामिल करने के लिए लेखापरीक्षा फॉर्म/प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में देरी के साथ-साथ जीएसटी लेखापरीक्षा मैनुअल (जो जुलाई 2019 में अस्तित्व में आया) को अंतिम रूप देने में देरी ने एसआरएस साइनऑफ में देरी में काफी हद तक योगदान दिया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (सितंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि लेखापरीक्षा मॉड्यूल 1 अप्रैल 2022 को शुरू कर दिया गया था।

मॉड्यूल के कार्यान्वयन की समीक्षा बाद की लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

**सिफारिश 4: विभाग को आईटी शासन और प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना की समयसीमा का पालन किया जा रहा है और शुरू किए गए मॉड्यूल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है जैसी परिकल्पना की गई थी।**

### 2.5.5 भुगतान कार्यक्रम

आरएफपी (खंड 9.2) ने एप्लीकेशन विकास लागत के भुगतान, संचालन और रखरखाव लागत और हेल्पडेस्क लागत के भुगतान और संवर्द्धन लागत और प्रशिक्षण लागत के भुगतान के लिए संगमील वार भुगतान कार्यक्रम को परिभाषित किया। उपर्युक्त गतिविधियों के लिए परिभाषित संगमील प्राप्त किये जाने पर प्रत्येक गतिविधि के लिए भुगतान कुल लागत के प्रतिशत के रूप में किया जाना था। लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर, लेखापरीक्षा द्वारा संक्षेप में, विभिन्न मॉड्यूल के विकास के लिए विभिन्न भुगतान संगमील के प्रति किए गए भुगतान नीचे दिए गए हैं:

तालिका 2.5- प्रत्येक भुगतान संगमील के प्रति किए गए भुगतान का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	भुगतान संगमील	बिल की गई राशि (ए)	डीस्कॉप की गई राशि (बी)	दावा की गई राशि (सी)	लंबित राशि (डी)	परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (ई)	वास्तविक भुगतान { एफ = ए - (बी + सी + डी + ई) }
<b>पंजीकरण मॉड्यूल</b>							
1.	एसआरएस साइन ऑफ (10%)	34.22	0	0	0	0	34.22
2.	यूएटी परिनियोजन (20%)	68.44	0	0	0	0	68.44
3.	यूएटी साइन ऑफ (50%)	171.10	6.84	3.42	0	4.43	156.41
4.	प्रस्तुतिकरण परिनियोजन (10%)	34.22	1.36	0	0	0.06	32.80
5.	गो-लाइव (10%)	34.22	1.36	0	0	0	32.86
	<b>कुल</b>	<b>342.20</b>	<b>9.56</b>	<b>3.42</b>	<b>0</b>	<b>4.49</b>	<b>324.73</b>
<b>रिटर्न मॉड्यूल</b>							
1.	एसआरएस साइन ऑफ (10%)	68.44	20.53	0	0	0	47.91
2.	यूएटी परिनियोजन (20%)	136.88	83.95	0	2.96	0	49.97
3.	यूएटी साइन ऑफ (50%)	342.21	209.89	0	24.52	1.38	106.42

क्र. सं.	भुगतान संगमील	बिल की गई राशि (ए)	डीस्कॉप की गई राशि (बी)	दावा की गई राशि (सी)	लंबित राशि (डी)	परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (ई)	वास्तविक भुगतान { एफ = ए - (बी + सी + डी + ई) }
4.	प्रस्तुतिकरण परिनियोजन (10%)	68.44	41.97	0	5.58	0.006	20.88
5.	गो-लाइव (10%)	68.44	41.97	0	4.90	0	21.57
	<b>कुल</b>	<b>684.41</b>	<b>398.31</b>	<b>0</b>	<b>37.96</b>	<b>1.38</b>	<b>246.75</b>
<b>प्रतिदाय मॉड्यूल</b>							
1.	एसआरएस साइन ऑफ (10%)	17.11	0	0	0	0	17.11
2.	यूएटी परिनियोजन (20%)	34.22	1.71	0	1.71	3.42	27.38
3.	यूएटी साइन ऑफ (50%)	85.55	11.40	0	10.83	0.83	62.49
4.	प्रस्तुतिकरण परिनियोजन (10%)	17.11	2.21	0	2.23	0	12.67
5.	गो-लाइव (10%)	17.11	1.82	0	3.39	0	11.9
	<b>कुल</b>	<b>171.10</b>	<b>17.14</b>	<b>0</b>	<b>18.16</b>	<b>4.25</b>	<b>131.55</b>
<b>एसीएल मॉड्यूल</b>							
1.	एसआरएस साइन ऑफ (10%)	34.22	0	0	0	0	34.22
2.	यूएटी परिनियोजन (20%)	68.44	0	0	0	0	68.44
3.	यूएटी साइन ऑफ (50%)	171.10	0	0	0	9.41	161.69
4.	प्रस्तुतिकरण परिनियोजन (10%)	34.22	0	0	0	0	34.22
5.	गो-लाइव (10%)	34.22	0	0	0	0	34.22
	<b>कुल</b>	<b>342.20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.41</b>	<b>332.79</b>
<b>एसीईएस जीएसटी माइग्रेशन मॉड्यूल</b>							
1.	एसआरएस साइन ऑफ (10%)	34.22	0	0	0	1.67	32.55
2.	यूएटी	68.44	0	0	0	0.19	68.25

क्र. सं.	भुगतान संगमील	बिल की गई राशि (ए)	डीस्कॉप की गई राशि (बी)	दावा की गई राशि (सी)	लंबित राशि (डी)	परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (ई)	वास्तविक भुगतान { एफ = ए- (बी + सी + डी + ई) }
	परिनियोजन (20%)						
3.	यूएटी साइन ऑफ (50%)	171.10	0	0	8.55	0.98	161.57
4.	प्रस्तुतिकरण परिनियोजन (10%)	34.22	0	0	1.71	0.11	32.4
5.	गो-लाइव (10%)	34.22	0	0	13.68	0	20.54
	<b>कुल</b>	<b>342.20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.94</b>	<b>2.95</b>	<b>315.31</b>

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े (मार्च 2022 तक)

शेष माँड्यूल या तो परिवर्तन अनुरोधों के माध्यम से विकसित किए गए थे या नियोजन एसआरएस चरणों में थे।

विक्रेता को भुगतान की गई कुल राशि (मूल संविदा राशि के प्रति) आज की तिथि तक लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2022) के दौरान, मंत्रालय ने कहा कि समेकित व्यय और उसके बजट के लिए परियोजना बजट फाइलें डीजी (सिस्टम्स) दिल्ली में लेखापरीक्षा दल को प्रदान की गई थीं और यह भी कहा कि वे इसे फिर से लेखापरीक्षा के साथ साझा करेंगे; हालाँकि, उक्त की प्रतीक्षा की जा रही थी (दिसंबर 2022)।

## 2.6 निकास प्रबंधन योजना (ईएमपी)

तालिका 2.6 - सारांशित लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

क्र. सं.	उप-उद्देश्य	लेखापरीक्षा जांच का सारांश	स्थिति	निष्कर्ष
1.	क्या आरएफपी के अनुसार निकास प्रबंधन नीति/योजना स्थापित की गई है	करार की प्रभावी तिथि से 90 दिनों के भीतर निकास प्रबंधन योजना। हर छह (6) महीने में निकास प्रबंधन योजना का फिर से मसौदा तैयार किया और अद्यतित रखा।	परीक्षित	2.6.1

### 2.6.1 निकास प्रबंधन योजना को विक्रेता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया

आरएफपी के अनुसार, विक्रेता को परियोजना के विभिन्न चरणों के संबंध में करार की प्रभावी तिथि से 90 दिनों के भीतर क्रेता या उसकी नामित एजेंसियों को लिखित रूप में एक निकास प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी थी। निकास प्रबंधन योजना को अद्यतित रखने के लिए इसे हर छह महीने में फिर से तैयार करने की आवश्यकता थी। निकास प्रबंधन योजना के प्रत्येक संस्करण को क्रेता या उसकी नामित एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाना था। आरएफपी के अनुसार, करार को समाप्त किए जाने के मामले में, क्रेता से विक्रेता को समाप्ति आदेश जारी होने के बाद 6 महीने की अवधि के लिए परियोजना संचालन जारी रखने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखा और विक्रेता को क्रेता को बिना किसी अतिरिक्त लागत और व्यय के और सेवाओं की गुणवत्ता में किसी बाधा के बिना ऐसी अवधि के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विक्रेता ने कोई निकास प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं की थी जिसकी पुष्टि डीजी (सिस्टम्स) द्वारा भी की गई थी। निकास प्रबंधन योजना के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि आउटगोइंग विक्रेता, व्यवसाय की प्रभावी निरंतरता के लिए सुचारु रूप से सहयोग करेगा। डीजी (सिस्टम्स) ने विक्रेता द्वारा निकास प्रबंधन योजना प्रस्तुत न करने का कारण नहीं बताया था और करार के आवश्यक दायित्वों को पूरा न करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (अगस्त 2022) कि डीजी सिस्टम्स ने अब विक्रेता से एक निकास प्रबंधन योजना प्राप्त की है। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया कि वे लेखापरीक्षा के साथ योजना की एक प्रति साझा करेंगे (सितंबर 2022); हालाँकि, उक्त की प्रतीक्षा की जा रही थी (दिसंबर 2022)।

### 2.7 सेवा स्तर करार (एसएलए) और परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (एलडी)

सीबीआईसी एप्लीकेशन के लिए एसएलए को इस आधार पर डिजाइन किया गया था कि एप्लीकेशन विक्रेता, सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) दल को

प्रस्तुतिकरण वातावरण में परिनियोजित किए जाने वाली एप्लीकेशन का कोड प्रदान करेगा। एसआई,<sup>10</sup> प्रस्तुतिकरण वातावरण का एकमात्र मालिक था और डीसी/डीआर साइटों, डीसी/डीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैन और वैन सहित पूरे बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था।

सीबीआईसी समग्र समयसीमा, एसएलए की निगरानी और दंड/परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की गणना के लिए उत्तरदायी था। विक्रेता से समय सीमा के अनुसार और आरएफपी में उल्लिखित सेवा स्तरों के अनुसार करार के तहत कार्य के कार्यक्षेत्र को पूरा करने की उम्मीद की गई थी। यदि विक्रेता, विक्रेता के लिए उत्तरदायी कारणों के कारण समयसीमा या सेवा स्तर प्राप्त करने में विफल रहता है, तो विक्रेता आरएफपी में प्रदान की गई कैपिंग के प्रतिशत के अनुसार परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

**तालिका 2.7 - सारांशित लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स**

क्र. सं.	उप-उद्देश्य	लेखापरीक्षा जांच का सारांश	स्थिति	निष्कर्ष
1	एसएलए को ठीक से परिभाषित किया गया था	एसएलए मापदंड	आंशिक रिकॉर्ड प्रस्तुतीकरण	2.7
2	एसएलए की निगरानी कैसे की जाती है	प्रतिबद्ध एसएलए और अनुपालन स्तर से विचलन	आंशिक रिकॉर्ड प्रस्तुतीकरण	2.7.1.1 2.7.1.2 2.7.1.3 2.7.2 2.7.3
3	गैर-अनुपालन के मामले में जुर्माना (परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति) प्रावधान	परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति		
4	परियोजना प्रबंधन सलाहकार की भूमिका यदि कोई हो	बार-बार हो रही हैं घटनाएं	आंशिक रिकॉर्ड प्रस्तुतीकरण	-

सेवा स्तर करार (एसएलए) के अनुसार विक्रेता द्वारा निष्पादन आवश्यकताओं को तार्किक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया था:

- परियोजना कार्यान्वयन - ये एसएलए परियोजना की शुरुआत से गो-लाइव के चरण-II तक लागू थे। ये एसएलए यह सुनिश्चित करने के

<sup>10</sup> टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड और हेवलेट पैकर्ड का संघ

लिए थे कि परियोजना सहमत हुई समयसीमा और गुणवत्ता के अनुसार शुरू हो जाए

- संचालन और रखरखाव
- कॉल सेंटर (हेल्पडेस्क और तकनीकी सहायता)
- प्रशिक्षण
- सुरक्षा

पांच एसएलए से संबंधित कुल 32 मापदंडों की तुलना में, विभाग ने नीचे दी गई तालिका-2.8 में उल्लिखित केवल 14 मापदंडों के लिए एसएलए रिकॉर्ड प्रदान किए:

तालिका 2.8 - एसएलए मापदंड

क्र. सं.	एसएलए श्रेणी	एसएलए मापदंड	दस्तावेज़ प्रदान किए गए (हाँ /नहीं)
1	कार्यान्वयन चरण के लिए स्तर	(i) दल को जुटाना और कार्य शुरू करना	नहीं
		(ii) प्रमुख संसाधन परिनियोजन	नहीं
		(iii) प्रमुख संसाधन उपलब्धता	नहीं
		(iv) कार्यान्वयन/संवर्द्धन संगमिल की प्राप्ति में देरी	नहीं
		(v) डेटा माइग्रेशन	नहीं
		(vi) कार्यान्वयन/संवर्द्धन के दौरान उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण	नहीं
2	परिचालन और रखरखाव चरण के लिए सेवा स्तर	(i) उपलब्धता	नहीं
		(ii) प्रतिक्रिया समय	नहीं
		(iii) परिवर्तन अनुरोध/संवर्द्धन	हाँ
		(vi) संवर्द्धन दल उपलब्धता	नहीं
		(v) हैंडहोल्डिंग समर्थन	हाँ
3	हेल्प डेस्क और तकनीकी सहायता घटना/हेल्पडेस्क (एल 1)	(i) टेलीफोन लाइन की उपलब्धता	हाँ
		(ii) ऑनलाइन शिकायत प्रणाली की उपलब्धता	हाँ
		(iii) कॉल का प्रतीक्षा समय	हाँ
		(iv) कॉल परित्याग	हाँ
		(v) कॉल पर कुल होल्ड समय	हाँ
		(vi) टिकट पावती	हाँ
		(vii) फीडबैक के लिए अ्येषित कॉल	हाँ
		(viii) कॉल प्रतिक्रिया रेटिंग	हाँ
		(ix) समाधान के लिए संबंधित दल को टिकटों का कार्य	हाँ
		(x) टिकटों की तीव्रता निर्धारण का सही कार्य	हाँ

क्र. सं.	एसएलए श्रेणी	एसएलए मापदंड	दस्तावेज़ प्रदान किए गए (हाँ /नहीं)
		कार्य	
	हेल्प डेस्क और तकनीकी सहायता घटना / टिकट रिज़ॉल्यूशन (एल 2 और एल 3)	(i) हेल्पडेस्क टिकट/घटना प्रतिक्रिया समय	नहीं
		(ii) हल करने का समय	नहीं
		(iii) हल करने का समय	नहीं
		(iv) हल करने का समय	नहीं
		(v) फिर से खोले गए मामलों का प्रतिशत	नहीं
		(vi) मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) रिपोर्ट प्रस्तुत करना	नहीं
		(vii) केईडीबी का समय पर अद्यतन	नहीं
4	प्रशिक्षण	(i) सीबीआईसी के साथ सहमत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की समय पर डिलीवरी	हाँ
		(ii) प्रशिक्षण की गुणवत्ता	हाँ
5	सुरक्षा	(i) भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण	नहीं
		(II) भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण	नहीं

**सिफारिश 5: विभाग को लेखापरीक्षा हेतु सभी 32 एसएलए मापदंडों के लिए अभिलेखों को तुरंत प्रदान करना चाहिए।**

लेखापरीक्षा, अभिलेखों की कमी के कारण एसएलए के अनुपालन के संबंध में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा के लिए दिए गए सीमित एसएलए रिकॉर्ड की संवीक्षा के दौरान, निम्नलिखित अभ्युक्तियों को देखा गया:

### 2.7.1 परिचालन और रखरखाव चरण के लिए सेवा स्तर

प्रचालनात्मक और अनुरक्षण चरण के अंतर्गत पांच एसएलए मापदंडों में से लेखापरीक्षा को दो एसएलए मापदंडों- एप्लीकेशन का प्रतिक्रिया समय, परिवर्तन अनुरोध/संवर्द्धन और हैंडहोल्डिंग सहायता के संबंध में दस्तावेज प्रदान किए गए थे।

#### 2.7.1.1 सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन का प्रतिक्रिया समय लागू नहीं किया गया - न्यूनतम लक्ष्य प्रदर्शन स्तर की प्राप्ति न होना

आरएफपी (खंड-1 के उपनियम 10.5.1) के अनुसार, 95 प्रतिशत व्यावसायिक लेनदेन का प्रतिक्रिया समय डेटा सेंटर में 2 सेकंड की समयसीमा के भीतर होना चाहिए था। यदि एप्लीकेशन विक्रेता इस

समयसीमा का पालन करने में विफल रहता है, तो वह त्रैमासिक भुगतान के सहमत प्रतिशत पर परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अलावा, एसएलए के अनुसार, एसआई से वांछित प्रदर्शन स्तर प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन विक्रेताओं के साथ मिलकर कार्य करने की उम्मीद की गई थी अर्थात्, सभी व्यावसायिक लेनदेन के कम से कम 95 प्रतिशत के लिए एप्लीकेशन का प्रतिक्रिया समय 2 सेकंड से कम होना चाहिए। कार्यान्वयन के बाद एसएलए पर किसी भी उल्लंघन के मामले में, एसआई लागू शास्ति के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

प्रदान किए गए संरचनात्मक डेटा की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि इस एसएलए (सेवा की गुणवत्ता) से संबंधित डेटा को तिमाही (अप्रैल से जून 2020) के लिए प्रदान नहीं किया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एसएलए लागू नहीं किया गया था। एसएलए डेटा में तृतीय पक्ष के लेखापरीक्षक की टिप्पणियों से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई थी अर्थात् "एसएलए लागू नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन की बेसलाइनिंग लंबित है। एसआई दल ने कम प्रतिक्रिया समय के लिए ईमेल साझा किए हैं"। इसके अलावा, न्यूनतम लक्षित स्तरों की प्राप्ति न होने की स्थिति में, डीजी सिस्टम्स द्वारा परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति को लगाया जाना चाहिए, हालांकि, इसे एप्लीकेशन विक्रेता या एसआई विक्रेता के प्रति नहीं लगाया गया था।

उत्तर में, डीजी सिस्टम (अगस्त 2021) ने एसआई विक्रेता (टीसीएस, टीसीएल और एचपी का संघ) और एप्लीकेशन विक्रेता (मैसर्स विप्रो लिमिटेड) के बीच हुए पत्राचार की प्रतियां प्रदान कीं, जिसमें एसआई विक्रेता ने नियमित रूप से जीएसटी सेवा यूआरएल और आरएमएस एक्सेस लॉग यूआरएल के प्रतिक्रिया समय के बारे में एप्लीकेशन विक्रेता और सीबीआईसी को सूचित किया था, जहां यह 2 सेकंड की निर्धारित समयसीमा से अधिक था। डीजी सिस्टम ने आगे स्वीकार किया (अक्टूबर 2021) कि प्रक्रिया के अनुसार एसआई एप्लीकेशन की बेंचमार्किंग करने के लिए एप्लीकेशन दल को नियमित ईमेल भेज रहा था ताकि एसएलए को नियमित किया जा सके और डेटाबेस पर अतिरिक्त गतिविधियां भी की जा सकें ताकि यह सुनिश्चित

किया जा सके कि अंतर्निहित बुनियादी ढांचे के कारण एप्लीकेशन में कोई अभ्युक्ति न मिले।

यह स्पष्ट है कि विभाग ने विक्रेताओं के साथ एप्लीकेशन की बेसलाइनिंग का सक्रिय रूप से अनुसरण नहीं किया है और इस तरह के बेसलाइनिंग के बिना, प्रतिक्रिया समय से संबंधित सेवा स्तर को लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह के बेसलाइनिंग की अनुपस्थिति में, लक्षित निष्पादन स्तर (प्रतिक्रिया समय) प्राप्त करने में विफलता के लिए न तो एप्लीकेशन विक्रेता और न ही प्रणाली समेकक विक्रेता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

जब अभ्युक्ति (जुलाई 2022) को इंगित किया गया, मंत्रालय ने अभ्युक्ति (अगस्त 2022) को स्वीकार कर लिया।

**सिफारिश 6: विभाग को सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के एप्लीकेशन निष्पादन की बेसलाइनिंग के लिए जल्द से जल्द दोनों विक्रेताओं (एसआई और एप्लीकेशन विक्रेताओं) के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करना चाहिए।**

#### 2.7.1.2 परिवर्तन अनुरोध / संवर्द्धन

आरएफपी के अनुसार (आरएफपी (खंड 1) की धारा 8.4), सभी नियोजित परिवर्तनों को स्थापित परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया के तहत समन्वित किया जाना चाहिए जिससे आवश्यक परिवर्तन की उचित सूचना, प्राप्त अनुमोदन, अनुसूचियों का समायोजन आदि को सुनिश्चित किया जा सके। सॉफ्टवेयर में किसी भी बदलाव हेतु, विक्रेता को प्रस्तावित परिवर्तनों, कार्यात्मक परिणामों के संदर्भ में सिस्टम पर प्रभाव/सिस्टम में जोड़ी गई अतिरिक्त सुविधाओं आदि सहित विस्तृत दस्तावेज तैयार करना था। एक बार एक परिवर्तन अनुरोध के कार्यान्वयन हेतु एक समयसीमा पर सहमति हो जाने के बाद, नियोजित समय-सीमा से किसी भी देरी हेतु, जिसके लिए पूरी तरह से विक्रेता जिम्मेदार होंगे, को सेवा स्तर आरएफपी में उल्लिखित नियमों के तहत दंडित किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि एक एमनेस्टी योजना, सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान (एसवीएलडीआर) और ई-वे बिल मॉड्यूल के लिए एप्लीकेशन परिवर्तन अनुरोधों के रूप में विकसित किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन परिवर्तन अनुरोधों के विकास में विलंब (4 दिन से 60 दिन) हुआ और विभाग ने उचित एसएलए और एलडी लगाए।

### 2.7.1.3 हैंड होल्डिंग संसाधनों के लिए परिनियोजन योजना

आरएफपी (धारा 5.1.4 क्र.सं. 14) के अनुसार, विक्रेता को सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी सिस्टम एप्लीकेशन पर संसाधनों को प्रशिक्षित करने और विभाग के उपयोगकर्ताओं के लिए हैंड होल्डिंग समर्थन के रूप में कार्य करने के लिए देश भर में 79 स्थानों पर संसाधनों (111 हैंड होल्डर) को तैनात करने की आवश्यकता थी। सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी सिस्टम पर अपने दैनिक कार्यों में विभाग के उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता थी। हैंड होल्डिंग संसाधनों की उपस्थिति का प्रबंधन स्थानीय आयुक्तालयों द्वारा किया जाना था और सेवा स्तर समझौता भाग में संसाधनों की उपस्थिति के लिए लक्ष्य सेवा स्तरों को परिभाषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रमुख सेवा करार की अनुसूची-III (डिलीवरी शेड्यूल) के अनुसार, विक्रेता को 01 सितंबर 2016 तक या सीबीआईसी से सूचना के 15 दिन बाद, जो भी पहले हो, हैंड होल्डिंग संसाधन परिनियोजन योजना प्रस्तुत करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने विक्रेता द्वारा प्रस्तुत हैंड होल्डिंग संसाधन परिनियोजन योजना और हैंड होल्डिंग संसाधनों की वास्तविक तैनाती की मांग की (जुलाई 2021)। हालांकि, विभाग ने हैंड होल्डिंग संसाधन परिनियोजन योजना प्रदान नहीं की। इसके अभाव में लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या विक्रेता ने परिनियोजन योजना प्रस्तुत की थी और क्या प्रमुख सेवा करार की सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान की गई थीं। हालांकि, भुगतान फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि विक्रेता ने मई 2017 में सेवा शुरू की थी और अप्रैल 2018 तक हैंड होल्डिंग संसाधनों की तैनाती में लगातार कमी बनी हुई थी।

## 2.7.2 सहायता डेस्क के लिए एसएलए (एल 1)

आरएफपी (आरएफपी खण्ड 1 कि धारा 5.1.5) के अनुसार, सीबीआईसी को प्रदान की जाने वाली हेल्पडेस्क सेवाओं के लिए, विक्रेता को निम्नलिखित स्थापित करना आवश्यक था:

- विभागीय उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ डीलरों के प्रश्नों को हल करने हेतु एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर (एल 1 हेल्पडेस्क)
- एल1 हेल्पडेस्क द्वारा हल नहीं किए जा सके संबंधी पूछताछ के लिए समय पर समाधान प्रदान करने के लिए एक तकनीकी सहायता दल (एल2/ एल3 हेल्पडेस्क)

एल1 हेल्पडेस्क की स्थापना मौजूदा कॉल सेंटर के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य 24/7 घंटों सहायता प्रदान करना और विभागीय उपयोगकर्ताओं और विक्रेताओं दोनों को अपनी शिकायतें/सुझाव दर्ज करने में सक्षम बनाना था। एमएसए के अनुसार, एल1 हेल्पडेस्क सेवा के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के साथ एल1 हेल्पडेस्क सेवाओं के लिए 10 सेवा स्तर पैरामीटर हैं, जो एल1 हेल्पडेस्क सेवा के लिए विक्रेता को किए जाने वाले त्रैमासिक भुगतानों की कैपिंग का 20 प्रतिशत है। यदि परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति सीमा का लगातार दो तिमाहियों तक उल्लंघन किया गया, तो सीबीआईसी के पास अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार था।

दिसंबर 2016 से मार्च 2020 की अवधि के लिए हेल्पडेस्क सेवाओं से संबंधित भुगतान फाइलों की संवीक्षा के दौरान, निम्नलिखित प्रेक्षण दर्ज किये गए :

### (i) हेल्पडेस्क परिचालन योजना प्रस्तुत करने में विलंब

प्रमुख सेवा करार (डिलीवरी कार्यक्रम-III) दिनांक 12 अगस्त 2016 के अनुसार, विक्रेता को 15 सितंबर 2016 तक या सीबीआईसी से सूचना के 15 दिन बाद, जो भी पहले हो, हेल्पडेस्क परिचालन योजना प्रस्तुत करना आवश्यक था। इसे 01 सितंबर 2017 को एक वर्ष के विलंब से सीबीआईसी को प्रस्तुत किया गया।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2022) द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार कर लिया और कहा (अगस्त 2022) कि हेल्पडेस्क का परिचालन

संविदात्मक तिथि के अनुसार शुरू किया गया था और चूंकि संदर्भित अवधि बहुत गतिशील थी, इसलिए प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने के बाद विक्रेता ने परिचालन योजना प्रस्तुत की।

### (ii) एसएलए की अनुपलब्धि

सेवा स्तर समझौतों के अनुसार, एल1 हेल्पडेस्क सेवाओं के लिए 10 पैरामीटर हैं। दिसंबर 2016 से जून 2017 की अवधि के दौरान, विक्रेता ने केवल 5 सेवा स्तर मापदंडों के लिए हेल्पडेस्क सेवाएं प्रदान कीं। इसी तरह, जुलाई-सितंबर 2017 और अक्टूबर-दिसंबर 2017 की तिमाहियों के दौरान, विक्रेता ने क्रमशः आठ और नौ मापदंडों के लिए सेवाएं प्रदान कीं। इसलिए, यह स्पष्ट था कि विक्रेता दिसंबर 2016 में हेल्पडेस्क के लाइव होने के बाद से 12 महीने से अधिक समय तक हेल्पडेस्क सेवाओं के संबंध में निष्पादन के आवश्यक स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2022) द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार कर लिया और कहा (अगस्त 2022) कि सेवा स्तर प्रतिवेदन की पीजीए द्वारा जांच की गई थी और अनुबंध में अधिकतम 20 प्रतिशत एलडी प्रयोज्य था। इस प्रकार, बिलों को 20 प्रतिशत के अधिकतम लागू सेवा स्तर पर स्वीकृति दी गई थी। डीजी (सिस्टम्स) ने विक्रेता से अनुबंध प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए निरंतर प्रयास किए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप विक्रेता ने शेष एसएलए पैरामीटर डेटा को जल्द से जल्द संभव समय में प्रस्तुत किया।

### (iii) परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण

आरएफपी (धारा 10.2) के अनुसार, एल1 हेल्पडेस्क के लिए कॉल सेंटर सेवाओं के लिए समग्र परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (एलडी) त्रैमासिक भुगतान के 20 प्रतिशत तक सीमित होगी।

हेल्पडेस्क सेवा दिसंबर 2016 में लाइव हो गई; पहला बीजक 07 दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 तक की अवधि के लिए प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद, बाद की तिमाहियों के लिए बीजक प्रस्तुत किए गए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि सेवाओं के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त

नहीं करने और कुछ सेवाएं प्रदान नहीं करने के कारण, दिसंबर 2016 से सितंबर 2018 (22 महीने) की अवधि के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति 20 प्रतिशत से अधिक थी और 28.18 प्रतिशत से 645 प्रतिशत तक थी। हालांकि, तिमाही भुगतान के 20 प्रतिशत पर एलडी की कैपिंग के कारण, जुर्माना सीमित था।

आरएफपी (धारा 10.2) इंगित करता है कि यदि परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति सीमा का लगातार दो तिमाहियों तक उल्लंघन किया जाता है, तो सीबीआईसी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दिसंबर 2016 और सितंबर 2018 के बीच 22 महीनों के लिए, गणना की गई परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति 20 प्रतिशत से अधिक बनी रही।

इस ओर ध्यान एकत्रित किये जाने (जुलाई 2022) पर मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि उपरोक्त 22 महीने का समय कानून और बाद में एप्लीकेशन में बहुत सारे बदलावों से गुजारा। निरंतर बदलाव की ऐसी स्थिति में, यहां तक कि विक्रेता को बदलने से भी सेवा की गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता।

लेखापरीक्षा ने मंत्रालय के उत्तर को नोट किया।

#### **(iv) लक्षित घटना प्रबंधन निष्पादन में कमी**

आरएफपी (धारा 10.6.2) के अनुसार, उच्च गंभीरता वाली घटनाएं वे हैं जिनसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रभाव पड़ता है और उन्हें 30 मिनट के भीतर हल किया जाना चाहिए। औसत गंभीरता की घटनाएं वे हैं जिनका महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रभाव है और उन्हें 4 घंटे के भीतर हल किया जाना चाहिए, जबकि कम गंभीरता की घटनाएं वे हैं जिनका न्यूनतम व्यावसायिक प्रभाव होता है और हेल्पडेस्क टिकट का हेल्पडेस्क पर कॉल लॉग इन के समय से समस्या के समाधान/सुधार होने तक और समस्या निवारण 16 घंटे के भीतर हल किया जाना चाहिए। सभी उच्च और मध्यम गंभीरता वाली घटनाओं के लिए मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) तैयार किया जाना था और घटनाओं के समाधान की तिथि से 5 कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत किया जाना था और

समाधान तिथि के 5 दिनों के भीतर त्रुटि पहचान डेटाबेस (केईडीबी) को अपडेट किया जाना था।

प्रतिदाय शिकायतों के आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला है कि 2018 से 2021 (7 अगस्त तक) की अवधि के दौरान प्रतिदाय मॉड्यूल के तहत उच्च और मध्यम गंभीरता की 19,266 घटनाएं घटित हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

**तालिका 2.9 - वर्षवार प्रतिदाय घटना गंभीरता की स्थिति**

वर्ष	तीव्रता	घटित घटनाओं की कुल संख्या	विलंब की घटनाएं	निर्धारित समय सीमा में सुलझाई गई घटनाएं	विलंब सीमा	सक्रिय घटनाएँ
					(विलंब > 30 मिनट उच्च, विलंब > 4 घंटे औसत, विलंब > कम गंभीरता में 16 घंटे)	
2018	उच्च	9	8	1	16 घंटे 23 मिनट से 37 दिन 16 घंटे 52 मिनट तक	0
	औसत	191	186	5	04 घंटे 50 मिनट से 94 दिन 1 घंटे 19 मिनट तक	0
	कम	173	164	9	23 घंटे 53 मिनट से 64 दिन 15 घंटे 44 मिनट तक	0
	खाली	8	8	0	1 दिन 0 घंटे 54 मिनट से 113 दिन 15 घंटे 09 मिनट तक	0
2019	उच्च	1787	1780	7	01 घंटे से 99 दिन 02 घंटे तक। 53 मिनट	0
	औसत	341	336	5	4 घंटे 16 मिनट से 168 दिन 3 घंटे तक। 57 मिनट	0
	कम	1091	1061	30	16 घंटे 1 मिनट से 592 दिन 3 घंटे 26 मिनट तक	0
	खाली	10	9	1	22 घंटे 42 मिनट से 89 दिन 13 घंटे 7 मिनट तक	0

वर्ष	तीव्रता	घटित घटनाओं की कुल संख्या	विलंब की घटनाएं	निर्धारित समय सीमा में सुलझाई गई घटनाएं	विलंब सीमा	सक्रिय घटनाएँ
					(विलंब > 30 मिनट उच्च, विलंब > 4 घंटे औसत, विलंब > कम गंभीरता में 16 घंटे)	
2020	उच्च	5918	5903	15	31 मिनट से 249 दिन 11 घंटे 44 मिनट तक	2
	औसत	120	119	1	4 घंटे 15 मिनट से 100 दिन 22 घंटे 9 मिनट तक	1
	कम	1879	1786	93	16 घंटे 1 मिनट से 267 दिन 4 घंटे 39 मिनट तक	0
	खाली	16	16	0	19 घंटे 19 मिनट से 149 दिन 50 मिनट तक	1
2021	उच्च	7507	7492	15	31 मिनट से 138 दिन 19 घंटे 22 मिनट तक	800
	औसत	161	161	0	21 घंटे 24 मिनट से 98 दिन 1 घंटे 6 मिनट तक	4
	कम	41	38	3	19 घंटे 50 मिनट से 56 दिन 23 घंटे 32 मिनट तक	3
	खाली	14	14	0	2 दिन 20 घंटे 39 मिनट से 100 दिन 1 घंटे 8 मिनट तक	0
<b>कुल</b>		<b>19266</b>	<b>19081</b>	<b>185</b>		<b>811</b>

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए डेटा (जुलाई 2021 तक)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उच्च गंभीरता की 15,221 घटनाओं में से 15,183 (99.75 प्रतिशत) घटनाओं को 30 मिनट की निर्धारित सीमा के बाद हल किया गया था। 'औसत गंभीरता' की श्रेणी में, 813 घटनाओं में से 802 (98.64 प्रतिशत) को निर्धारित समय के बाद हल किया गया था। इसी तरह, 'कम गंभीरता' की श्रेणी में 3,184 घटनाओं में से 3,049 (95.76 प्रतिशत) को विलंब से हल किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया

कि 48 घटनाओं को किसी भी गंभीरता के तहत सौंपा नहीं गया था और शून्य रखा गया था।

इससे घटनाओं के प्रबंधन में समग्र विलंब और निर्धारित समय के भीतर उन्हें हल करने में असमर्थता का संकेत मिलता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (सितंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि विभाग ने जुलाई-सितंबर 2021 तक किए गए सभी त्रैमासिक भुगतानों में अधिकतम 20 प्रतिशत एलडी की कटौती की है।

*सिफारिश 7: विभाग को घटना श्रेणी के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर घटनाओं को हल करने के लिए विक्रेता की निगरानी करने की और निरंतर दबाव डालने की आवश्यकता है। चूंकि एलडी अधिकतम 20 प्रतिशत पर प्रतिबंधित है, इसलिए यह विक्रेता के लिए एक प्रभावी हतोत्साहन के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।*

### 2.7.3 प्रशिक्षण के लिए एसएलए

आरएफपी (धारा 5.1.4 क्रम संख्या 1) के अनुसार, विक्रेता को विभागीय उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी ताकि वे सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन सिस्टम का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित और निष्पादित कर सकें। सेवा स्तर के दो पैरामीटर हैं (i) बिना किसी विलंब के सीबीआईसी के साथ सहमत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की समय पर सुपुर्दगी और (ii) नोडल अधिकारी से प्राप्त फीडबैक के संदर्भ में 'प्रशिक्षण गुणवत्ता'। प्रशिक्षण से संबंधित समयसीमा प्राप्त नहीं करने के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (एलडी) को प्रशिक्षण लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया था, जिसकी प्रभावी तिथि से छह महीने बाद और ऐसे अंतरालों पर समीक्षा की जा सकती है जिसका निर्धारण सीबीआईसी द्वारा किया जा सकता है।

प्रमुख सेवा करार (एमएसए) के अनुसार, 200 बैचों (प्रत्येक दल में 25) के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त, डिलीवरी अनुसूची-III के अनुसार, विक्रेता को 30 सितंबर 2016 तक या सीबीआईसी से सूचना के 15 दिन बाद, जो भी पहले हो, प्रशिक्षण योजना

प्रस्तुत करनी थी और सीबीआईसी द्वारा प्रशिक्षण योजना को अनुमोदित किए जाने के बाद प्रशिक्षण सत्र शुरू करना था।

**(i) प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने के लिए एसएलए की अनुपलब्धि**

अभिलेख की संवीक्षा से पता चला कि जनवरी 2017 से सितंबर 2017 तक 164 बैचों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था और सितंबर 2021 तक 36 बैच प्रशिक्षण के लिए लंबित थे। उपर्युक्त अवधि के दौरान, विक्रेता का निष्पादन अपेक्षित स्तर के अनुसार नहीं था और परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति अधिकतम (20 प्रतिशत) कैपिंग सीमा तक लगाई गई थी, जबकि परियोजना अभिशासन और निगरानी एजेंसी (पीजीएमए) (मैसर्स पीडब्ल्यूसी) द्वारा की गई गणना 20 प्रतिशत कैपिंग से ऊपर और 27 प्रतिशत से 149 प्रतिशत तक थी। हालांकि, विक्रेता द्वारा निष्पादन स्तर कम होने के बावजूद विभाग केवल 20 प्रतिशत सीमित परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के रूप में लागू करने के लिए बाध्य था।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2022) द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि चालू समय में नई कर व्यवस्था लागू हुई थी। किसी भी नए विक्रेता को लंबी आरएफपी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता और अंततः उसे भी इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता। इसके अतिरिक्त, विभाग ने उपलब्ध विभागीय अधिकारियों से प्रमुख प्रशिक्षकों का एक समूह बनाने के लिए एक प्रयास भी किया, जिन्हें आगे के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे सीबीआईसी अधिकारियों द्वारा अधिक संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे और विक्रेता पर निर्भरता कम हो गई थी।

**(ii) एसएलए परिभाषाओं, लक्ष्य स्तरों और परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का गैर-संशोधन**

आरएफपी के अनुसार, सेवा स्तर समझौता परिभाषाओं, लक्ष्य स्तरों और परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की प्रभावी तिथि से छह महीने के बाद और ऐसे अंतरालों, जो क्रेता द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, पर समीक्षा की जानी

थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने इसकी समीक्षा और संशोधन नहीं किया।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2022) द्वारा इंगित किए जाने के बाद, मंत्रालय ने पैरा स्वीकार करते हुए (अगस्त 2022) कहा कि सीबीआईसी ने अब अनुबंध और सेवा स्तर समझौते की समीक्षा कर ली है। सक्षम प्राधिकारी ने तदनुसार आरएफपी हेतु एक परिशिष्ट को भी स्वीकृति दी थी।

**सिफारिश 8: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा स्तर समझौते के सभी पहलुओं के कार्यान्वयन की प्रभावी ढंग से निगरानी की जाए; विभाग और विक्रेता संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार अपनी-अपनी भूमिका निभाएं और गैर/विलंब से निष्पादन की प्रभावी ढंग से समीक्षा की जाए और सहमत समयसीमा के भीतर इसका समाधान किया जाए ।**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जुलाई 2022), मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और कहा (अगस्त 2022) कि विभाग ने जुलाई-सितंबर 2021 तक किए गए सभी त्रैमासिक भुगतानों में अधिकतम 20 प्रतिशत एलडी की कटौती की है।

## 2.8 परिवर्तन प्रबंधन

आईटी संगठनों में, एक संरचित परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का उपयोग आमतौर पर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और संबंधित प्रलेखन जैसे परिसंपत्तियों में परिवर्तनों को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन नियंत्रणों की आवश्यकता है कि सिस्टम कॉन्फिगरेशन में सभी परिवर्तन अधिकृत, परीक्षित, प्रलेखित और नियंत्रित हैं ताकि सिस्टम नियोजित तरीके से व्यवसाय परिचालन का समर्थन करना जारी रखे, और परिवर्तनों का पर्याप्त ट्रेल/अभिलेख हो।

**तालिका 2.10 - सारांशित लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स**

क्र.सं.	उप-उद्देश्य	लेखापरीक्षा जांच का सारांश	स्थिति	निष्कर्ष
1.	क्या आवश्यक परिवर्तन पर विक्रेता और सीबीआईसी के बीच उचित संचार हुआ है;	सीआर नीति, प्रवर्तन के लिए प्रक्रियाएं, परिवर्तन अनुरोध की समीक्षा और अनुमोदन, परिवर्तन नियंत्रण बोर्ड, लॉग और प्रतिवेदन की समीक्षा, आदेश परिवर्तन समयसीमा।	आंशिक रिकॉर्ड प्रस्तुतीकरण	2.8 2.8.1

2.	क्या विक्रेता को सीबीआईसी से समुचित अनुमोदन प्राप्त हुआ है;	परिवर्तन आदेश, पहले और बाद की परिवर्तन व्यवस्था और उपयोगकर्ता प्रलेखन।	सीमा प्रतिबन्ध	-
3.	क्या उत्पादन परिस्थिति पर प्रभाव को कम करने के लिए अनुसूची को समायोजित या फिर से प्राथमिकता दी गई है।	परिवर्तन क्रम के लिए दस्तावेजों का बैक-अप , आपातकालीन परिवर्तन।	सीमा प्रतिबन्ध	-

आरएफपी ने इन कार्यों के लिए उत्तरदायित्व के मानचित्रण के साथ-साथ परिवर्तन के लिए प्रवर्तन, समीक्षा और अनुमोदन की प्रक्रियाओं को विस्तृत किया है। आरएफपी (धारा 8.4) के अनुसार, विक्रेता को प्रस्तावित परिवर्तनों, कार्यात्मक परिणामों/प्रणाली में जोड़ी गई अतिरिक्त विशेषताओं आदि के संदर्भ में प्रणाली पर प्रभाव सहित विस्तृत प्रलेखन तैयार करना था। विक्रेता उत्पादन वातावरण में कार्यान्वयन से पहले सभी प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए सीबीआईसी से अनुमोदन प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रलेखन प्रत्येक तिमाही के परिचालन और रखरखाव सहायता के अंत में समीक्षा के अधीन है।

एक बार परिवर्तन अनुरोध के कार्यान्वयन के लिए एक समय सीमा पर सहमति हो जाने के बाद, नियोजित समयसीमा से किसी भी विलंब, जिसके लिए पूरी तरह से विक्रेता उत्तरदायी थे, को आरएफपी के सेवा स्तर समझौते में उल्लिखित के रूप में दंडित किया जाएगा। बड़े बदलाव के मामले में स्वीकृति परिचालन समिति की बैठकों में मांगी जाएगी।

लेखापरीक्षा में परिवर्तन नियंत्रण बोर्ड (सीएबी) की स्थापना, परिवर्तन नियंत्रण लॉग, किसी भी परिवर्तन अनुरोध को लागू करने से पहले बैक आउट प्रक्रिया का विकास, सिस्टम में आपातकालीन परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं को बदलना, परिवर्तन आदेश प्रलेखन आदि से संबंधित अभिलेख की मांग की गई थी। लेकिन विभाग ने मांगे गए अभिलेख के विरुद्ध दस्तावेज प्रदान नहीं किए और केवल प्रणाली में किए गए परिवर्तन अनुरोधों (सीआर) की सूची और इन सीआर पर किए गए व्यय की सूची प्रदान की, जो नीचे दिए गए हैं:

### 2.8.1 परिवर्तित अनुरोध / संवर्द्धन

विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि विभाग ने नीचे दी गई तालिका में विस्तृत विभिन्न मॉड्यूल के तहत 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹16.62 करोड़ के मूल्य के 173 परिवर्तन अनुरोधों को लागू किया।

तालिका 2.11 - परिवर्तन अनुरोध

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	मॉड्यूल का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		परिवर्तन अनुरोध की संख्या	परिवर्तन अनुरोध का मूल्य	परिवर्तन अनुरोध की संख्या	परिवर्तन अनुरोध का मूल्य	परिवर्तन अनुरोध की संख्या	परिवर्तन अनुरोध का मूल्य	परिवर्तन अनुरोध की संख्या	परिवर्तन अनुरोध का मूल्य
1.	पंजीकरण	7	31.18	1	10.47	12	155.36	7	94.55
2.	रिटर्न	10	47.02	15	81.44	19	377.67	9	55.38
3.	भुगतान	- (*)							
4.	प्रतिदाय	2	28.20	7	54.61	14	53.14	7	126.37
5.	डीएसआर (एडीजे+आरईसी+ए पीएल)	-	-	-	-	4	105.50	7	79.54
6.	जांच	-	-	-	-	3	46.70	1	4.65
7.	निर्यात (*)	- (*)							
8.	एसीईएस जीएसटी	- (*)	-	2	21.63	12	12.56	3	7.53
9.	मोबाइल एप	मोबाइल एप केवल एसआरएस साइन ऑफ स्टेज पर है।							
10.	लेखापरीक्षा	लेखापरीक्षा मॉड्यूल सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश साइन ऑफ स्टेज पर है।							
11.	करदाता एक नजर में (*)	- (*)							
12.	अभिगम नियंत्रण तर्क	- (*)							
13.	सामान्य परिवर्तन अनुरोध	16	3.44	-	-	1	7.87	-	-
14.	एसवीएलडीआरएस**	-	-	4	116.34	-	-	-	-
15.	ई-वे बिल	-	-	-	-	10	140.30	-	-
कुल		35	109.86	29	284.51	75	899.15	34	368.06

(\*)सीआर विवरण उपलब्ध नहीं है

(\*\*)एसवीएलडीआरएस एक नई आवश्यकता थी जिसे परिवर्तन अनुरोध के माध्यम से पूरा किया गया है।

## 2.9 आईटी सुरक्षा

आईटी सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा जैसी सूचना प्रौद्योगिकियों की अखंडता को हमले, क्षति या अनधिकृत पहुंच से बचाती है।

तालिका 2.12 - सारांशित लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

क्र.सं.	उप-उद्देश्य	लेखापरीक्षा जांच का सारांश	स्थिति	निष्कर्ष
1.	क्या आईटी सिस्टम की सुरक्षा को प्रभावी तरीके से डिजाइन किया गया है?	उपयोगकर्ता अभिगम प्रबंधन प्रक्रिया	जांचा हुआ	2.9.1.1
2.	व्यापार निरंतरता और आपदा बहाली	व्यापार प्रभाव विश्लेषण, जोखिम निर्धारण प्रतिवेदन, डेटा और कार्यक्रमों का बैकअप लेना, अनुपालन प्रतिवेदन को पैच करना, अनुसूचित डेटा प्रतिकृति, संसाधन आवश्यकताएं, आपदा बहाली (डीआर) ड्रिल योजना, संकट प्रबंधन दल, पुनर्प्राप्ति बिंदु उद्देश्य (आरपीओ) और पुनर्प्राप्ति समय उद्देश्य (आरटीओ)	जांचा हुआ	प्रणाली समेकक (सक्षम) परियोजना की आईटी लेखापरीक्षा में अलग से समाहित किया जाना है।

### 2.9.1 अभिगम नियंत्रण

एक्सेस कंट्रोल लॉजिक मॉड्यूल (एसीएल) यह निर्धारित करता है कि विशेषाधिकारों को विभिन्न उपयोगकर्ताओं को कैसे सौंपा जाना है ताकि व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्धारित रूप से उपयोग किया जा सके। एक आदर्श एक्सेस कंट्रोल लॉजिक को न केवल उचित अधिकारी को सही ढंग से विशेषाधिकार प्रदान करना चाहिए जैसा कि वांछित है, बल्कि भूमिकाओं को फिर से सौंपने, लंबित कार्यों को स्थानांतरित करने आदि के लिए आवश्यक लचीलापन भी प्रदान करना चाहिए।

अभिगम नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि केवल प्रक्रिया क्रेडेंशियल्स वाले उपयोगकर्ताओं के पास संवेदनशील डेटा तक पहुंच हो। व्यावसायिक जानकारी और डेटा तक पहुंच को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुंच को सीमित किया जा सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जानकारी या डेटा में किसी भी अनुचित पहुंच या अनधिकृत परिवर्तन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

### 2.9.1.1 उपयोगकर्ता अभिगम प्रबंधन (यूएम)

उपयोगकर्ता अभिगम प्रबंधन में नियंत्रित तरीके से नेटवर्क, एप्लीकेशन और नेटवर्क उपकरणों जैसे सीबीआईसी बुनियादी ढांचे के विभिन्न घटकों तक उपयोगकर्ता की पहुंच प्रदान करना, बनाए रखना और हटाना शामिल है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के पास एप्लीकेशन में अभिगम नियंत्रण के लिए एक स्पष्ट रूप से परिभाषित नीति/ढांचा है। एप्लीकेशन में एक्सेस आरएफपी और सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश पर आधारित है। एप्लीकेशन के भीतर, एक संरचना में उपयोगकर्ता की तैनाती के आधार पर संरचना के प्रशासक (एसीएल एडमिन) द्वारा पहुंच दी जाती है। उपयोगकर्ता पंजीकरण, उपयोगकर्ता संशोधन, मौजूदा उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी संशोधन, पदनाम संशोधन, पिछले स्थान में लंबित कार्यों के लिए पहुंच, अतिरिक्त शुल्क, अक्षम अनुरोध, सेवानिवृत्त उपयोगकर्ता आदि के लिए प्रक्रियाएं नीति ढांचे में स्पष्ट रूप से चिन्हित की गई हैं। प्रक्रिया की एक विस्तृत रूपरेखा नीचे उल्लिखित है:

**एसएसओ आईडी निर्माण** - नोडल अधिकारी एसएसओ आईडी निर्माण टेम्पलेट भरकर एसएसओ आईडी निर्माण अनुरोध शुरू करता है और उसे अपने आधिकारिक आइसगेट ईमेल आईडी / gov.in / nic.in आईडी से सक्षम सेवा को अग्रेषित करता है।

**यूएम दल सत्यापन** - अनुरोध प्राप्त करने पर, यूएम दल नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, आदि को सत्यापित करने के लिए अनुरोध चैनल, टेम्पलेट के सही और अनिवार्य फ़ील्ड और उपयोगकर्ता के प्रासंगिक दस्तावेजों को सत्यापित करती है।

**प्रतिलिपि की जांच** - यूएएम दल यह भी सत्यापित करती है कि उपयोगकर्ता के लिए प्रतिलिपि एसएसओ आईडी पहले से मौजूद है या नहीं। यदि कोई मौजूदा एसएसओ आईडी नहीं पाया जाता है, तो यूएएम दल एसएसओ आईडी के निर्माण के लिए आगे बढ़ती है।

**प्रतिलिपि जांच के बाद की प्रक्रिया** - यूएएम दल प्रतिलिपि जांच के प्रेक्षण के साथ अनुमोदन के लिए पीएमयू दल को ईमेल और बातचीत भेजती है। पीएमयू दल अनुरोध और सभी अनुलग्नकों को सत्यापित करती है। सत्यापन के बाद, पीएमयू दल अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुरोध को यूएएम डीओएस<sup>11</sup> को अग्रेषित करती है।

**निर्माता परीक्षक** - अनुरोध संसाधित करने वाले सहयोगी को निर्माता के रूप में नामित किया गया है और पूर्ण अनुरोध को सत्यापित करने वाले सहयोगी को परीक्षक के रूप में जाना जाता है। एसएसओ आईडी/ईमेल आईडी के निर्माण के बाद, परीक्षक सत्यापन जांच करता है।

सिस्टम में उपयोगकर्ता भूमिकाओं के संशोधन, सक्रियण और डी-एक्टिवेशन के मामले में एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

प्रस्तुतिकरण परिवेश में, लेखापरीक्षा ने पदनाम संशोधन, सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के एसएसओ आईडी को निष्क्रिय करने और विक्रेता के कर्मचारियों के एसएसओ आईडी को निष्क्रिय करने के एक-एक मामले की जांच की। इन तीन परीक्षण-जांच किए गए मामलों में, यह देखा गया कि उपयोगकर्ता अभिगम प्रबंधन के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन किया गया और कोई विचलन नहीं पाया गया था।

### 2.9.2 आईटी सेवा निरंतरता प्रबंधन योजना

सीबीआईसी ने अपने व्यावसायिक परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नवंबर 2019 को एक आईटी सेवा निरंतरता प्रबंधन (आईटीएससीएम) योजना (संस्करण 2.3) जारी की। आईटी सेवा निरंतरता योजना (आईटीएससीएम योजना) सीबीआईसी के किसी भी डेटा केंद्र में आपदा की स्थिति में व्यापार संतर्जकआपात स्थितियों, व्यवसाय निरंतरता

---

<sup>11</sup> सिस्टम निदेशालय

और अपने व्यावसायिक एप्लीकेशन की पूर्ण बहाली हेतु आकस्मिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है।

सीबीआईसी ने जुलाई 2020 में सूचना सुरक्षा नीति (संस्करण 2.3) जारी की, जो एक अनुपालन और प्रभावी सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने और बनाए रखने के लिए समग्र ढांचे को परिभाषित करती है।

लेखापरीक्षा के दौरान विभाग को सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में लागू सूचना सुरक्षा से संबंधित सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया था। उत्तर में, विभाग ने सूचना सुरक्षा नीति, बैकअप नीति आदि प्रदान की। इन दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि:

#### (i) सूचना सुरक्षा नीति

सूचना सुरक्षा नीति की संवीक्षा से पता चला कि आईटी विभाग में सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए भूमिकाओं और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। नीति दस्तावेज में, संचार माध्यम संचालन (संचार माध्यम के स्थानांतरण, संचार माध्यम के निपटान, भौतिक संचार माध्यम के हस्तांतरण का प्रबंधन) के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।

आईटी सुरक्षा नीति का पहला संस्करण जून 2009 में जारी किया गया था और अंतिम अद्यतन संस्करण जुलाई 2020 में जारी किया गया।

#### (ii) बैकअप नीति

बैकअप नीति दस्तावेज़ के अनुसार, डेटा को महत्वपूर्ण डेटा (कोर बिजनेस एप्लीकेशन और डेटा) और गैर महत्वपूर्ण डेटा (नॉन-कोर बिजनेस एप्लीकेशन और डेटा) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस डेटा को पूरी तरह से साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आधार पर बैकअप किए जाने के साथ-साथ मासिक और वार्षिक आधार पर डेटा प्रतिधारण किया जाना है। नेटवर्क उपकरणों का बैकअप साप्ताहिक आधार पर लिया जाना है और सर्वर/भौतिक टेप कार्टरिज के स्थानीय ड्राइव पर संग्रहीत किया जाना है। डेटा सेंटर कोर फ़ायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन बैकअप स्वयं प्रतिदिन पर लिया जाता है।

नेटवर्क डिवाइस लॉग का बैकअप आर्क साईट लॉगर सर्वर के माध्यम से लिया जाता है।

बैकअप नीति को समय-समय पर अद्यतन किया गया है। पहला संस्करण अगस्त 2009 में जारी किया गया था और नवीनतम अद्यतन संस्करण जुलाई 2020 में जारी किया गया।

आईएस सुरक्षा के उपर्युक्त पहलुओं की विस्तृत लेखापरीक्षा अलग से सिस्टम्स इंटीग्रेटर सक्षम प्रोजेक्ट की भविष्य में की जाने वाली लेखापरीक्षा के भाग में की जाएगी।

### अध्याय III: कार्यात्मकताओं का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में जीएसटी अधिनियमों/नियमों से प्रवाहित व्यावसायिक प्रक्रियाओं के मानचित्रण की जांच की और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या उन्हें सही ढंग से लागू किया गया था या नहीं। एप्लीकेशन में 11 मॉड्यूल परिकल्पित थे जो लेखापरीक्षा के समय विकास के विभिन्न चरणों पर थे। चार मॉड्यूल (एक्सपोर्ट, टैक्सपेयर एट ग्लांस, मोबाइल एप्लीकेशन और लेखापरीक्षा) विकास के प्रारंभिक चरण में थे और शेष सात मॉड्यूल विकसित किए जा चुके थे और प्रस्तुतीकरण वातावरण में रोल आउट हो चुके थे।

पंजीकरण मॉड्यूल में, अनुमोदन प्रक्रिया से संबंधित कार्यात्मकताओं के संबंध में सत्यापन और नए पंजीकरण/निलंबन/पंजीकरण रद्द करने की समय-सीमा के अनुपालन से संबंधित कतिपय कमियां पाई गई थीं।

रिटर्न मॉड्यूल में सीएमपी फॉर्म, जीएसटीआर -4 आदि जैसे फॉर्मों के कार्यान्वयन/परिनियोजन में विलंब के अतिरिक्त, रिटर्न की संवीक्षा और जोखिम निर्धारण इंजन, अनंतिम निर्धारण, सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण आदि जैसी कार्यात्मकताएं अभी विकसित की जा रही थीं।

प्रतिदाय मॉड्यूल में अधिसूचित व्यक्ति को प्रतिदाय की प्रोसेसिंग, अनंतिम प्रतिदाय ऑर्डर में बकाया मांग का समायोजन, बकाया मांग के समायोजन पर ब्याज की वसूली या प्रतिदाय को रोकने जैसी विभिन्न कार्यात्मकताओं को विकसित नहीं किया गया था।

विवाद निपटान और समाधान (डीएसआर) मॉड्यूल में, जबकि प्रतिदाय आदेश पर अपील मैनुअल रूप से दायर की जा रही थी, विवाद जीवनचक्र रजिस्टर और नियत तिथियों की निगरानी के लिए तंत्र अनुपस्थित थे।

यह भी देखा गया कि डिजिटल हस्ताक्षरों को किसी भी मॉड्यूल में शामिल और अपनाया नहीं गया है, मसौदा चरण में पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर फॉर्मर्स में किए गए व्यक्तिगत परिवर्तनों के लॉग दर्ज नहीं किए जा रहे थे और ब्याज की स्वचालित गणना के लिए कार्यात्मकता की अनुपस्थिति भी देखी गई थी।

### 3.1 पंजीकरण मॉड्यूल

कर अधिकारियों के साथ एक व्यवसाय के पंजीकरण का तात्पर्य संबंधित कर अधिकारियों से माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) प्राप्त करना है ताकि व्यवसाय से संबंधित सभी परिचालन और डेटा को समूहबद्ध तथा सहसम्बद्ध किया जा सके। यह कर उद्देश्यों के लिए या किसी भी अनुपालन सत्यापन कार्यक्रम के लिए व्यवसाय की पहचान के लिए मौलिक आवश्यकता है। जीएसटी व्यवस्था में, पंजीकरण पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है और पंजीकरण करने के इच्छुक किसी भी वैध व्यक्ति को माल एवं सेवा कर नेटवर्क पोर्टल का उपयोग करना होगा। आवेदक माल एवं सेवा कर नेटवर्क पोर्टल में नए करदाता पंजीकरण फॉर्म के सभी आवश्यक मद्दों को भरेगा और अनुमोदन के लिए जमा करेगा। माल एवं सेवा कर नेटवर्क पोर्टल में प्रस्तुत लेनदेन और अभिलेख को सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में सुचारू रूप से एकीकृत किया जाना है ताकि अभिलेख अधिकारियों के डैशबोर्ड पर पूरी तरह से और समय पर उपलब्ध हों।

तालिका 3.1 - सारांशित लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

उप उद्देश्य	परीक्षण किया गया / परीक्षण नहीं किया गया	सफल/असफल/सीमा प्रतिबंध	लेखापरीक्षा जांच का सारांश	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
यह जांचने के लिए कि राजस्व प्रभाव वाले परिचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सतर्कता (अलर्ट) /निगरानी कार्यविधि प्रभावी है या नहीं	परीक्षित (38)	सफल (10)	अनिवार्य पंजीकरण, अलग पंजीकरण (विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या डेवलपर), आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति से संबंधित प्रावधान, पंजीकरण की प्रभावी तिथि, पंजीकरण का स्थान और अवधि से संबंधित प्रावधान	-
		असफल (28)	डीमंड रजिस्ट्रेशन आधार प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन से संबंधित मुद्दों का परिचालन	3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4

उप उद्देश्य	परीक्षण किया गया / परीक्षण नहीं किया गया	सफल/असफल/सीमा प्रतिबंध	लेखापरीक्षा जांच का सारांश	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
			<p>स्थगन कार्यात्मकता</p> <p>कुल कारोबार फ्लैगिंग</p> <p>तंत्र कम्पोजीशन प्रपत्रों की समय पर तैनाती</p> <p>समामेलन के मामले में</p> <p>पंजीकरण की प्रभावी तिथि</p> <p>रद्दीकरण में समस्या</p> <p>मैपिंग समस्याएँ</p> <p>पंजीकरण में संशोधन</p> <p>जीएसटीपी मुद्दे</p> <p>आरएफपी और एसआरएस के बीच बेमलता</p> <p>स्वतः संज्ञान पंजीकरण</p>	<p>3.1.1.6</p> <p>3.1.2.1</p> <p>3.1.2.2</p> <p>3.1.2.3</p> <p>3.1.2.4</p> <p>3.1.2.5</p> <p>3.1.2.6</p> <p>3.1.2.7</p> <p>3.1.2.9</p> <p>4.1.3</p> <p>3.1.3</p> <p>3.1.4</p> <p>4.1.2</p>
	परीक्षित नहीं (2)	सीमा प्रतिबंध (2)	कर देयता का आकलन, व्यवसाय के मुख्य स्थान में परिवर्तन से संबंधित संशोधन	-
यह निर्धारण करने के लिए कि क्या कार्यात्मकताएं व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करती हैं	परीक्षित	असफल (1)	नए पंजीकरण के मामले में समय सीमा का पालन	3.1.1.5
	जांच नहीं की जा सकी	सीमा प्रतिबंध (1)	एमआईएस प्रतिवेदन	परीक्षण वातावरण की सुविधा न होने के कारण एमआईएस प्रतिवेदनों की जांच नहीं की जा सकी।
	परीक्षित	सफल	पंजीकरण के संबंध में कार्यात्मकता के विकास के संबंध में समय सीमा का पालन	-

उप उद्देश्य	परीक्षण किया गया / परीक्षण नहीं किया गया	सफल/असफल/सीमा प्रतिबंध	लेखापरीक्षा जांच का सारांश	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
	जांच नहीं हुआ	सीमा प्रतिबंध (1)	पंजीकरण का गलत रद्दीकरण	-
परीक्षण किए गए अन्य मॉड्यूल के साथ एकीकरण की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए	परीक्षित (3)	सफल (1)	जीएसटी पोर्टल के एकीकरण के मुद्दे	-
		असफल (2)	सिस्टम सतर्कता	3.1.2.8

विभाग ने 22 कार्यात्मकताओं को विकसित किया, जिसमें सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया के पहलुओं को शामिल किया गया, जिसकी परिकल्पना 2016 में हस्ताक्षरित एसआरएस में की गई थी। बाद में, कानून के प्रावधानों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन अनुरोधों (सीआर) के माध्यम से नौ अतिरिक्त कार्यात्मकताएं विकसित की गईं, जिनके लिए इन संशोधनों/परिवर्धन की आवश्यकता थी। इन परिवर्तनों की सूचना सभी हितधारकों को परामर्शी के रूप में दी गई थी। विभाग ने एक वॉकथ्रू में कहा (दिसंबर 2020) कि 24 पंजीकरण फॉर्म प्रस्तुतिकरण में थे और चार फॉर्म विकास के लिए लंबित थे।

एप्लीकेशन में मैप की गई पंजीकरण प्रक्रियाओं की परीक्षण-जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (एनआरटीपी) के मामले में पंजीकरण की वैधता, पंजीकरण की प्रभावी तिथि, नए पंजीकरण के विभिन्न चरणों के लिए तिथियां और समयसीमा, नए पंजीकरण के लिए कर-अधिकारी के डैशबोर्ड में ट्रिगर अलर्ट आदि जैसी कार्यात्मकताएं व्यवस्थित पाई गईं। तथापि, एसआरएस की जांच, डेटा प्रश्नों के आउटपुट और कार्यात्मकताएं जिनका परीक्षण नकारात्मक आया के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ देखी गईं:

### 3.1.1 नए पंजीकरण की अनुमोदन प्रक्रिया से संबंधित प्रस्तुतिकरण में विकसित और तैनात की गई कार्यात्मकताओं के संबंध में अपर्याप्त सत्यापन

अधिसूचना 18/2020 और 19/2020-केंद्रीय कर दिनांक 23 मार्च 2020, माल एवं वस्तु कर पंजीकरण की मांग करने वाली इकाई से जुड़े निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में 01 अप्रैल 2020 से आधार प्रमाणीकरण शुरू किया गया:

- व्यक्तिगत,
- सभी प्रकार के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
- साझेदारी फर्म के प्रबंध और अधिकृत भागीदारों, और
- एचयूएफ का कर्ता

#### 3.1.1.1 अप्रमाणित आधार मामलों के लिए व्यावसायिक परिसरों का अनिवार्य भौतिक सत्यापन (पीवी) नहीं किया गया था

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 8 के उप-नियम (4ए)<sup>12</sup> के साथ पठित परामर्शी संख्या 19/2020 अगस्त 2020, सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 9 (1) और 9 (5) में एक साथ प्रावधान है कि जहां धारा 25 की उप-धारा (6 डी) के तहत अधिसूचित लोगों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति आधार संख्या के प्रमाणीकरण से गुजरने में विफल रहता है या आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनता है, तो 01 अप्रैल 2020 से, आवेदन की तिथि से साठ दिनों के अंदर, नियम 25 के तहत प्रदान किए गए तरीके से पंजीकरण<sup>13</sup> केवल उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में व्यवसाय के प्रमुख स्थान के भौतिक सत्यापन के बाद ही प्रदान किया जाएगा और पूर्वोक्त नियम 9 (5) में उल्लिखित डीमड अनुमोदन के प्रावधान ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा ने 01 अप्रैल 2020 से 20 अगस्त 2020 की अवधि के सीबीआईसी डेटाबेस से 2,78,732 पंजीकरण आवेदनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि 34,227 मामलों में पंजीकरण डीमड अनुमोदित माना गया था। इन 34,227 मामलों में से, 225 यादृच्छिक रूप

<sup>12</sup> अधिसूचना संख्या 16/2020-केंद्रीय कर के माध्यम से अन्तर्स्थापित

<sup>13</sup> अधिसूचना संख्या 16/2020-केंद्रीय कर दिनांक 23.03.2020 से अन्तर्स्थापित और अधिसूचना संख्या 62/2020-केंद्रीय कर दिनांक 20.08.2020 द्वारा प्रतिस्थापित एवं 01.04.2020 से प्रभावी।

से चयनित मामलों<sup>14</sup> को आधार सत्यापन स्थिति के लिए माल एवं सेवा कर नेटवर्क पोर्टल में डेटा के साथ क्रॉस सत्यापित किया गया था और यह देखा गया कि 208 मामलों में, माल एवं सेवा कर नेटवर्क पोर्टल ने आधार सत्यापन की स्थिति को 'एन' के रूप में दिखाया, जिसका अर्थ है कि आधार सत्यापित नहीं था और कर अधिकारी को माल एवं सेवा कर पहचान संख्या प्रदान करने से पहले परिसर का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करना था और आवेदनों को उक्त अवधि के लिए डीमड अनुमोदित नहीं माना जाना चाहिए था। इन 208 अभिलेखों के लिए, सीबीआईसी डेटाबेस ने भी 'अनिवार्य भौतिक सत्यापन' मद को 'एन' के रूप में दिखाया, जिससे यह पुष्टि होती है कि इन आवेदनों को व्यावसायिक आधार के भौतिक सत्यापन के परिचालन के बिना डीमड अनुमोदित माना गया था, जिससे उक्त अवधि के लिए कानून के प्रावधानों से विचलन हुआ। इसका मतलब यह है कि प्रणाली कर अधिकारियों को असत्यापित आधार स्थिति वाले करदाताओं के संबंध में परिसर के अनिवार्य भौतिक सत्यापन के बिना या उससे पहले पंजीकरण प्रदान करने की अनुमति देती है। ऐसे मामलों में पीवी का परिचालन नहीं करने से धोखाधड़ी करने के इरादे से लेनदेन करने के लिए पंजीकरण प्राप्त करने का जोखिम बढ़ता है।

**सिफारिश 9: विभाग को उन मामलों के लिए परिसर का पार्श्व भौतिक सत्यापन करना चाहिए जहां आधार प्रमाणित नहीं किया गया था। सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी प्रणाली में असत्यापित आधार स्थिति वाले करदाताओं के अनिवार्य भौतिक सत्यापन के बिना पंजीकरण की अनुमति नहीं देने का प्रावधान होना चाहिए।**

**सिफारिश 10: विभाग को उन मामलों के लिए अपवाद रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान करना चाहिए जहां करदाता के आधार सत्यापन और अनिवार्य भौतिक सत्यापन स्थिति की निगरानी और उचित कार्रवाई करने के लिए 'एन' के रूप में चिह्नित किया गया है।**

---

<sup>14</sup> लेखापरीक्षा दल को प्रदान किए गए चेन्नई ज़ोन को सिंगल साइन ऑन आईडी क्रेडेंशियल के माध्यम से सत्यापित।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने पैरा स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि आधार प्रमाणीकरण माल एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा अगस्त 2020 से सक्रिय किया गया था और इसे सीबीआईसी द्वारा 5 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया था और उन मामलों के लिए पश्च भौतिक सत्यापन करने के लिए लेखापरीक्षा की सिफारिश को, जहां आधार प्रमाणित नहीं किया गया है और आवेदन को डीम्ड अनुमोदित माना गया है, पॉलिसी विंग को सूचित किया गया है।

तथ्य यह है कि आधार प्रमाणीकरण के स्थान पर भौतिक सत्यापन का कानूनी प्रावधान 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी था।

### 3.1.1.2 अनुमोदन करने वाले सीपीसी अधिकारियों और क्षेत्राधिकार अधिकारियों के बीच सूचना के अधूरे आदान-प्रदान से पीवी के निर्णय पर प्रभाव

जहां पंजीकरण करने हेतु करदाता आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनते हैं, माल एवं सेवा कर नेटवर्क पोर्टल ईमेल के माध्यम से आधार सत्यापन के लिए लिंक को अग्रेषित करता है। इस प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर, माल एवं सेवा कर नेटवर्क पोर्टल ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध 'सत्यापित'/'असफल' के रूप में आधार स्थिति निर्धारित करेगा। यदि सभी व्यक्ति अपने आधार को सफलतापूर्वक सत्यापित करते हैं, तो भौतिक सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उनमें से कोई भी आधार सत्यापन में विफल रहता है, तो माल एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) चिह्नित की जाती है। जहां व्यक्ति आधार सत्यापन का विकल्प नहीं चुनता है, पंजीकरण प्रदान करने से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य हो जाता है और ऐसे मामलों में भी, एआरएन को माल एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए चिह्नित किया जाता है। भौतिक सत्यापन के लिए चिह्नित सभी मामलों को सीबीआईसी के केन्द्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ द्वारा भौतिक सत्यापन के परिचालन के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारियों को भेज दिया जाता है।

उचित अधिकारी, लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने के बाद और संयुक्त आयुक्त के रैंक से नीचे-नहीं के अधिकारी के अनुमोदन से, व्यवसाय के

स्थान के भौतिक सत्यापन के बदले में, ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन कर सकता है जो वह भौतिक सत्यापन<sup>15</sup> के बदले में उचित समझे। भौतिक सत्यापन किए बिना दस्तावेजों के सत्यापन पर अनुमोदन प्रदान करने की यह सुविधा बाद में वापस<sup>16</sup> ले ली गई थी। इसके अतिरिक्त, 24 अगस्त 2020 के परामर्शी 19/2020 के अनुसार, विभाग ने दिए गए 21 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा (केवल सांकेतिक) निर्दिष्ट की; ये समय सीमाएं केवल अधिकारियों को उनके अंत पर बिना किसी विलंब के काम पूरा करने में सहायता करने के लिए सांकेतिक हैं।

अगस्त 2020 से मार्च 2021 की अवधि के सीबीआईसी डेटाबेस<sup>17</sup> से 28,775 मामलों के डेटा जहां आधार स्थिति 'एन' है और अनिवार्य फ़ील्ड विज़िट 'वाई' है के विश्लेषण से पता चला है कि 13,665 मामलों में, जिस तिथि को केन्द्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारी को अग्रेषित किया गया था, वह तिथि रिक्त थी और क्षेत्राधिकार अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि भी रिक्त थी। क्षेत्राधिकार अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के परिचालन पर महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में, केन्द्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ कर अधिकारी ने पंजीकरण को किस आधार पर स्वीकृति दी है, यह ज्ञात नहीं हो पाया। 'भौतिक सत्यापन को अग्रेषित' और 'भौतिक सत्यापन के संचालन की तिथि' फ़ील्ड में रिक्त मूल्य से पता चलता है कि केन्द्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ से क्षेत्राधिकार अधिकारी और इसके प्रतिकूल में डेटा के प्रवाह में समस्याएं हैं जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा इस बात पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि क्या उजागर किए गए मामलों के लिए भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया था।

यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में उन मामलों में संयुक्त आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्यप्रवाह प्रदान नहीं किया गया था जहां भौतिक सत्यापन के बदले दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है और आईटी प्रणाली से यह पता नहीं

<sup>15</sup> अधिसूचना 62/2020 दिनांक: 20.08.2020 के अनुसार

<sup>16</sup> अधिसूचना 94/2020 दिनांक: 22.12.2020 के माध्यम से

<sup>17</sup> सीबीआईसी द्वारा लिंक में अंतरंग से डेटा साझा किया गया था दिनांक: 10.09.2021

लगाया जा सका कि 20 अगस्त 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि में भौतिक सत्यापन के बदले दस्तावेजों का सत्यापन किया गया था या नहीं। कर अधिकारी द्वारा अनुमोदित पंजीयनों के यादृच्छिक रूप से चयनित 15 प्रकरणों की नमूना-जांच करने पर यह पाया गया कि 6 मामलों<sup>18</sup> में कर अधिकारी ने भौतिक सत्यापन किए बिना पंजीयन को स्वीकृति प्रदान की थी।

महत्वपूर्ण जानकारी की अनुपस्थिति जैसे '\_\_\_ पर भौतिक सत्यापन को अग्रेषित' और 'पीवी के परिचालन की तिथि\_\_\_\_' केन्द्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ अधिकारी द्वारा पंजीकरण के अनुमोदन को प्रभावित करती है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने अनुपालन के लिए अभ्युक्ति (अगस्त 2022) को नोट किया और कहा कि कार्यप्रवाह के अभाव में अधिकारी ऑफ़लाइन अनुमोदन प्राप्त कर सकता है और सिस्टम में टिप्पणियाँ अपलोड कर सकता है और उचित समझे जाने वाली कार्रवाई कर सकता है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि निर्णयों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सबसे अच्छा तभी बनाए रखा जा सकता है जब ट्रेल सिस्टम में बनाया जाता है न कि ऑफ़लाइन।

### 3.1.1.3 पंजीकरणों के अनियमित अनुमोदन जिन्हें भौतिक सत्यापन (पीवी) प्रतिवेदन में अस्वीकृति के लिए अनुशंसित किया गया था

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 883 मामलों (अखिल भारतीय) में जहां क्षेत्राधिकार रेंज अधिकारी ने भौतिक सत्यापन का परिचालन किया था और विशेष रूप से भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में अस्वीकृति के लिए सिफारिश की थी, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन ने करदाताओं के रूप में उनके पंजीकरण की स्वीकृति की अनुमति दी थी और माल एवं सेवा कर पहचान संख्या भी उत्पन्न किए गए थे। लेखापरीक्षा ने चेन्नई जोन से संबंधित लेखापरीक्षा सिंगल साइन ऑन आईडी क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के साथ इन 883 मामलों में से

<sup>18</sup> चेन्नई जोन के लेखापरीक्षा सिंगल साइन ऑन आईडी के माध्यम से सत्यापित।

आठ मामलों को क्रॉस वेरिफाई किया। यह देखा गया कि रेंज ऑफिसर ने वास्तव में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में अपनी टिप्पणियों में पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार करने की सिफारिश की थी।

इस संबंध में, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में भौतिक सत्यापन के लिए चिह्नित आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) के प्रसंस्करण के लिए दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के परामर्शी संख्या 26/2020 में वर्णित प्रक्रियाओं और प्रक्रमों का सन्दर्भ लिया गया। रेंज ऑफिसर/सुपरिंटेंडेंट द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर, प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के सत्यापन के लिए सहायक आयुक्त (एसी)/उपायुक्त (डीसी) के डैशबोर्ड पर एक 'भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त' कार्य बनाया जाता है। तथापि, इन अधिकारियों को केवल फारवर्ड प्रतिवेदन का विकल्प प्रदान किया जाता है और उन्हें टिप्पणियाँ कॉलम में टिप्पणियाँ दर्ज करने के बाद भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ उनके सहमति/असहमति के बावजूद आवश्यक रूप से प्रतिवेदन को केन्द्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ अधिकारी को अग्रेषित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि केन्द्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ अधिकारी निर्धारित 21 कैलेंडर दिनों के भीतर इन एआरएन पर कार्रवाई करने में विफल रहता है तो इन आवेदनों को डीमड अनुमोदित माना जाता है। इस प्रकार, पीवी रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में सीपीसी अधिकारी को सतर्क(अलर्ट) करने के लिए सीबीआईसी एप्लीकेशन में प्रावधान की कमी के परिणामस्वरूप उन मामलों में भी पंजीकरण को अनुमोदन दिया गया है जहां पीवी रिपोर्ट पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार करने की मांग करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीपीसी पीवी रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों को सत्यापित किए बिना पंजीकरण के अनुमोदन की अनुमति दे रहा है क्योंकि लेखापरीक्षा में पंजीकरणों के अनुमोदन के स्रोत को सत्यापित नहीं किया जा सका जिनकी विशेष रूप से अस्वीकृति के लिए सिफारिश की गई है। अस्वीकृति करने की इस तरह की ओवररूलिंग से उन करदाताओं के सृजन का जोखिम हो सकता है जो पंजीकृत होने के हकदार नहीं हैं।

**सिफारिश 11: विभाग को एक अलर्ट विकसित करना चाहिए जिसके द्वारा सीपीसी अधिकारी प्रतिकूल/नकारात्मक टिप्पणियों की पहचान कर सकें। उसे**

**ऐसे मामलों की एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने पर भी विचार करना चाहिए।**

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट किया (अगस्त 2022) और बताया कि विभाग पहले से ही सीपीसी अधिकारियों को पीवी टिप्पणियों के बारे में अलर्ट को लागू करने पर विचार कर रहा था।

#### **3.1.1.4 प्रासंगिक नियम/प्रावधानों के अभाव में आधार प्रमाणीकरण/भौतिक सत्यापन के बिना पंजीकरणों का गलत अनुमोदन**

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 29 मार्च 2019 की अधिसूचना जीएसआर 275 ई के अनुसार, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में नियम 38 (ए) को शामिल किया गया है, जिससे एमसीए पोर्टल में निगमन होने की इच्छुक कंपनी को एमसीए पोर्टल के स्पाइस-एजाइल फॉर्म के माध्यम से जीएसटीआईएन पंजीकरण का विकल्प चुनने में सक्षम बनाया गया है। यह प्रावधान जीएसटीएन द्वारा 21 जून 2019 से लागू किया गया है। एमसीए पोर्टल पर जीएसटी आवेदन के सफल प्रसंस्करण के बाद, सीआईएन (कॉर्पोरेट पहचान संख्या), डीआईएन (निदेशक पहचान संख्या) और पैन को आगे की प्रक्रिया के लिए जीएसटी पोर्टल पर प्रेषित किया जाता है।

एमसीए पोर्टल के माध्यम से दर्ज एआरएन के लिए सीजीएसटी अधिनियम में आधार प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन से कोई विशिष्ट छूट उपलब्ध नहीं है। जीएसटीएन पोर्टल के साथ चेन्नई जोन में यादृच्छिक रूप से चुने गए 19 मामलों के प्रति सत्यापन पर, यह देखा गया कि 15 मामलों में, आधार को प्रमाणित नहीं किया गया है और सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन ने पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध इसे मंजूरी देने की अनुमति दी है।

इसके अलावा, 15 मार्च 2021 को परिवर्तन सलाहकार बोर्ड (सीएबी) की बैठक (09/2021) के कार्यवृत्त की अवलोकन में यह पाया गया कि एमसीए पोर्टल के माध्यम से करदाताओं (एआरएन) द्वारा दर्ज आवेदनों के लिए, आधार फ्लैग और भौतिक सत्यापन (पीवी) फ्लैग को जेएसओएन फाइल में शून्य के रूप में प्रेषित किया गया था। चूंकि ऐसे एआरएन के लिए आधार प्रमाणीकरण जीएसटीएन में लागू नहीं किया गया है, इसलिए आधार विवरण

रिक्त हैं और उचित अधिकारी को आवंटित नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप एआरएन डीमंड अनुमोदित हुए थे। इस समस्या के समाधान के लिए, विप्रो द्वारा 21 दिसंबर 2020 को 'परिवर्तन अनुरोध (सीआर) 282-आरईजी- 01 एआरएन- आधार छूट प्राप्त मामले (एमसीए)' के माध्यम से एक समाधान किया गया था, जिसके तहत एमसीए पोर्टल के माध्यम से दर्ज ऐसे सभी एआरएन को प्रसंस्करण के लिए उचित अधिकारी को आवंटित किया गया था जिनके आधार और पीवी विवरण रिक्त छोड़े गए थे।

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 9 (1) के प्रभावी कार्यान्वयन पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए, जिसमें आधार का विकल्प नहीं चुने गए या आधार प्रमाणीकरण विफल होने वाले एआरएन के लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य होता है, 21 अगस्त 2020 (सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में आधार कार्यात्मकता को लागू करने की तिथि) और 31 मार्च 2021 के बीच दर्ज एआरएन के सीबीआईसी डेटाबेस से एक अखिल भारतीय डेटा लिया गया था, जहां अनिवार्य 'आधार सत्यापन प्रास्थिति' का फील्ड या तो 'रिक्त' या 'असफल' है, लेकिन पंजीकरण को बिना किसी आधार प्रमाणीकरण या भौतिक सत्यापन के सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन द्वारा अनुमोदित किया गया है। लेखापरीक्षा ने ऐसे 1,130 एमसीए सृजित एआरएन की पहचान की। इनमें से, 152 एआरएन 21 दिसंबर 2020 की तय तिथि के कार्यान्वयन के बाद दर्ज किए गए थे। इसका अर्थ यह है कि उचित अधिकारी को मामलों के आवंटन को सक्षम करने वाली प्रणाली को ठीक किए जाने के बावजूद, उचित अधिकारी ने अनिवार्य भौतिक सत्यापन के बिना उन मामलों को मंजूरी दे दी, जहां करदाता ने या तो आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना था या आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुना था लेकिन यह विफल हो गया था।

विभाग को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए दर्शाए गए मामलों की जांच करने और कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखा गया है। इसके अलावा, विभाग से यह भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि समस्या का समाधान करने के बाद, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन द्वारा 'रिक्त' या 'असफल' के रूप

में आधार सत्यापन की स्थिति वाले 152 एआरएन को कैसे मंजूरी दी गई थी।

**सिफारिश 12: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एमसीए पोर्टल के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में अनुमोदित नहीं किया जाता है, जब तक कि इसे आधार प्रमाणित नहीं किया जाता, या भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हो जाता।**

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट किया (अगस्त 2022) और बताया कि किसी प्रदत्त आवेदन के लिए भौतिक सत्यापन की आवश्यकता है या नहीं, यह निर्णय जीएसटीएन प्रणाली द्वारा इंगित और सूचित किया गया है। जहां तक सीआर-282 का संबंध है, इसे एमसीए पोर्टल के माध्यम से दर्ज एआरएन को प्रसंस्करण करने के लिए उचित अधिकारी को आवंटित करने और डीमंड अनुमोदन को रोकने के लिए लागू किया गया था।

तथ्य यह है कि एमसीए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण आवेदनों के मामले में पंजीकरणों को मान्य (डीमंड) माने जाने से बचने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है।

### **3.1.1.5 अपर्याप्त वैधीकरण के परिणामस्वरूप पंजीकरण आवेदनों के प्रसंस्करण में समय सीमा का पालन नहीं हुआ**

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 9 (2) के अनुसार, जहां नियम 8 के तहत प्रस्तुत आवेदन में या तो उक्त नियम के तहत प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी जानकारी या किसी भी दस्तावेज के संदर्भ में, कोई कमी पाई जाती है, या जहां उचित अधिकारी को आवेदन में प्रदान की गई किसी भी जानकारी या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, वहां उचित अधिकारी आवेदन जमा करने की तिथि से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी आरईजी -03 में आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी कर सकता है और आवेदक ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी

आरईजी -04 में, इस तरह के नोटिस की प्राप्ति की तिथि से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

इसके अलावा, नियम 9 (3) में यह निर्धारित किया गया है कि यदि उचित अधिकारी प्रस्तुत स्पष्टीकरण, जानकारी या दस्तावेजों से संतुष्ट है, तो पंजीकरण के लिए आवेदन को इस तरह के स्पष्टीकरण या सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और फॉर्म जीएसटी आरईजी 06 में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। यदि उचित अधिकारी सात दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो ऐसे मामलों के पंजीकरण को डीमड अनुमोदित माना जाएगा।

हालांकि, जहां उप-नियम (2) के तहत जारी नोटिस के उत्तर में आवेदक द्वारा सात दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, तो नियम 9 (4)<sup>19</sup> के तहत उचित अधिकारी द्वारा कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद ऐसे आवेदन को अस्वीकृत करना और फॉर्म जीएसटी आरईजी -05 में आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना देना अपेक्षित है। इसके अलावा, पंजीकरण पर एसआरएस संस्करण 1.3 में यह भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन को पंजीकरण आवेदन को स्वचालित रूप से अस्वीकार करने की कार्यात्मकता के साथ सक्षम बनाया जाएगा यदि करदाता नोटिस प्राप्त होने की तिथि से सात सामान्य कार्य दिवसों के भीतर उत्तर देने में विफल रहता है।

सीबीआईसी डेटाबेस से अखिल भारतीय आधार पर निकाले गए आंकड़ों से निम्नलिखित का पता चला:

---

<sup>19</sup> नियम 9 (4) निर्दिष्ट करता है कि उचित अधिकारी को आवेदन को अस्वीकार करना होगा, यदि जारी किए गए नोटिस का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है या अधिकारी उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद और आवेदक को फॉर्म जीएसटी आरईजी -05 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करना होगा। हालांकि पूर्वोक्त नियम में इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया है कि उचित अधिकारी को किस समयसीमा के भीतर आवेदन को अस्वीकार करना होता है।

- (i) 7,67,328 मामलों (एसएटीक्यू\_आरईजी\_एसक्यू02, अवधि: 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2021) में, पंजीकरण के लिए आवेदनों को कर अधिकारी द्वारा न तो अनुमोदित किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है जो कि सीजीएसटी नियमावली के नियम 9 के प्रावधानों का उल्लंघन है और सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में एक प्रभावी वैधीकरण कार्यविधि के अभाव को दर्शाता है।
- (ii) 72,955 मामलों (एसएटीक्यू\_आरईजी\_एसक्यू05, अवधि: 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2021) में, जहां फॉर्म आरईजी 03 के माध्यम से प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन करदाता द्वारा उत्तर (फॉर्म आरईजी 04) प्रस्तुत नहीं किए गए थे, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन ने 15,727 मामलों में कर अधिकारी द्वारा पंजीकरण को अनुमोदन देने की अनुमति दी थी और 57,228 मामलों में डीमंड अनुमोदित माना गया था और पंजीकरण का प्रमाण पत्र (आरईजी 06) जारी किया गया था, जो पूर्वोक्त नियम 9 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। ऐसे सभी मामलों में जहां निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर नहीं मिला है, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन ने आवेदन को अस्वीकार करने के बजाय पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी थी।

यह, यदि करदाता नोटिस की प्राप्ति की तिथि से सात सामान्य कार्य दिवसों के भीतर उत्तर देने में विफल रहता है तो उसके पंजीकरण आवेदन को स्वचालित रूप से अस्वीकृत करने के लिए एसआरएस 1.3 में परिकल्पित वैधीकरण सुविधा की अप्रभाविकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। विभाग को उपर्युक्त कार्यात्मकता की विफलता के कारणों की जांच करने की आवश्यकता है। साथ ही उन कारणों की जांच की जानी चाहिए कि कैसे एआरएन का न तो अनुमोदन किया गया और न ही इसे अस्वीकार किया गया और इस पर उचित कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने आंशिक रूप से पैरा को स्वीकार कर लिया और बताया (अगस्त 2022) कि नियम 9 उन

मामलों के लिए कोई समयसीमा प्रदान नहीं करता जहां करदाता ने उत्तर नहीं दिया है और इसलिए प्रणाली में स्वतः-अस्वीकृति का विकल्प नहीं बनाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि अलर्ट कोड की विफलता के कारण जीएसटीएन के साथ समन्वय की विफलता के कारण 57,228 मामलों को डीम्ड अनुमोदित किया गया था। तकनीकी टीम इस मामले पर कार्य कर रही है।

**सिफारिश 13: विभाग सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 9 के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकता है ताकि उन मामलों में पंजीकरण के लिए आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए एक समयसीमा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जा सके, जहां आवेदक सात दिनों के भीतर फॉर्म जीएसटी आरईजी -03 का उत्तर देने में विफल रहता है।**

### 3.1.1.6 निलंबन कार्यात्मकता के कार्यान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप अप्रभावी निगरानी हुई

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 21 (ए) (1) के अनुसार, जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति ने नियम 20 के तहत पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन किया है, वहां पंजीकरण को आवेदन जमा करने की तिथि या निरस्त करने की मांग की तिथि जो भी बाद में हो, से पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही पूरी होने तक निलंबित माना जाएगा। पूर्वोक्त नियम 21 (ए) (2) में प्रावधान है कि जहां उचित अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि किसी व्यक्ति का पंजीकरण निरस्त करने के लिए दायी है, वह उक्त व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, निरस्त करने की कार्यवाही पूरी होने तक उसके द्वारा निर्धारित की गई तिथि से ऐसे व्यक्ति के पंजीकरण को निलंबित कर सकता है। इसके अलावा, नियम 21 (ए) (3) निर्दिष्ट करता है कि एक पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पंजीकरण पूर्वोक्त नियम 21 (ए) (1) या नियम 21 (ए) (2) के तहत निलंबित कर दिया गया है, निलंबन की अवधि के दौरान कोई कर योग्य आपूर्ति नहीं करेगा और उसे धारा 39 के तहत कोई रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त सभी नियम प्रावधान सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 03/2019-

केंद्रीय कर दिनांक 29 जनवरी 2019 के माध्यम से 01 फरवरी 2019 से प्रभावी हैं।

एसआरएस दस्तावेजों, विभागीय परामर्शों की जांच करने और विभागीय अधिकारियों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त नियमों के अनुरूप कार्यात्मकताओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था और सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में 'निलंबन की प्रभावी तिथि' को दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में 'निलंबन की प्रभावी तिथि' को शामिल करने के प्रावधान के अभाव में यह देखा गया कि पूर्वोक्त नियम 21 (ए) (3) के तहत निर्धारित शर्तों को लागू करने के लिए कोई तंत्र नहीं था, जिससे पंजीकृत व्यक्तियों को किसी भी कर योग्य आपूर्ति करने से प्रतिबंधित किया जा सके और निलंबन की अवधि के दौरान क्रेडिट का हस्तांतरण रोका जा सके।

मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार कर लिया और बताया (अगस्त 2022) कि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा निरस्तीकरण के लिए आवेदन किए जाने के मामले में, निलंबन की प्रभावी तिथि को एपीआई के माध्यम से जीएसटीएन द्वारा सूचित किया जाना है और इसे समन्वय के लिए लिया जाएगा। स्वतः निरस्तीकरण के मामले में निलंबन की तिथि सीबीआईसी प्रणाली में दर्ज की जाएगी। इस संवर्द्धन को कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा।

**सिफारिश 14: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निलंबन कार्यात्मकता सीजीएसटी नियमों के अनुरूप सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में लागू की जाए।**

3.1.2 कुछ वैधीकरण नियंत्रणों में अपर्याप्तताएं जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण अनुमोदनों और निरस्तीकरणों से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन हुआ

3.1.2.1 संयोजन उद्ग्रहण योजना का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के मामले में एकल पैन के तहत कुल कारोबार की गणना करने के लिए कार्यविधि का अभाव

अधिसूचना संख्या 14/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 07 मार्च, 2019 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 में प्रावधान है कि कोई पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्त वर्ष में कुल कारोबार एक करोड़ पचास लाख रुपये<sup>20</sup> से अधिक नहीं था, संयोजन उदग्रहण योजना (सीएलएस) के तहत भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। जहां पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में करदाता के एकल पैन के तहत कुल कारोबार सीमा से अधिक है, तो पंजीकृत व्यक्ति संयोजन उदग्रहण योजना के तहत कर का भुगतान जारी रखने के लिए पात्र नहीं है और उसे जीएसटी प्रभारित करने के लिए सामान्य करदाता में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था।

मॉडल कानून के मसौदे के आधार पर 2016 में हस्ताक्षरित एसआरएस रिटर्न मॉड्यूल में कर रिटर्न राशि से कुल कारोबार का वैधीकरण नहीं करता और पंजीकृत व्यक्ति का कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक होने पर क्षेत्राधिकार के उचित अधिकारी को सचेत नहीं करता है ताकि कर अधिकारी तदनुसार कार्रवाई शुरू कर सके। साथ ही, एप्लीकेशन सीएलएस कि दर को मान्य करने के लिए राज्यों में कुल कारोबार को निर्धारित नहीं करती। चूंकि सामान्य करदाताओं के लिए कर व्यवस्था सीएलएस करदाताओं की तुलना में भिन्न है, इसलिए आईटी प्रणालियों में इस तरह की कमी से राजकोष पर राजस्व प्रभाव पड़ेगा और इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

**सिफारिश 15: विभाग को रिटर्न से कुल कारोबार की गणना करने के लिए वैधीकरण को लागू करने और संयोजन उदग्रहण योजना के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित कारोबार सीमा को पार करने के बाद सामान्य करदाता स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए जीएसटीएन के साथ मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए कर अधिकारी के लिए अलर्ट को भी शामिल किया जा सकता है जहां करदाता संयोजन उदग्रहण योजना के लिए कारोबार सीमा को पार करते हैं। विभाग को ऐसे सभी पिछले मामलों की पहचान करनी चाहिए ताकि उन्हें सामान्य करदाता श्रेणी में लाया जा सके।**

<sup>20</sup> अधिसूचना संख्या 14/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 07.03.2019 में उल्लिखित राज्यों के लिए निर्धारित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की कुल वार्षिक कारोबार सीमा पचहत्तर लाख रुपये (75 लाख रुपये) है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2022) बताया कि विभाग ने पहले ही कारोबार सीमा से अधिक वाले करदाताओं के लिए संयोजन के विकल्प को प्रतिबंधित करने के लिए जीएसटीएन सीआर को प्राथमिकता दी थी।

**3.1.2.2. समान 'पैन करदाता प्रकार' को मान्य करने में विफलता जिसके परिणामस्वरूप करदाता एक ही पैन के साथ संयोजन और सामान्य करदाता के रूप में मौजूद है**

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (2) के तहत परंतुक में प्रावधान है कि जहां एक से अधिक पंजीकृत व्यक्तियों के पास एक ही स्थायी खाता संख्या है, वहां पंजीकृत व्यक्ति सीएलएस का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि ऐसे सभी पंजीकृत व्यक्ति सीएलएस के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प नहीं चुनते हैं। इसके अलावा, सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 6 (1) में प्रावधान है कि पूर्वोक्त धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प केवल तभी तक वैध रहेगा जब तक कि वह धारा और नियमों के तहत उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है। जहां उचित अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि पंजीकृत व्यक्ति धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के लिए पात्र नहीं है, तो उसे पूर्वोक्त धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प से इनकार करने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए (सीएमपी -5)।

संयोजन अनुमोदित करदाताओं के लिए सीबीआईसी डेटाबेस से निकाले गए डेटा से पता चला कि एक ही पैन के साथ कई पंजीकरण सीएलएस के साथ-साथ सामान्य करदाताओं के तहत पंजीकृत पाए गए थे। इसके अलावा, ऐसे मामलों की पहचान की गई जहां एक करदाता का मौजूदा सामान्य पंजीकरण था और उसी पैन के साथ पंजीकरण के लिए बाद की तिथि में कर अधिकारी द्वारा सीएलएस के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिससे कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ (169 में से 17 ऐसे उदाहरण देखे गए)।

पंजीकरण आवेदन को अनुमोदित करते समय कर अधिकारी को 'पूर्व पंजीकरण देखें' की सुविधा दी जाती है। इस टैब के तहत कर अधिकारी

जीएसटीआईएन, पंजीकरण प्रकार (नया पंजीकरण /मौजूदा पंजीकरण), कानूनी नाम, क्षेत्राधिकार, पंजीकरण स्थिति (सक्रिय/निष्क्रिय), निरस्तीकरण की स्थिति (निरस्त/प्रस्तावित/ शुरू), निरस्तीकरण प्रकार (स्वतः संज्ञान/ करदाता द्वारा), निरसन किया गया, पर्यवेक्षण (केंद्र/राज्य) और निरस्त करने का कारण देख सकते हैं। हालांकि इस टैब में इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि उसी पैन वाले दूसरे पंजीकरण में सीएलएस का विकल्प चुना है या सामान्य स्थिति का। चूंकि सामान्य करदाताओं के लिए कर व्यवस्था सीएलएस करदाताओं की तुलना में अलग है, इसलिए आईटी प्रणालियों में इस तरह की कमी से राजकोष पर राजस्व प्रभाव पड़ेगा और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

**सिफारिश 16: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रणाली में वैधीकरण मौजूद है ताकि एक ही समय पर सामान्य पंजीकरण के तहत करदाता को संयोजन उदग्रहण योजना के तहत एक ही पैन के साथ और इसके प्रतिकूल में पंजीकरण की अनुमति ना दी जाए। विभाग को ऐसे सभी पिछले मामलों की पहचान करनी चाहिए ताकि उन्हें सामान्य करदाता श्रेणी में लाया जा सके।**

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट किया (अगस्त 2022) और बताया कि जीएसटीएन डेटा बेस के साथ सभी पंजीकरण डेटा बेस का मिलान कार्य सुधार हेतु किया जाता है, और यदि कोई है।

### 3.1.2.3 संयोजन (सीएमपी) फॉर्म के कार्यान्वयन में देरी

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (2) के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 6 में प्रावधान है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प केवल तभी तक वैध रहेगा जब तक वह सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। नियम 6 (4) के अनुसार, जहां उचित अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि पंजीकृत व्यक्ति धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के लिए पात्र नहीं था, वहां वह सीएमपी -05 में ऐसे व्यक्ति को कारण बताने के लिए नोटिस जारी कर सकता है कि धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प

से इनकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस का उत्तर (सीएमपी-06) प्राप्त होने पर उचित अधिकारी को ऐसे उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर सीएमपी-07 में एक आदेश जारी करना चाहिए जिसमें या तो उत्तर स्वीकार किया गया हो या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तिथि से सीएलएस के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प से इनकार किया गया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रासंगिक सीएमपी फॉर्म को लागू नहीं किया गया था, जिसके द्वारा उचित अधिकारी धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प से इनकार कर सकता है, जिससे प्रावधानों के तहत कर अधिकारी द्वारा शुरू की जा सकने वाली कार्रवाई का दायरा सीमित हो गया। इसके अलावा, उन करदाताओं की पहचान करने के लिए उचित अधिकारी को सचेत करने के लिए कोई वैधीकरण जांच नहीं है जो अब सीएलएस से संबंधित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

संयोजन करदाताओं के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण फॉर्म के कार्यान्वयन में देरी और पात्रता शर्तों को मान्य करने के लिए अपर्याप्त जांच के परिणामस्वरूप अपात्र करदाताओं जैसे कि संयोजन और सामान्य करदाताओं दोनों के रूप में मौजूद समान पैर वाले करदाताओं की पहचान नहीं की गई और योजना के तहत विकल्प से वंचित करने के लिए कार्रवाई शुरू करने में उचित अधिकारियों की ओर से विफलता हुई।

**सिफारिश 17: विभाग को सीएमपी-5, सीएमपी-6 और सीएमपी-7 प्रपत्रों का शीघ्र विकास सुनिश्चित करना चाहिए और वैधीकरण जांच अलर्ट सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उचित अधिकारी उन करदाताओं के विरुद्ध निर्धारित कार्रवाई शुरू कर सकें जो अब सीएलएस से संबंधित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।**

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने अनुपालन के लिए सिफारिश (अगस्त 2022) को नोट किया और बताया कि विभाग ने इसे लागू करने को प्राथमिकता दी है।

### 3.1.2.4 उत्तराधिकार/अविलयन/समामेलन के कारण हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त पंजीकरणों के मामले में दायित्व की प्रभावी तिथि का पता लगाने के लिए अपर्याप्त वैधीकरण

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 (1) के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 10 (2) और 10 (3) निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा और पंजीकरण उस तिथि से प्रभावी होगा जिस पर व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी हो जाता है और जहां पंजीकरण उसके उत्तरदायी होने की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया गया है तो पंजीकरण की प्रभावी तिथि पंजीकरण को अनुमति देने की तिथि होगी।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 (3) के अनुसार, जहां उत्तराधिकार के कारण या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को पंजीकरण प्राप्त होता है, तो हस्तांतरिती या उत्तराधिकारी इस तरह के हस्तांतरण या उत्तराधिकार की तिथि से पंजीकृत होने के लिए दायी होगा। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दो या दो से अधिक कंपनियों के अविलयन/समामेलन के मामले में हस्तांतरिती उस तिथि से पंजीकृत होने के लिए दायी होगा जिस पर कंपनी पंजीयन द्वारा निगमन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है (धारा 22 (4))।

सीबीआईसी डेटाबेस से 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए प्राप्त किए गए डेटा के विश्लेषण से पता चला कि सामान्य पंजीकरण पूर्वोक्त नियम के अनुसार अनुमोदित हैं। इसके अलावा पंजीकरण डेटा के विश्लेषण से पता चला कि स्थानांतरण/अविलयन/समामेलन के कारणों से 3,290 मामले पंजीकृत किए गए थे। सभी मामलों में पंजीकरण की प्रभावी तिथि को पूर्वोक्त नियम में प्रदान की गई शर्तों को पूरा करते हुए देखा गया था, न कि पूर्वोक्त धारा 22 (3) या धारा 22 (4) में किए गए प्रावधान के अनुसार। चेन्नई जोन में 10 मामलों की यादृच्छिक जांच से पता चला कि 5 मामलों में, पंजीकरण की प्रभावी तिथि निगमन/साझेदारी विलेख के प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि के समान नहीं थी। निगमन की तिथि को प्राप्त

करने के लिए सीबीआईसी एप्लीकेशन में प्रावधान के अभाव में, विभाग हस्तांतरिती कंपनी के दायित्व/पंजीकरण की प्रभावी तिथि का पता लगाने की स्थिति में नहीं है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) को जारी किया गया था, और मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2022) कि इसे जीएसटीएन की ओर से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय की आवश्यकता होगी और इसलिए यह एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के कार्यक्षेत्र से बाहर था।

**सिफारिश 18: विभाग को स्थानांतरित कंपनी के निगमन की तिथि को डेटा तत्व के रूप में अभिग्रहित करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ मामले के अनुसरण के लिए जीएसटीएन से अनुरोध करना चाहिए।**

### 3.1.2.5 करदाता के अनुरोध पर पंजीकरण निरस्त करने के संबंध में कर अधिकारी को सचेत करने के लिए वैधीकरण का अभाव

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 22 (3) में प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति जिसने अपना पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अब पंजीकृत होने के लिए दायी नहीं है, वहां उचित अधिकारी आवेदन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर या, जैसा भी मामला हो, जारी किए गए किसी भी कारण बताओ नोटिस के उत्तर की तिथि पर, फॉर्म जीएसटी आरईजी -19 में एक आदेश जारी कर उसके द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथि से पंजीकरण को निरस्त करेगा और कर योग्य व्यक्ति को सूचित करेगा तथा उसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उप-धारा (5) के तहत भुगतान की जाने वाली राशि सहित किसी भी कर, ब्याज या दंड के बकाया का भुगतान करने का निर्देश देगा।

सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 20 के साथ पठित परिपत्र संख्या 69/43/2018-जीएसटी में प्रावधान है कि पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करने वाला करदाता "निरस्तीकरण को प्रमाणित करने की घटना" के 30 दिनों की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आरईजी - 16 में आवेदन जमा करेगा। हालांकि, घटना वाले दिन की ठीक-ठीक पहचान करने में कठिनाई को देखते हुए, समय सीमा के संभावित उल्लंघन

के कारण आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उचित अधिकारी को आवेदन दर्ज होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे सभी आवेदनों को स्वीकार करना चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां आवेदन अधूरे हैं या जहां हस्तांतरण/उत्तराधिकार या समामेलन के कारणों से करदाता द्वारा निरस्तीकरण का आवेदन किया गया है और उत्तराधिकारी इकाई ने मौजूदा पंजीकरण को निरस्त करने से पहले एक नया पंजीकरण प्राप्त नहीं किया था। परिपत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन को उचित अधिकारी द्वारा तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए और निरस्त करने का आदेश फॉर्म जीएसटी आरईजी -19 में जारी किया जाना चाहिए, निरस्त करने की प्रभावी तिथि उस तिथि के समान होनी चाहिए जिससे आवेदक ने फॉर्म जीएसटी आरईजी -16 में निरस्तीकरण की मांग की है। किसी भी मामले में, प्रभावी तिथि उसी के लिए आवेदन की तिथि से पहले की तिथि नहीं हो सकती है। इसके अलावा, एसआरएस वी.1.3 पैरा 2.1.6 में करदाता द्वारा जीएसटी पंजीकरण के अभ्यर्पण के लिए व्यावसायिक प्रक्रिया (अनुमोदन, प्रश्न उठाएं, कर अधिकारी द्वारा प्रश्न पर कार्रवाई का उत्तर) प्रदान की गई है।

01 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान स्वैच्छिक निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने वाले 2,27,327 करदाताओं के डेटा विश्लेषण से निम्नलिखित विचलनों का पता चला जो आवेदन का प्रसंस्करण करते समय अपर्याप्त वैधीकरण जांच को दर्शाता हैं।

**(i) अप्रभावी अलर्ट प्रणाली के परिणामस्वरूप निरस्तीकरण के अनुमोदन में हुई देरी**

एसआरएस वी.1.3 में निर्धारित पंजीकरण डैशबोर्ड के संबंध में वैधीकरण/व्यावसायिक नियमों में प्रावधान है कि सभी संव्यवहारों में, संव्यवहारों की गंभीरता के आधार पर अलर्ट के संकेतक दिखाए जाने चाहिए। प्रत्येक अलर्ट श्रेणी (निम्न, मध्यम और उच्च) के लिए मॉड्यूल-वार, संव्यवहार-वार सतर्कता की समयसीमा परिभाषित की जानी चाहिए।

निष्कर्षित डेटा के विश्लेषण से पता चला कि आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद निरस्तीकरण के लिए 51,561 अनुरोधों को अनुमोदन दिया

गया था, इस तथ्य के बावजूद कि कर अधिकारी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था। हालांकि, यह देखा गया कि समयसीमा पर अलर्ट को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है और जिससे निरस्तीकरण होने में देरी हो सकती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021), मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2022) कि कानून में निरस्तीकरण आवेदनों के अनुमोदन के लिए समयसीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि मंत्रालय अलर्ट प्रणाली को लागू करने के सुझाव की जांच करेगा।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त नियम 22(3) स्पष्ट रूप से बताता है कि उचित अधिकारी आवेदन की तिथि, या जैसा भी मामला हो, जारी किए गए किसी भी कारण बताओ नोटिस के जवाब की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी आरईजी-19 में एक आदेश जारी करेगा। ।

#### (ii) अनुमोदन के विभिन्न चरणों की प्रक्रिया प्रवाह वाले मामले

स्वैच्छिक निरस्तीकरण आवेदनों के संबंध में, आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) के विभिन्न चरणों के प्रक्रिया प्रवाह की समीक्षा करने के लिए 01 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए डेटा को निष्कर्षित किया गया था, जिसे न तो अनुमोदित किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है। 13,536 अभिलेखों के डेटा आउटपुट से पता चला कि 10,302 मामलों में, आवेदन की स्थिति अनुमोदन के लिए लंबित दर्शाई गई है। इसके अलावा, जैसा कि आरएफपी और एसआरएस में निर्दिष्ट किया गया है, समय पर सुधार प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारी और उच्च अधिकारियों द्वारा देखने के लिए चरण-वार लंबित और समय-वार लंबित रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी, जिससे एक अप्रभावी निगरानी तंत्र बनता है। 2,883 मामलों में, प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जिन्होंने दर्शाया कि स्वतः अस्वीकृति विकल्प लागू नहीं किया गया है। 297 मामलों में यद्यपि करदाताओं ने प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन फिर भी कर अधिकारी ने 74 दिनों की औसत देरी के बाद भी न तो निरस्तीकरण का अनुमोदन दिया और न ही इसे अस्वीकार किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021), मंत्रालय ने बताया कि निरस्त करने के लिए आवेदन कार्रवाई के लिए लंबित रहता है क्योंकि स्वतः अस्वीकृति कार्यात्मकता विकसित नहीं की गई थी क्योंकि अभ्यर्पण आवेदन के संबंध में अस्वीकृति के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।

**(iii) पूर्वव्यापी तिथि से प्रभावी निरस्तीकरण आदेश परिपत्र अनुदेशों के अनुसार नहीं थे**

81,495 मामलों में, कर अधिकारी द्वारा आवेदन तिथियों के बजाय करदाताओं द्वारा अनुरोध की गई तिथियों से पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था, यह इस तथ्य के बावजूद था कि अनुरोधित तिथियां आवेदन तिथि से पहले थीं। यह सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 20 के साथ पठित परिपत्र संख्या 69/43/2018-जीएसटी के अनुसार नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021), मंत्रालय ने बताया कि वे आवेदन अभ्यर्पण की तिथि से पहले निरस्तीकरण को प्रतिबंधित करने के लिए वैधीकरण प्रदान करने के सुझाव की जांच करेंगे।

**सिफारिश 19: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी प्रणाली में आवश्यक वैधीकरण, अलर्ट और रद्द करने की प्रभावी तिथियाँ तैनात की जाएं। एसआरएस में परिकल्पित एमआईएस रिपोर्ट को एक प्रभावी निगरानी तंत्र को सक्षम करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। यदि आवेदक सात कार्य दिवसों के भीतर एससीएन का जवाब देने में विफल रहता है तो मंत्रालय रद्दीकरण के आवेदन की अस्वीकृति के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट करने पर भी विचार कर सकता है।**

**3.1.2.6 स्वतः निरस्तीकरण कार्यात्मकता का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कई नॉन फाइलर्स के पंजीकरण निरस्त नहीं किए जाते**

दिनांक 20 दिसंबर 2019 की पंजीकरण परामर्श संख्या 38/2019 के संदर्भ में, सितंबर 2019 तक की अवधि के लिए जीएसटीआर -3 बी रिटर्न को

फाइल नहीं करने वाले सभी लोगों के विरुद्ध विस्तृत स्वतः निरस्तीकरण शुरू करने के लिए 19 दिसंबर 2019 को एक नई कार्यात्मकता "विस्तृत स्वतः निरस्तीकरण" विकसित की गई और प्रस्तुतीकरण हेतु परिनियोजित की गई। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 (2) (सी) के अनुसार, उचित अधिकारी द्वारा धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति का, किसी भी पूर्वव्यापी तिथि सहित, जैसा वह उचित समझे, ऐसी तिथि से तो पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है, यदि रिटर्न लगातार छह महीने की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किये गए हैं।

लेखापरीक्षा में सभी नियमित करदाताओं के सीबीआईसी डेटाबेस से 2,70,536 मामलों का अखिल भारतीय डेटा लिया गया (सितंबर 2021), जहां जीएसटीआर 3 बी की रिटर्न जनवरी 2020 से पहले अंतिम बार फाइल की गई थी अथवा जहां जनवरी 2020 से पहले एक भी जीएसटीआर 3 बी की रिटर्न फाइल नहीं की गई है और उन्हें अभी भी सक्रिय पाया गया है। उक्त नियमों के अनुसार, इन सभी पंजीकरणों को 'विस्तृत स्वतः निरस्तीकरण' करके निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा, इस डेटा के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

- (i) 2,70,536 मामलों में से 2,34,486 मामलों में जनवरी 2020 से पहले एक भी जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल नहीं की गई थी और 36,050 मामलों में अंतिम जीएसटीआर -3बी रिटर्न जनवरी 2020 से पहले फाइल की गई थी। ये सभी पंजीकरण 27 सितंबर 2021 तक सक्रिय थे।
- (ii) तमिलनाडु से संबंधित 40 मामलों<sup>21</sup> की यादृच्छिक नमूना जांच में यह पाया गया कि 11 मामलों में करदाता द्वारा पिछली बार फाइल की गई जीएसटीआर -3बी अवधि के बाद की कर अवधि के लिए जीएसटीआर -1 रिटर्न फाइल की जा रही थी। इसलिए जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल किए बिना जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करना, जो

---

<sup>21</sup> चेन्नई ज़ोन की लेखापरीक्षा को प्रदान की हुई एसएसओआईडी के माध्यम से सत्यापित।

जावक कर योग्य आपूर्ति को दर्शाता है, अपात्र आवक कर क्रेडिट को पारित करने की संभावना पर संभावित चिंता पैदा करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021), मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2022) कि जीएसटीएन ने रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के लिए केंद्रीकृत विस्तृत निलंबन को लागू किया है और इसमें लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अवधि शामिल है।

**सिफारिश 20: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फाइल नहीं करने वालों के केंद्रीकृत विस्तृत निलंबन (निरस्तीकरण) की कार्यात्मकता का जीएसटीएन द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।**

**3.1.2.7 जीएसटीआईएन प्राप्त करने के बाद बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं करने वाले करदाताओं की पहचान करने के लिए अलर्ट तंत्र का अभाव**

नियम 21 और 21ए के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 10 और 10ए में प्रावधान है कि पंजीकृत करदाता, पंजीकरण प्रदान करने या सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 के तहत रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करेगा, ऐसा नहीं करने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

01 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 की अवधि के लिए निष्कर्षित नए पंजीकरणों के डेटा से पता चला कि 5.22 लाख पंजीयकों ने अपने बैंक खाते का विवरण फाइल नहीं किया था। हालांकि, कर अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया था या नियम के तहत आवश्यक पंजीकरण को निलंबित नहीं किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन/डैशबोर्ड में कोई अलर्ट तंत्र नहीं था, जिससे कर अधिकारी उन करदाताओं की पहचान कर सकें, जिन्होंने बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और उक्त धारा 29 (2) के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर सकें।

**सिफारिश 21: विभाग को नियम 21 और 21ए के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 10 और 10ए का अनुपालन सुनिश्चित करना**

**चाहिए और निर्धारित समयसीमा के भीतर बैंक खाते का विवरण फाइल नहीं करने की स्थिति में कर अधिकारी के डैशबोर्ड पर अलर्ट कार्यात्मकता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।**

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2022) कि इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा।

### **3.1.2.8 स्वतः निरस्तीकरण कार्यवाही में अपर्याप्त वैधीकरण**

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 22 (1) के अनुसार, जहां उचित अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि धारा 29 के तहत किसी व्यक्ति का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है, वह ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताने की आवश्यकता होगी कि क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाए। धारा 29 (2) (बी) और (सी) में बताया गया है कि यदि धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति ने कर देने की लगातार तीन अवधियों के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है, या संयोजन विक्रेता के अलावा किसी पंजीकृत व्यक्ति ने लगातार छह महीने की अवधि के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है तो पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

नियम 22 (1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस का उत्तर निर्दिष्ट अवधि के भीतर फॉर्म आरईजी-18 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नियम 22 (4) के तहत परंतुक में बताया गया है कि जहां व्यक्ति नोटिस का उत्तर देने के बजाय, सभी लंबित रिटर्न प्रस्तुत करता है और लागू ब्याज और विलंब शुल्क के साथ पूर्ण कर बकाया का भुगतान कर देता है, तो उचित अधिकारी कार्यवाही बंद कर देगा और फॉर्म जीएसटी-आरईजी 20 में एक आदेश पारित करेगा।

एसआरएस - स्वतः निरस्तीकरण नया पंजीकरण वी0.6 में उल्लिखित व्यावसायिक नियम के अनुसार, करदाता को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए बिना पंजीकरण निरस्त नहीं किया जा सकता।

करदाता को सूचित किया जाएगा और कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए सात सामान्य कार्य दिवस प्रदान किए जाएंगे। निर्धारित समय के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, अधिकारी के पास केवल पंजीकरण निरस्त करने का विकल्प होता है।

पंजीकरण को स्वतः निरस्त करने की कार्यात्मकता 18 अगस्त 2018 (स्वतः निरस्तीकरण पर एडवाइजरी) से प्रस्तुतीकरण में है। एक सुविधा उपाय के रूप में, परिवर्तन अनुरोध के माध्यम से एक सुविधा विकसित की गई थी, जिसमें अधिकारी एक बार में 20 करदाताओं के लिए विस्तृत स्वतः निरस्तीकरण कर सकता है और कार्यात्मकता को 19 दिसंबर 2020 (एडवाइजरी संख्या 38/2019) को प्रस्तुतीकरण हेतु परिनियोजित किया गया था। अगस्त 2019 की कर अवधि तक सभी जीएसटीआर 3 बी फाइल न करने वालों को स्वतः संज्ञान लेते हुए विस्तृत रूप से नोटिस जारी करने के लिए यह एकबारगी प्रक्रिया थी। एसआरएस (वी.06) पर कुछ सुधारों के साथ प्रस्तुतीकरण में वास्तविक कार्यात्मकता के अनुसार साइन ऑफ (जुलाई 2020) किया गया था। स्वतः निरस्तीकरण के लिए कार्यप्रवाह निम्न है:

- (i) वैयक्तिक जीएसटीआईएन स्वतः निरस्तीकरण शुरू करना: कर अधिकारी पंजीकरण पर नेविगेट करेगा और सक्रिय पंजीकरण के तहत, अधिकारी निरस्तीकरण शुरू करने के लिए विशेष जीएसटीआईएन का चयन करेगा।
- (ii) विस्तृत रूप से जीएसटीआईएन स्वतः निरस्तीकरण शुरू करना: कर अधिकारी "फाइल न करने वालों को देखें" पर नेविगेट करेंगे, जिसमें 'जीएसटीआर -3 ए/स्वतः संज्ञान' नामक टॉगल बटन के क्लिक पर उन करदाताओं की सूची प्रस्तुत की जाएगी जिनके विरुद्ध जीएसटीआर -3 ए नोटिस जारी किए गए हैं और जिनमें से पंजीकरण निरस्त करने के लिए दायीं करदाताओं का चयन किया जा सकता है। एक बार करदाताओं (एक बार में अधिकतम 20) का निरस्तीकरण के लिए चयन किए जाने पर "निरस्तीकरण शुरू करें" बटन का उपयोग विस्तृत रूप से स्वतः निरस्तीकरण शुरू करने के लिए किया जा सकता है।

- (iii) एक बार निरस्तीकरण शुरू हो जाने के बाद (वैयक्तिक और विस्तृत दोनों के लिए), संबंधित रिकार्ड को कारण बताओ नोटिस के लिए जीएसटीआईएन के उत्तर के बाद "प्रतिक्रिया प्रतीक्षित" चरण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे रिकार्ड को "प्रतिक्रिया प्रश्न/एससीएन" चरण में ले जाया जाएगा जिसमें अधिकारी पंजीकरण निरस्त/कार्यवाही बंद कर सकता है।
- (iv) यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित रिकार्ड "प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई" चरण में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें अधिकारी केवल "पंजीकरण निरस्त" कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जहां करदाता को रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए आरईजी-17 में एससीएन जारी किया गया है और वह देय रिटर्न फाइल करता है और नियम 22 (4) के परंतुक के तहत प्रावधान के अनुसार कारण बताओ नोटिस (एससीएन) का उत्तर देने के बजाय करों का पूरा भुगतान करता है, तो सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में कर अधिकारी को सचेत करने का कोई प्रावधान नहीं है कि रिटर्न फाइल किए गए हैं। रिटर्न और पंजीकरण मॉड्यूल के बीच लिंक की अनुपस्थिति के कारण, एक उपयुक्त अधिसूचना संदेश कि 'एससीएन के उत्तर में रिटर्न फाइल किया गया है', यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध नहीं है कि वह नियम 22 (4) के तहत अपेक्षित रिटर्न फाइल करने और करों/ब्याज/कर के भुगतान को ध्यान में रखे बिना निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं करेगा।

इसके अलावा, कर अधिकारियों के डैशबोर्ड और हेल्पडेस्क टिकटों के वाकथू से पता चला कि जहां भी एससीएन जारी किया गया है, समय सीमा के संबंध में वैधीकरण प्रभावी नहीं है। सीबीआईसी डेटाबेस से निष्कर्षित डेटा से यह भी स्पष्ट है कि 10,246 मामलों में, यहां तक कि जहां आरईजी -18 में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और सात कार्य दिवसों के भीतर रिटर्न फाइल नहीं की गई हैं और एससीएन के उत्तर 33 से 1003 दिनों तक प्रतीक्षित थे, वहां कर अधिकारी का डैशबोर्ड स्थिति को 'प्रतिक्रिया प्रतीक्षित' के रूप में दर्शाता रहा, जबकि तब ऐसे विलंबित मामलों में पंजीकरण को कर अधिकारियों द्वारा निरस्त कर दिया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने पैरा स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2022) कि (i) करदाताओं को नोटिस का उत्तर देने का अवसर प्रदान किया जाता है और इसलिए यदि उन्होंने रिटर्न फाइल की है, तो यह बहुत अच्छी तरह से उचित अधिकारी को सूचित किया जा सकता है और (ii) लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे के लिए कि कुछ मामलों में जहां आरईजी -18 में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, कर अधिकारी का डैशबोर्ड 'प्रतिक्रिया प्रतीक्षित' के रूप में दर्शाना जारी रखता है, मामले की जांच की गई और यह देखा गया कि विसंगति बीपीएम त्रुटि के कारण हुई है और इसे प्राथमिकता पर सुधारा गया है।

**सिफारिश 22: विभाग को पंजीकरण और रिटर्न मॉड्यूल के बीच एक लिंक प्रदान करना चाहिए ताकि रिटर्न फाइल करने और आरईजी -17 में नोटिस के उत्तर में करों का भुगतान करने पर कर अधिकारी को सचेत किया जा सके। सीजीएसटी नियमों के प्रावधानों के अनुसार समयसीमा के संबंध में प्रभावी वैधीकरण/अलर्ट प्रदान करने के लिए भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।**

### 3.1.2.9 किसी भी क्षेत्राधिकार प्राधिकरण में करदाताओं के पंजीकरण (जीएसटीआईएन) को मानचित्रित न करना

आरएफपी (खंड 1.2 (सी) (iv)) के अनुसार, पंजीकरण के लिए आवेदन स्कैन किए गए संलग्न दस्तावेजों के साथ आवेदक द्वारा जीएसटीएन पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और जीएसटीएन द्वारा पैन, सीआईएन, डीआईएन आदि के वैधीकरण के बाद, इसे जीएसटीएन प्रणाली द्वारा सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन को भेजा जाता है। इसके बाद, इसे जीएसटी कानून के तहत परिभाषित सीबीआईसी के क्षेत्राधिकार के उचित अधिकारी के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया जाता है। जीएसटीएन प्रणाली, पंजीकरण आवेदन में आवेदक द्वारा बताए गए व्यवसाय के मुख्य स्थान और क्षेत्राधिकार मास्टर और आवंटन तर्क के आधार पर सीबीआईसी द्वारा प्रशासित उद्ग्रहणों के लिए आवेदक के अनंतिम क्षेत्राधिकार का निर्धारण करती है।

नियमित और संयोजन करदाताओं के संबंध में सीबीआईसी डेटाबेस से 5,004 मामलों के डेटा निष्कर्षण से पता चला कि हालांकि, इन मामलों में जीएसटीआईएन सृजित किए गए थे, लेकिन इन्हें किसी भी क्षेत्राधिकार को आवंटित नहीं किया गया था। 5,004 मामलों में से 4,933 मामलों को डीम्ड अनुमोदित माना गया और शेष 71 मामलों को अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया।

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन पोर्टल के साथ चेन्नई जोन से संबंधित 20 ऐसे जीएसटीआईएन का यादृच्छिक रूप से सत्यापन किया और पाया कि जीएसटीआईएन सभी प्रासंगिक क्षेत्राधिकार विवरणों के साथ जीएसटीएन पोर्टल में उपलब्ध थे और सभी 20 मामलों के लिए, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 बी रिटर्न नियमित रूप से फाइल किए जा रहे हैं। हालांकि, इन 20 जीएसटीआईएन<sup>22</sup> को आज तक किसी भी क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में चित्रित (मैप) नहीं किया गया है।

जीएसटीएन पोर्टल में क्षेत्राधिकार विवरण होने के बावजूद सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में क्षेत्राधिकार प्राधिकरण के साथ जीएसटीआईएन का गैर-चित्रण का अर्थ है कि सीबीआईसी आईटी एप्लीकेशन मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, इस प्रकार उचित कर प्रशासन के लिए क्षेत्राधिकार प्राधिकरण के साथ जीएसटीआईएन के मानचित्रण को बाधित करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021), मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2022) कि जब स्वतः आवंटन लॉजिक क्षेत्राधिकार आवंटित करने में असमर्थ रहता है, तो जीएसटीआईएन को जारी किए गए व्यापार नोटिसों के आधार पर हस्त्य रूप से क्षेत्राधिकार आवंटित करने के लिए क्षेत्र (ज़ोन) के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र को सौंपा जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा संदर्भित जीएसटीआईएन का सत्यापन किया गया और यह पाया गया कि इन सभी जीएसटीआईएन को क्षेत्राधिकार के हस्त्य रूप से आवंटन के लिए सीपीसी अधिकारियों को सौंपा गया था।

---

<sup>22</sup> चेन्नई जोन की लेखापरीक्षा को प्रदान की हुई एसएसओआईडी के माध्यम से सत्यापित।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ जीएसटीआईएन का विवरण अभी भी एप्लीकेशन के कुछ मॉड्यूल में उपलब्ध नहीं है।

**सिफारिश 23: विभाग को मामलों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करनी चाहिए कि जीएसटीएन पोर्टल में उपलब्ध क्षेत्राधिकारों के साथ सभी मॉड्यूलों में जीएसटीआईएन को सही ढंग से चित्रित (मैप) किया गया है।**

### 3.1.3 अधिनियम में पर्याप्त प्रावधानों के बिना जीएसटी कर वृत्तिक (जीएसटीपी) संशोधन के संबंध में सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की रूप-रेखा

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 19 पंजीकरण के समय पर प्रस्तुत या समय-समय पर यथा संशोधित किसी भी विवरण में संशोधनों का प्रावधान करता है। निम्नलिखित प्रपत्रों में आवेदन करके पंजीकरण प्राप्त करने और संशोधन की मांग करने वाले श्रेणी के व्यक्तियों को इस तरह के परिवर्तन के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी आरईजी -14 में किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित करना चाहिए:

- फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 (सामान्य करदाता)
- फॉर्म जीएसटी आरईजी-07 (टीडीएस टीसीएस)
- फॉर्म जीएसटी आरईजी -09 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति) अथवा
- फॉर्म जीएसटी आरईजी -10 (ओआईडीएआर)

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 19 के तहत परंतुक में बताया गया है कि यदि परिवर्तन (i) व्यवसाय के कानूनी नाम; (ii) व्यवसाय के मुख्य स्थान या व्यवसाय का किसी अतिरिक्त स्थान (ओं) का पता; या (iii) व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार भागीदारों या निदेशकों में वृद्धि, इन्हें हटाने या सेवानिवृत्ति, कर्ता, प्रबंधन समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष, व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार, से संबंधित है तो फिर उचित अधिकारी को उचित सत्यापन के बाद, फॉर्म जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्राप्त होने की तिथि से

पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर संशोधन को अनुमोदन देना हैं और फॉर्म जीएसटी आरईजी -15 में एक आदेश जारी करना है। जहां परिवर्तन ऊपर निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य जानकारी से संबंधित है, तो सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन जमा करने पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र संशोधित हो जाएगा।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 48 में अनुमोदित जीएसटी वृत्तियों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र व्यक्ति को प्राधिकार प्रदान करने का प्रावधान है। एक पंजीकृत व्यक्ति एक अनुमोदित जीएसटी वृत्तिक को अपनी ओर से सरकार को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकता है। माल एवं सेवा कर वृत्तियों के अनुमोदन का तरीका, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और दायित्व, हटाने का तरीका और उनकी कार्यप्रणाली के लिए प्रासंगिक अन्य शर्तें सीजीएसटी नियमावली के नियम 83 में निर्धारित की गई हैं। जीएसटी वृत्तिक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने, नामांकन प्रमाण पत्र, अयोग्यता के लिए कारण बताओ नोटिस, नामांकन के आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश, प्राधिकार पत्र और प्राधिकरण वापस लेने के लिए मानकीकृत प्रारूप, जीएसटी पीसीटी -1 से जीएसटी पीसीटी -5 निर्धारित किए गए हैं। सीजीएसटी नियमों में पीसीटी-01 में दिए गए विवरणों में संशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं है और न ही इनमें इस तरह के संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए कोई फॉर्म निर्धारित किया है।

परिवर्तन सलाहकार बोर्ड (सीएबी) की बैठक (06/08/2019) के कार्यवृत्त और परिवर्तन अनुरोध के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए संबंधित पत्राचार की समीक्षा से पता चला कि विभाग ने जीएसटीपी के गैर-मुख्य संशोधन और मुख्य परिनियोजित संशोधन के संबंध में परिवर्तन आदेश को अनुमोदन दे दिया था और इसे क्रमशः जून 2020 और जून 2021 में परिनियोजित किया गया था। सीएबी के कार्यवृत्त में पीएमयू की पुनरीक्षण टिप्पणियों की जांच करते हुए, यह बताया गया था कि जब पंजीकरण संख्या प्राप्त करते समय प्रस्तुत आवेदन अर्थात् पीसीटी-01 से संबंधित परिवर्तन होते हैं, तो जीएसटी वृत्तिक आवश्यक समर्थित दस्तावेजों के साथ फॉर्म आरईजी -14 के माध्यम से मुख्य संशोधन आवेदन प्रस्तुत करता है और सामान्य पोर्टल पर

दर्ज ऐसे संशोधन आवेदनों को बैकएंड पर एपीआई के माध्यम से लिया जाता है और संबंधित अधिकारी द्वारा उचित माने जाने पर अनुमोदन/अस्वीकृत करने के लिए आवश्यक सत्यापन और कार्रवाई के लिए नामित रेंज में भेज दिया जाता है। इस संबंध में एसआरएस तैयार किया जा रहा है लेकिन इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, लेखापरीक्षा ने पाया कि फॉर्म पीसीटी -01 में प्रस्तुत जीएसटीपी नामांकन डेटा के संबंध में विवरण में संशोधन के नियम जीएसटी अधिनियम/नियमों में प्रदान नहीं किए गए हैं और कर अधिकारी के पास मुख्य संशोधनों को अनुमोदन देने के लिए औपचारिक अधिदेश नहीं है। फॉर्म आरईजी-14 एक निर्धारित प्रपत्र है जिसे केवल उन्हीं श्रेणियों के करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जो आरईजी-01, आरईजी-07, आरईजी-09 और आरईजी-10 में दिए गए ब्यौरे में परिवर्तन करना चाहते हैं। जीएसटी कर वृत्तिक को फॉर्म आरईजी -14 में विवरण में संशोधन के लिए आवेदन करने की अनुमति देना, जो इस तरह के संशोधनों के लिए प्रासंगिक नहीं है, तार्किक प्रतीत नहीं होता ।

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021) कि जीएसटी वृत्तिक (जीएसटीपी) के नामांकन में संशोधन के लिए किसी भी प्रावधान या प्रक्रियाओं के अभाव में, जीएसटीएन द्वारा जारी एपीआई का उपभोग किया गया था और उपयोगकर्ताओं को इसे उपलब्ध कराने की तात्कालिकता के कारण, सामान्य पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म आरईजी -14 का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया गया है। कार्यात्मकता सामान्य पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म आरईजी -14 के अनुसार विकसित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2019 में जीएसटीएन द्वारा एपीआई जारी किया गया था, लेकिन एसआरएस तैयार किए बिना कार्यात्मकता जून 2021 में लागू की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021), मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2022) कि यह सुविधा केवल एक सुविधाजनक/सक्षम कार्यविधि है जिसका कोई राजस्व निहितार्थ नहीं है और जैसा कि जीएसटीएन ने पहले ही इस सुविधा को शुरू कर दिया है, इसे सीबीआईसी द्वारा लागू किया गया है।

**सिफारिश 24: विभाग को जीएसटीपी संशोधनों की प्रक्रिया के लिए जीएसटी परिषद/जीएसटीएन विधि समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।**

3.1.4 आरएफपी में आवश्यकताओं को एसआरएस के हस्ताक्षरित (साइन ऑफ) संस्करण में पर्याप्त रूप से नहीं ले जाया गया था और परिवर्तन अनुरोध के माध्यम से विकसित कुछ कार्यात्मकताओं में अपर्याप्तताओं को पाया गया था जो शुरू में आरएफपी के तहत मूल कार्य का भाग थे

आरएफपी (खंड 1.2 (डी) (iii)) के अनुसार, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन उन व्यक्तियों/संस्थाओं के पैन-आधारित डेटा को बनाए रखेगा, जिन्हें पहले ब्लैक-लिस्ट किया गया था या जिनके आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे या पंजीकरण निरस्त कर दिए गए थे। जब सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन द्वारा इस तरह के पैन के साथ कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो यह जानकारी आवेदन को संसाधित करते समय अलर्ट के रूप में क्षेत्राधिकार के उचित अधिकारी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

परिवर्तन आदेश के संबंध में प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि परिवर्तन आदेश केवल तभी शुरू किया जाएगा जब (i) खरीदार, विक्रेता को लिखित रूप में निर्देश दे कि वह समझौते के तहत कवर किए गए कार्यक्षेत्र में किसी संवर्धन को शामिल करें या समझौते के तहत कार्यक्षेत्र के किसी हिस्से को हटा दें।

एसआरएस (वी 1.3) ने 'पूर्व पंजीकरण देखें' के लिए प्रक्रिया प्रवाह प्रदान नहीं किया। हालांकि, एसआरएस के अनुरेखणीय मैट्रिक्स में उल्लेख किया गया कि उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन आरईजी\_अनुमोदन\_01 में किया गया है। हालांकि, उसी पैन के साथ "पूर्व पंजीकरण देखें" की कार्यात्मकता को जुलाई 2019 (पैन वैधीकरण) में ₹13.72 लाख की लागत से परिवर्तन अनुरोध 177 के रूप में विकसित किया गया था और कार्यात्मकता को 12 नवंबर 2019 से प्रस्तुतीकरण हेतु परिणियोजित किया गया था (एडवाइज़री: 34, दिनांक 04 दिसंबर 2019)।

आरएफपी के कार्यक्षेत्र में इसका उल्लेख होने के बावजूद ₹13.72 लाख की अतिरिक्त लागत पर परिवर्तन अनुरोध (दिसंबर 2019) के रूप में कार्यात्मकता का विलंबित विकास उचित नहीं है।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2022) कि विभाग उक्त राशि की वसूली के लिए मांग नोटिस(ओं) को जारी करने की प्रक्रिया में है।

नए पंजीकरण जहां पूर्व निरस्त पंजीकरण मौजूद था, आवेदन की अनुमोदन प्रक्रिया के वाकथू के आधार पर, और पैन सत्यापन पर एसआरएस दस्तावेज के अवलोकन में भी, कार्यात्मकता में निम्नलिखित अपर्याप्तताएं देखी गईं:

- (i) एसआरएस में अनुमोदन प्रक्रिया प्रवाह यह प्रावधान करता है कि निरस्त किए गए पंजीकरणों के मामले में, पूर्व पंजीकरणों के रिटर्न फाइल किए गए विवरणों को सत्यापित करने के लिए "रिटर्न देखें" लिंक को सक्षम किया जाना चाहिए। हालांकि, केंद्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (सीपीसी) के वाकथू में अनुमोदन प्रक्रिया का अवलोकन करते समय, कर अधिकारी के लिए 'रिटर्न देखें' टैब सक्षम नहीं है। सीबीआईसी डेटाबेस (एसएटीक्यू\_न्यूआरईजी\_जीक्यू\_10) से निष्कर्षित एक ही पैन के लिए मौजूद निष्क्रिय और सक्रिय पंजीकरणों हेतु जीएसटीएन पोर्टल में यादृच्छिक जांच से पता चला कि 9 मामलों में करदाताओं ने निरस्त किए गए जीएसटीआईएन (रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए स्वतः निरस्तीकरण) के संबंध में देयताओं को असंपादित रखते हुए कारोबार जारी रखने के लिए एक नया पंजीकरण प्राप्त किया था। इस तरह के नए आवेदन किए गए होंगे क्योंकि हो सकता है कि व्यक्ति ने अपेक्षित रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया हो और पुराने/निरस्त किए गए पंजीकरण के तहत कवर की गई कर अवधि के लिए कर का भुगतान नहीं किया हो। कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि निष्क्रिय जीएसटीआईएन ने जीएसटीआर-1 फाइल किया है लेकिन जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया है। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी की कर फाइल करने की अवधि में विसंगतियों की जानकारी कर अधिकारी को अलर्ट के रूप में उपलब्ध नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2022) कि 'रिटर्न देखें टैब' के तहत रिटर्न देखने की सुविधा उचित परीक्षण के बाद परिनियोजित की गई थी और यह कार्यशील थी। हालांकि, टैब के कार्यकारी न होने को सुधार के लिए लिया जा रहा था। जहां तक जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच विसंगति का संबंध है, अलर्ट की संभावना की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।

- (ii) "रिटर्न देखें" टैब, जो पूर्व पंजीकरणों के रिटर्न फाइल किए गए विवरण उपलब्ध कराता है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके आधार पर कर अधिकारी पंजीकरण के संबंध में नए आवेदन को मंजूरी देता है या अस्वीकार करता है जहां रिटर्न फाइल न करने के लिए पूर्व पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाता है। यह उल्लेख करना उचित है कि क्षेत्राधिकार के उचित अधिकारी, जिसने पंजीकरण रद्द किया हो, वह उस कर अधिकारी से भिन्न हो सकते हैं, जो समान पैन के साथ नए पंजीकरण को मंजूरी दे रहा है। अतः, अनुमोदन अधिकारी को पूरा रिटर्न फाइलिंग डेटा प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह नए पंजीकरण आवेदन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने या पूछताछ करने का निर्णय लेने में सक्षम रहे। रिटर्न और पंजीकरण मॉड्यूल का इस प्रकार संयोजन किया जाना चाहिए कि जीएसटीआर-1 फाइलिंग कर अवधि और फाइलिंग दिनांक के साथ साथ जीएसटीआर 3 बी फाइलिंग विवरण को एक ही पैन पर समूहीकृत किया जाए और ब्लैक लिस्टिंग विवरण एक बटन के क्लिक पर देखने के लिए उपलब्ध हो ताकि अनुमोदन अधिकारी (सीपीसी अधिकारी) एक नए पंजीकरण आवेदन को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने से पहले एक सूचित निर्णय ले सके।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि 'रिटर्न देखें' टैब में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा ताकि कर अधिकारी पूर्ण रिटर्न

फाइलिंग डेटा देख सके। लेखापरीक्षा के परामर्श के अनुसार, रिटर्न और पंजीकरण मॉड्यूल को जोड़ने की जांच की जाएगी।

- (iii) 'व्यू अर्लीयर रजिस्ट्रेशन' के अंतर्गत दी गई जानकारी रद्द पंजीकरण तक सीमित है। यह एप्लीकेशन चूककर्ता जीएसटीआईएन के प्रति रद्दीकरण की कार्यवाही के आरंभ होने और सीजीएसटी नियमावली के नियम 21 ए के अंतर्गत निलंबन, पर स्वीकृति देने वाले कर अधिकारी को सतर्क (अलर्ट) नहीं करता और वही पैन धारक नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। सक्रिय और निष्क्रिय मामलों की यादृच्छिक जांच करने पर, यह देखा गया कि निलंबित स्थिति वाले करदाता द्वारा नए पंजीकरण के लिए आवेदन किया और इसे मंजूरी भी मिल गई।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि 'व्यू अर्लीयर रजिस्ट्रेशन' को 2019 के दौरान प्रस्तुतीकरण के लिए परिनियोजित किया गया था, जबकि जीएसटीआईएन के निलंबन को नवंबर 2020 के दौरान जीएसटीएन द्वारा कार्यान्वित किया गया था। निलंबित स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक आशोधन किए जाएंगे।

- (iv) जहां राज्य कर प्राधिकरण द्वारा रद्दीकरण किया गया है, वहाँ कर अधिकारी रद्द करने के उन कारणों का पता नहीं लगा सकता। राज्य कर प्राधिकारियों के साथ एकीकरण की कमी के कारण रिटर्न दाखिल न करने वालों/काली सूची के विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं होते, जिससे प्रभावी निगरानी तंत्र प्रभावित होता है।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि इस मामले पर एकीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

- (v) आरएफपी (खंड 1.2 (डी) (iv)) यह निर्धारित करता है कि एप्लीकेशन द्वारा विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं में जोखिम पैरामीटर के रूप में उपयोग करने के लिए आपराधिक मामलों के लिए पैन-आधारित डेटा

बनाया जाना चाहिए। आरएफपी के अंतर्गत संविदागत बाध्यता होने के बावजूद भी, यह कार्यात्मकता विकसित नहीं की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) अन्य अत्यावश्यक कार्यात्मकताओं की प्राथमिकता के साथ-साथ डीएसआर मॉड्यूल के तैयार न होने के कारण इस कार्यात्मकता पर कार्य नहीं किया जा सका। इस सुविधा की प्रासंगिकता की जांच की जाएगी और यदि आवश्यक पाया गया तो इसे विकसित किया जाएगा।

- (vi) विभाग ने उचित निर्णय लेने में कर अधिकारी की सहायता के लिए मॉड्यूल और अंतर्निहित वैधीकरण के बीच एकीकरण विकसित नहीं किया। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि आगे जाकर इसकी जांच की जाएगी और इस पर विचार किया जाएगा।

लेखापरीक्षा आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या एनआरटीपी द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम कर की प्रक्रिया की भी जांच नहीं कर सकी और क्या वह अनुमानित कर देनदारी के बराबर है, क्या प्रधान व्यापार स्थल में परिवर्तन हुआ है; और परीक्षण वातावरण के प्रावधान न होने के कारण पंजीकरण के त्रुटिपूर्ण रद्दीकरण की जांच नहीं कर सकी।

### 3.2 रिटर्न मॉड्यूल

रिटर्न एक निर्धारित अवधि के दौरान कर योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए व्यावसायिक क्रियाकलापों से संबंधित निर्दिष्ट जानकारी का एक विवरण है। एक कर योग्य व्यक्ति के कुछ कानूनी दायित्व होते हैं जैसे कि :

- निर्यात सहित वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, माल/सेवाओं का विवरण, मूल्य और कर की दर आदि का विवरण प्रस्तुत करके रिटर्न में दी गई अवधि के लिए अपनी कर देनदारी घोषित करना,
- प्राप्त की गई इनपुट और इनपुट सेवा तथा इन इनपुट और इनपुट सेवाओं पर लिए गए क्रेडिट का विवरण प्रस्तुत करना,
- किए गए करों के भुगतान के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना, और

- सही जानकारी प्रस्तुत कर, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण रिटर्न दाखिल करना ।

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर निर्धारित कर अवधि के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। रिटर्न की अवधि के दौरान कोई व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं होने पर भी रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए अर्थात् रिटर्न अवधि के दौरान 'शून्य' रिटर्न। पूर्ण रूप से भुगतान की गई कर देनदारी के साथ भरी गई रिटर्न को जीएसटीएन द्वारा वैध रिटर्न के रूप में स्वीकार किया जाता है और संवीक्षा के लिए कर अधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है। विक्रेता/क्रेता द्वारा दाखिल रिटर्न के साथ अनुलग्नकों को जीएसटीएन प्रणाली द्वारा सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन को उचित अधिकारियों द्वारा इस संबंध में सीबीआईसी द्वारा निर्धारित व्यावसायिक नियमों के अनुसार आगे के प्रसंस्करण हेतु भेजा जाता है।

**तालिका 3.2 - संक्षेपित लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स**

उप-उद्देश्य	परीक्षित/अपरीक्षित	सफल/असफल/ सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
रिटर्न फाइलिंग प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में निगरानी कार्यविधि की समीक्षा करना	परीक्षित (12)	सफल (9)	रिटर्न फाइलिंग समयसीमा, अमान्य रिटर्न की पहचान, रिटर्न फाइल न करने वालों के मामले, नॉन-फाइलर रिपोर्ट तैयार करते समय विस्तारित डेटा पर विचार, डेटा स्थिरता, रिटर्न फाइलिंग मामले	-
		असफल (3)	जीएसटीआर फॉर्म की समय पर तैनाती, रिटर्न की सही फाइलिंग, फ्लैगिंग तंत्र	3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3
	अपरीक्षित (1)	सीमा प्रतिबन्ध (1)	कर अधिकारी के लिए सही और पूर्ण रिटर्न डेटा की उपलब्धता	-
कर भुगतान की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए	अपरीक्षित (2)	सीमा प्रतिबन्ध (2)	ब्याज गणना, विलंब शुल्क गणना	-

उप-उद्देश्य	परीक्षित/अपरीक्षित	सफल/असफल/सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
मॉड्यूल के बीच इंटरफेस के कार्य की समीक्षा करने हेतु	अपरीक्षित (3)	सीमा प्रतिबन्ध (3)	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी फाइलिंग के बीच तुलनात्मक तंत्र, प्रतिदाय के संदर्भ में फ्लैग तंत्र, परीक्षण योजना के अनुसार प्रणाली परीक्षण और एकीकरण परीक्षण	-
मॉड्यूल के कार्यान्वयन की समय सीमा की समीक्षा करना	अपरीक्षित (2)	सीमा प्रतिबन्ध (2)	रिटर्न के संदर्भ में एसआरएस और आरएफपी की समयसीमा का कार्यान्वयन, लाइव वातावरण में रिटर्न मॉड्यूल का निर्धारण और संवीक्षा, जोखिम निर्धारण इंजन का कार्यान्वयन	3.2.2

रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा का अनुपथन, अवैध रिटर्न की पहचान करने, रिटर्न की आवधिकता का सत्यापन, भरी न गई रिटर्न के लिए लंबित कार्य को अद्यतित करना, जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने वाले सामान्य करदाताओं के लिए फाइल न करने वालों की रिपोर्ट को पॉप्युलेट करना आदि जैसी कार्यात्मकताएं क्रियाशील और व्यवस्थित पाई गईं। तथापि, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हुईं:

### 3.2.1 रिटर्न मॉड्यूल में कमियाँ

#### 3.2.1.1 जीएसटीआर-4 रिटर्न को परिनियोजित नहीं किया जाना

बोर्ड ने 23 अप्रैल 2019 की अधिसूचना संख्या 20/2019-केंद्रीय कर के माध्यम से सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 62 के पहले परंतुक में निम्नलिखित आशोधन प्रस्तुत किए:

- फॉर्म जीएसटीआर सीएमपी -08 को हर तिमाही या, जैसा भी मामला हो, उसके भाग के लिए एक विवरण, जिसमें स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान का विवरण शामिल था, ऐसी तिमाही के बाद के महीने के 18 वें दिन तक प्रस्तुत करने के लिए शुरू किया गया था;

- धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए एक नया फॉर्म जीएसटीआर-4, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए या, जैसा भी मामला हो, उसके भाग के लिए ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के बाद 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करने के लिए शुरू किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि नए फॉर्म जीएसटीआर -4 को अभी भी प्रस्तुतिकरण में परिनियोजित नहीं किया गया, यद्यपि बोर्ड ने अप्रैल 2019 में इसे अधिसूचित किया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि जीएसटीआर-4 वार्षिक रिटर्न फॉर्म आरएफपी का हिस्सा नहीं था और इसे अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। अतः, वेंडर की तरफ संसाधन की कमी के कारण कार्यात्मकता के विकास में विलंब हुआ।

मंत्रालय ने इसके अतिरिक्त कहा कि एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में विभिन्न कार्यात्मकताओं के विकास में विलंब को दूर करने के लिए, 17 फरवरी 2022 को विक्रेता के साथ मौजूदा अनुबंध में एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अनुसार सभी लंबित कार्यों को दक्ष प्रणाली के अंतर्गत टी एंड एम (समय और सामग्री) आधार पर किया जाएगा। तदनुसार, जीएसटीआर -4 वार्षिक रिटर्न का विकास और परिनियोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और जिसके अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है ।

**सिफारिश 25: विभाग को संशोधित फॉर्म जीएसटीआर-4 की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।**

### 3.2.1.2 'पंजीकरण के प्रकार' के साथ 'भरी गई रिटर्न के प्रकार' की गलत मैपिंग

सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 61 (1) के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करेगा:-

- आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 14 के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति (व्यक्ति जो कर योग्य क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्ता का प्रतिनिधि है)
- इनपुट सेवा वितरक
- अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
- धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति (कंपोजिशन लेवी स्कीम)
- धारा 51 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति (स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्ति)
- धारा 52 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति (ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा स्रोत पर कर संग्रह)।

इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 62 में प्रावधान है कि धारा 10 के अंतर्गत कर भुगतान करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को हर तिमाही में फॉर्म जीएसटी सीएमपी -08 में स्व-निर्धारित कर के भुगतान का विवरण प्रस्तुत करना होगा और प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए फॉर्म जीएसटीआर -4 में एक रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी।

चेन्नई में तीन रेंज से संबंधित सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के रिटर्न मॉड्यूल ('व्यू रिटर्न') में एक यादृच्छिक जांच से पता चला कि आठ मामलों<sup>23</sup> में, जिन लोगों ने कंपोजिशन का विकल्प चुना है, वे जीएसटीआर -3बी दाखिल कर रहे थे। जब जीएसटीएन पोर्टल में विवरण के साथ क्रॉस सत्यापित किया गया तो यह पाया गया कि चार मामलों में करदाता के प्रकार में बेमलता थी क्योंकि उन्हें जीएसटीएन में सामान्य करदाताओं के रूप में दर्शाया गया था। रिटर्न मॉड्यूल में 'पंजीकरण के प्रकार' के साथ 'प्रस्तुत रिटर्न के प्रकार' का अशुद्ध प्रतिचित्रण सीबीआईसी डेटाबेस की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

---

<sup>23</sup> चेन्नई जोन की लेखापरीक्षा को प्रदान की हुई एसएसओआईडी के माध्यम से सत्यापित

**सिफारिश 26: विभाग को सीबीआईसी में डेटा को जीएसटीएन के आंकड़ों के साथ मिलाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और दिए हुए पंजीकरण के साथ सही रिटर्न प्रकार को मैप करना चाहिए।**

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने सिफारिश (अगस्त 2022) को स्वीकार कर लिया और कहा कि कुछ मामलों में, करदाता के प्रकार को सीबीआईसी बैकएंड पंजीकरण डेटाबेस में "कम्पोज़िशन" के रूप में त्रुटिपूर्ण रूप से दिखाया गया है। जीएसटीएन और सीबीआईसी के बीच पंजीकरण डेटाबेस के संबंध में एक समाधान प्रक्रिया आरंभ की गई है और सीबीआईसी डेटाबेस में इसे सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

### **3.2.1.3 'गैर-फाइलर सूची देखें' कार्यात्मकता कंपोज़िशन फाइल न करने वालों के लिए सक्षम नहीं**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 46 के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 68 के अनुसार धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले पंजीकृत व्यक्ति (इसके बाद "चूककर्ता" के रूप में संदर्भित) को फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी करना आवश्यक है, उसे पंद्रह दिनों के भीतर इस तरह के रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, धारा 62 में उन पंजीकृत व्यक्तियों के रिटर्न दाखिल न करने वालों के निर्धारण का प्रावधान है, जो धारा 46 के अंतर्गत नोटिस मिलने के बाद भी धारा 39 या धारा 45 के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं।

परामर्शी 28/2019, दिनांक 18 नवंबर 2019, ने एक नई कार्यात्मकता 'गैर-फाइलर देखें' की शुरुआत की, जिसमें रेंज अधिकारी रिटर्न न भरने वालों को नोटिस जारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च संरचना के अधिकारी रिटर्न न भरने वालों की सूची देख सकते हैं और ऐसे करदाताओं को जीएसटीआर -3 ए नोटिस भेजे जाते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 'गैर-फाइलर देखें' कार्यात्मकता केवल जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर-8 रिटर्न दाखिल न करने वालों

के लिए सक्षम थी। इस कार्यात्मकता में कंपोजिशन करदाताओं द्वारा फाइल किए गए तिमाही रिटर्न जैसे जीएसटीआर-4 (मार्च 2019 तक) और सीएमपी-08 (अप्रैल 2019 से) रिटर्न के गैर-फाइलर्स को देखने के लिए प्रावधान नहीं था। यहां तक कि बल्क स्वतः संज्ञान से रद्द करने की कार्यात्मकता भी केवल जीएसटीआर-3B रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए लागू की गई थी और जीएसटीआर-4 और सीएमपी-08 रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए नहीं। नतीजतन, रेंज अधिकारियों ने धारा 29(2)(बी) के तहत जरूरी जीएसटीआर-4 और सीएमपी-08 रिटर्न दाखिल न करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं की है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने सिफारिश (अगस्त 2022) को स्वीकार कर लिया और कहा कि यह जीएसटीएन द्वारा फ्रंट-एंड में, रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले पंजीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटीआर -3 ए में नोटिस जारी करना कार्यात्मकता के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण था। डीजी (सिस्टम्स), चेन्नई द्वारा एक अंतरिम उपाय के रूप में सीबीआईसी बैंकएंड के माध्यम से ईमेल के माध्यम से क्षेत्राधिकार अधिकारियों द्वारा करदाता को सीधे नोटिस जारी करने के लिए डीजी (सिस्टम्स), चेन्नई द्वारा 'गैर-फाइलर देखें' की कार्यात्मकता विकसित की गई थी। तथापि, जीएसटीएन ने उक्त कार्यात्मकता को कार्यान्वित किया और जीएसटीआर -3 बी रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को सामान्य पोर्टल के माध्यम से सीधे करदाताओं को जीएसटीआर -3 ए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 12/04/2022 के मेल के माध्यम से जीएसटीएन से अनुरोध किया गया था कि वे शीघ्र ही कम्पोजिशन गैर-फाइलर्स सहित सभी प्रकार के रिटर्न दाखिल न करने वालों को सामान्य पोर्टल के माध्यम से जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी करने की कार्यात्मकता विकसित करें और उसे कार्यान्वित करें।

**सिफारिश 27: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जीएसटीआर-04 और सीएमपी-08 सहित सभी प्रकार के रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को सामान्य पोर्टल के माध्यम से जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी किया जाए।**

### 3.2.2 एसआरएस और परिवर्तन अनुरोध (सीआर) के माध्यम से विकसित किए जाने वाले प्रपत्र कार्यात्मकताओं की स्थिति

रिटर्न मॉड्यूल एसआरएस वी1.9 को 12 जनवरी 2017 को साइन ऑफ किया गया था। लेखापरीक्षा को एसआरएस वी9.2 भी प्रदान किया गया था जो रिटर्न के अपडेट किए गए पहले संस्करण का एक मसौदा संस्करण था। यह संस्करण कई पुनरावृत्तियों से गुजरा था और अभी तक साइन ऑफ नहीं किया गया है। इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

- (i) समाप्त हुए एसआरएस वी1.9 में परिकल्पित कार्यात्मकताओं की तुलना में उनके कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट (दिसंबर 2021) के अवलोकन पर, निम्नलिखित पाया गया:
  - सहमत समयसीमा के अनुसार तीन कार्यात्मकताएं नामतः प्रपत्रों को देखने की कार्यात्मकता, टीआरएएन 1 और टीआरएएन 2 को परिनियोजित किया गया है।
  - तीन कार्यात्मकताएं अर्थात् गैर-फाइलर देखें, गैर-फाइलर देखें को नोटिस जारी करें (3ए नोटिस) और एमआईएस रिपोर्ट आंशिक रूप से परिनियोजित की गई हैं।
  - नौ कार्यात्मकताओं नामतः चूककर्ता और फाइल न करने वालों कार्य प्रवाह, अनंतिम निर्धारण, सारांश निर्धारण, गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का निर्धारण, जोखिम आधारित संवीक्षा, टीडीएस/टीसीएस का प्रति सत्यापन, अंतिम रिटर्न दाखिल करना और आरईजी-रद्दीकरण प्रक्रियाओं के साथ लिंक अप करना, प्रति सत्यापन के लिए बीजक मिलान<sup>24</sup> और लेजर रखरखाव (नकदी, आईटीसी और देनदारी) को प्रस्तुतीकरण में परिनियोजित नहीं किया गया है।
- (ii) लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए जीएसटी\_रिटर्न्स\_न्यू रिकवायरमेंट्स\_वी0.6 (7/7/2020 को हस्ताक्षरित (साइन ऑफ)), एसआरएस - रिटर्न निर्धारण वी.7.0 (15/04/2020 को हस्ताक्षरित

<sup>24</sup> बीजक मिलान के लिए एक कार्यात्मकता के विकास से संबंधित कानूनी प्रावधानों (धारा 42, 43 और 43 ए के अंतर्गत) को वित्त अधिनियम, 2022 की धारा 107 द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 से लोपित किया गया है (अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय कर दिनांक 28 सितंबर 2022 द्वारा अधिसूचित)

(साइन ऑफ)), रिटर्न की संवीक्षा वी1.2 (25.03.2019 को हस्ताक्षरित (साइन ऑफ)) और अनंतिम निर्धारण वी0.5 (25.03.2019 को हस्ताक्षरित (साइन ऑफ)) पर एसआरएस को विकसित नहीं कराया गया। यह बताना उचित है कि इन कार्यात्मकताओं को पहले से ही एसआरएस वी1.9 में शामिल किया गया था और बाद में हटा दिया गया था।

(iii) विभाग ने एकल परिवर्तन अनुरोध जारी करके 54 कार्यात्मकताओं का विकास किया, जिनमें से 52 पूर्ण हो चुकी हैं और दो का कार्य प्रगति पर हैं।

चूंकि परीक्षण वातावरण उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए एसआरएस और सीआर के माध्यम से प्रस्तुतीकरण में परिनियोजित कार्यात्मकताओं का परीक्षण नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विवरणियों की संवीक्षा, सारांश और अनंतिम निर्धारण, जोखिम निर्धारण इंजन, खाता-बही रखरखाव आदि जैसी कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मकताओं को विकसित नहीं किया गया था और विकसित करने के लिए समयसीमा निश्चित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अप्रैल 2022) के उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि कार्यात्मकताएं विकासाधीन हैं या शीघ्र ही आरंभ की जाएंगी।

**सिफारिश 28: विभाग को प्रभावी निगरानी के लिए कार्यात्मकताओं के विकास और परिनियोजन के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संवीक्षा और निर्धारण, जोखिम निर्धारण इंजन, खाता बही रखरखाव आदि जैसी महत्वपूर्ण कार्यात्मकताओं को समयानुसार विकसित और परिनियोजित किया जाए।**

### 3.3 भुगतान मॉड्यूल

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत, कर भुगतान संबंधित शीर्षो- सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान प्रणाली की मुख्य विशेषताएं पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक, कहीं भी कैसे भी भुगतान मोड, तार्किक कर संग्रह डेटा प्रारूप, तीव्र प्रेषण, कागज रहित लेनदेन, त्वरित लेखांकन, इलेक्ट्रॉनिक

मिलान, बैंकों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया और डिजिटल चालान का भंडारण है। भुगतान के तीन तरीके हैं:

- प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से करदाताओं द्वारा भुगतान।
- प्राधिकृत बैंकों के चालान द्वारा दस हजार रुपये तक का काउंटर भुगतान (ओटीसी)।
- किसी भी बैंक से आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान।

**तालिका 3.3 - संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स**

उप-उद्देश्य	परीक्षित/अपरीक्षित	सफल/असफल/सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
डेटा प्रवासन और डेटा प्रसंस्करण की पर्याप्तता और प्रभावकारिता का निर्धारण करना	परीक्षित (4)	सफल (2)	उपयुक्त उपयोगकर्ता विशेषाधिकारों में समस्याएं, लेनदेन के विवरण में डेटा अनुरूपता	-
		असफल (2)	देखी गई विसंगतियां, देखी गई बेमेल स्थितियाँ	एआरपीआईटी प्रणाली की आईटी लेखापरीक्षा में अलग से कवर किया जाना है
	अपरीक्षित (1)	सीमा प्रतिबन्ध (1)	वास्तविक समय के आधार पर डेटा प्रेषण	लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या कच्चा भुगतान डेटा एपीआई के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है
यह देखना कि क्या एमआईएस रिपोर्ट सटीक और विश्वसनीय है	अपरीक्षित (2)	सीमा प्रतिबन्ध (2)	एमआईएस रिपोर्ट की प्रासंगिकता, सृजित रिपोर्टों का प्रमाणीकरण	परीक्षण वातावरण की सुविधा न होने के कारण एमआईएस रिपोर्ट की जांच नहीं की जा सकी
यह सुनिश्चित करना कि कार्यात्मकताएं और वैधीकरण कानून के प्रावधानों के अनुसार हैं।	परीक्षित (1)	असफल (1)	कानून के प्रावधानों के अनुसार वैधीकरण	3.3.1

भुगतान एसआरएस संस्करण 4.4ए के अनुसार, कुल 12 कार्यात्मकताओं को परिनियोजित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने प्रस्तुतीकरण में कुछ प्रमुख कार्यात्मकताओं को परिनियोजित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि विभाग (अगस्त 2018) ने आरंभ में केवल खाता बही को देखने के लिए कार्यात्मकता परिनियोजित की थी और बाद में इसने (नवंबर 2018) एक अतिरिक्त कार्यात्मकता (परामर्श संख्या 3 दिनांक 13 नवंबर 2018) "जीएसटीएन के साथ एकीकरण" प्रदान की क्योंकि खाता बही को देखने के लिए वर्तमान कार्यात्मकता अपडेट नहीं हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप खाता बही में डेटा में कमियाँ आ रही थी। "जीएसटीएन के साथ एकीकरण" कार्यात्मकता से, जब भी 'जीएसटीएन के साथ एकीकरण फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है तब उपयोगकर्ता जीएसटीएन से वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन खाता बही विवरण प्राप्त कर सकता है; जिसके परिणामस्वरूप खाता बही विवरण स्थायी रूप से आद्यतित किया जा सकता है और फ़ील्ड संरचनाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है। लेखापरीक्षा एसएसओआईडी के माध्यम से देखने और एकीकरण कार्यात्मकता के कामकाज की यादृच्छिक रूप से जांच की गई और कोई विचलन नहीं देखा गया। उपरोक्त दो को छोड़कर, शेष कार्यात्मकताएं विकसित नहीं की गईं ।

एसआरएस में परिकल्पित कार्यात्मकताओं का विकास न होने और काउंटर पर (ओटीसी) भुगतानों के संबंध में वैधीकरण विफलता से संबंधित एक अतिरिक्त निष्कर्ष का विवरण निम्नानुसार हैं:

### **3.3.1 सीजीएसटी नियमावली में संशोधन किए बिना वैधीकरण नियंत्रण का हटाया जाना: काउंटर पर (ओटीसी) भुगतान मोड में विसंगतियाँ**

पूर्वोक्त सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 87 (3) के अनुसार प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से ओटीसी भुगतान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रति कर अवधि प्रति चालान दस हजार रुपये तक जमा के लिए किया जा सकता है। दस हजार की सीमा निम्नलिखित द्वारा जमा की गई जमा पर लागू नहीं होती है:

- सरकारी विभागों या व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली कोई अन्य जमा राशि जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए;
- किसी भी व्यक्ति, चाहे वह पंजीकृत है या नहीं, से बकाया देयों की वसूली के लिए प्राधिकृत उचित अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी द्वारा चल या अचल संपत्तियों की कुर्की या बिक्री के माध्यम से की गई वसूली सहित;
- प्राधिकृत उचित अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी जांच या प्रवर्तन कार्यकलाप या किसी तदर्थ जमा के दौरान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एकत्र की गई राशि।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमत श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य करदाताओं द्वारा ओटीसी भुगतान मोड के माध्यम से दस हजार रुपये से अधिक के भुगतान की अनुमति दी गई थी, जो सीजीएसटी नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह भी देखा गया कि सामान्य पोर्टल ओटीसी भुगतान मोड के माध्यम से दस हजार रुपये से अधिक की जमा राशि के लिए चालान बनाने की अनुमति दे रहा है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, जीएसटीएन ने ओटीसी भुगतान को केवल दस हजार रुपये तक सीमित करके सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

### 3.4 एसीईएस से डेटा प्रवासन (माइग्रेशन)

'एसीईएस टू जीएसटी माइग्रेशन' पर दिनांक 12 जून 2018 के एसआरएस तकनीकी दस्तावेज संस्करण 1.1 के अनुसार, डेटा प्रवासन परियोजना का व्यावसायिक उद्देश्य डेटा सटीकता में सुधार और कार्य निरंतरता को बनाए रखते हुए स्रोत प्रणाली (एसीईएस) से लक्ष्य प्रणाली (एसीईएस-जीएसटी) में रुचि के डेटासेट को अंतरित करना था। डेटा माइग्रेशन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल थे, जैसे कि व्यावसायिक प्रभाव का विश्लेषण, सूचना एकत्र करना, प्रतिचित्रण और अभिकल्प, माइग्रेशन योजना, प्रावधान, परीक्षण माइग्रेशन, माइग्रेशन और वैधीकरण। डेटा माइग्रेशन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित कार्य परिकल्पित किए गए थे।

- पूर्व-जीएसटी (146 कमिश्नरी) के अंतर्गत करदाताओं के प्रति दर्शाये गए कार्यों को पश्च जीएसटी (107 कमिश्नरी) सेटअप में प्रवासित किया जाना।
- एसीईएस-सनसेट के समय एसीईएस आवेदन के अंतर्गत लंबित कार्यों को एकीकृत सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाना।
- कुछ पूर्व-पहचाने गए कार्यों (उदाहरणार्थ, 30 जून 2017 तक लंबित एकल परिसर पंजीकरण आवेदन) के डीमड बंद (अर्थात, बैकएंड क्लोजर) के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय कार्यान्वित किया जाना।
- कुछ पहचाने गए कार्यों (उदाहरणार्थ, 30 जून 2017 तक आयुक्त के पास लंबित केंद्रीकृत सेवा कर पंजीकरण) के ऑनलाइन प्रसंस्करण और समापन (अर्थात, फ्रंटएंड क्लोजर) के लिए नीतिगत निर्णय।
- पूर्व-जीएसटी अवधि के संबंध में लंबित सीई और एसटी रिटर्न की संवीक्षा को आगे ले जाया जाना और विभागीय उपयोगकर्ता को इस कार्य में निरंतर सहभाग करने हेतु सक्षम बनाया जाना।
- मॉड्यूल-वार सृजित किए जाने वाले लंबित कार्यों की सूची, 30 जून 2017 तक एकबारगी आधार पर सीडीआर-वार (पूर्व-जीएसटी संरचनाओं के संबंध में) और 30 जून 2018 तक (पश्च-जीएसटी के संरचनाओं के संबंध में) और कार्यों के प्रसंस्करण और पूर्णता में तीव्रता लाने के लिए सभी ज़ोनों/आयुक्तालयों/डिवीजनों/रेंज प्राधिकरणों के साथ साझा किया जाना है।

**तालिका 3.4 - संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स**

उप-उद्देश्य	परीक्षित /अपरीक्षित	सफल/असफल/ सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
यह सुनिश्चित करना कि आंकड़ा पूरी तरह से प्रवासित हो गया है।	परीक्षित (7)	सफल (1)	नीतिगत निर्णय पर दस्तावेज	-
		सीमा प्रतिबन्ध (6)	डेटा प्रवासन की पूर्णता, तालिका संरचनाओं की समीक्षा और एसीईएस और एसीईएस - जीएसटी तालिका का प्रतिचित्रण,	3.4

उप-उद्देश्य	परीक्षित /अपरीक्षित	सफल/असफल/ सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
			एमआईएस रिपोर्ट, प्रवासित डेटा का सत्यापन	
जीएसटी के अंतर्गत समाहित नहीं किए गए उत्पादों के लिए एसीईएस - सीबीआईसी जीएसटी एप्लीकेशन में कार्य निरंतरता बनाए रखना	अपरीक्षित (3)	सीमा प्रतिबन्ध (3)	अनंतिम निर्धारण मॉड्यूल, भुगतान, प्रतिदाय और दावे और सूचना मॉड्यूल।	

तकनीकी दस्तावेज में परिकल्पित डेटा प्रवासन प्रक्रिया की शुद्धता और पूर्णता पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए, लेखापरीक्षा ने डेटा प्रवासन से संबंधित रिपोर्टों और दस्तावेजों नामतः डेटा प्रवासन योजना, परीक्षण प्रवासन रिपोर्ट, वैधीकरण और पूर्णता रिपोर्ट, डेटा प्रवासन के आरंभ और पूर्ण होने का विवरण, त्रुटि लॉग इत्यादि के लिए की मांग (09/02/2021) की थी।

लेखापरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच करने पर, निम्नलिखित पाया गया:

'एसीईएस टू जीएसटी माइग्रेशन' पर दिनांक 12 जून 2018 के एसआरएस तकनीकी दस्तावेज संस्करण 1.1 के अनुसार, डेटा प्रवासन परियोजना का व्यावसायिक उद्देश्य डेटा सटीकता में सुधार और कार्य निरंतरता को बनाए रखते हुए स्रोत प्रणाली (एसीईएस) से लक्ष्य प्रणाली (एसीईएस-जीएसटी) में रूचि के डेटासेट को प्रवासित करना था।

विभाग ने कहा (मई 2021) कि 4,45,752 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सीई) और 37,12,710 सेवा कर (एसटी) दाताओं को एसीईएस से एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में सफलतापूर्वक अंतरित कर दिया गया था। विभाग ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2022) कि वास्तविक प्रवासन तकनीकी दस्तावेज में निहित विस्तृत प्रवासन योजना के आधार पर किया गया था, जिसने निगरानी उद्देश्य के लिए समयसीमा के साथ वर्क ब्रेक डाउन की संरचना का

आधार बनाया था। विभाग ने आगे कहा कि 4 ज़ोन अर्थात चेन्नई, पुणे, मेरठ और गुवाहाटी के प्रतिनिधि डेटा से संबंधित सत्यापन रिपोर्टों में चयनित फ़ील्ड की डेटा गणना के आधार पर डेटा प्रवासन को पूर्ण होना स्वीकार किया गया था, जिसमें डेटा गणना में कोई विचलन नहीं देखा गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 4 नमूना प्रतिनिधि ज़ोन का चयन भौगोलिक रूप से सीबीआईसी की क्षेत्रीय संरचनाओं से किया गया था। डेटा प्रवासन की पूर्णता का वैधीकरण इन चार नमूना प्रतिनिधि ज़ोन की वैधीकरण रिपोर्ट पर पूरी तरह से निर्भर होकर मान्य किया गया था। तथापि, परीक्षण वातावरण की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण, लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से इन रिपोर्टों की सत्यता के साथ-साथ अधिसूचित, गैर-जीएसटी वस्तुओं के लिए एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में कार्य निरंतरता का सत्यापन करने में विफल रही।

### 3.5 प्रतिदाय मॉड्यूल

जीएसटीएन द्वारा विकसित जीएसटीएन सामान्य पोर्टल प्रतिदाय हेतु करदाताओं के लिए फ्रंट-एंड पोर्टल के रूप में कार्य करता है। एक करदाता/डीलर/फर्म प्रतिदाय के लिए जीएसटीएन सामान्य पोर्टल पर आवेदन करती है और सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूपों में प्रतिदाय दावा प्रस्तुत करती है। सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में एपीआई के माध्यम से प्रतिदाय आवेदन प्रसंस्कृत करने के लिए विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें वे संस्वीकृत/अस्वीकृत/प्रतिदाय दावों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।

तालिका 3.5 - संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

उप-उद्देश्य	परीक्षित/अपरीक्षित	सफल/असफल/सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
क्या प्रतिदाय मॉड्यूल सीबीआईसी बैकएंड में करदाता प्रतिदाय	परीक्षित (35)	सफल (33)	एप्लीकेशन डेटा का संचरण, कार्यों का सृजन, प्रतिदाय आवेदन की जांच, आरएफडी 02 और आरएफडी 03, कलर कोडिंग फ्लैग, आरएफडी 06, प्रतिदाय	-

उप-उद्देश्य	परीक्षित/अपरीक्षित	सफल/असफल/सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
आवेदन दर्शाने वाली प्रणाली और कर अधिकारी को प्रतिदाय अनुरोध को प्रसंस्कृत करने और उसी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए विकल्प प्रदान करता है।			आवेदन का संग्रह, कारण बताओ नोटिस जारी करना, देनदारियों का समायोजन, अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति, वसूली की स्थिति, आरएफडी 05, विवरण स्क्रीन पर नेविगेशन, सहायक दस्तावेजों को अपलोड करना, पीएमटी - 03, "एआरएन विवरण को पीडीएफ में परिवर्तित करना" का विकल्प	
		असफल (2)	पर्याप्त कार्यात्मकताओं की उपलब्धता, बकाया मांग का समायोजन, प्रतिदाय रोक कार्यात्मकता	3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4
		अपरीक्षित (39)	सीमा प्रतिबन्ध (39)	आवेदन का पुनः आवंटन, प्रतिदाय दावे का पुनः क्रेडिट, आरएफडी-09 की उपलब्धता, भुगतान संवितरण कार्यप्रवाह, कर अधिकारी के ई-हस्ताक्षर, भुगतान सलाह विवरण, लेजर का अद्यततिकरण, त्रुटि कार्य सूची, प्रशासक स्क्रीन में कार्यात्मकताएं, निर्धारित मास्टर तालिका, मूल भुगतान सलाह विवरण पर विचार, सचेतन अधिसूचनाएं, जीएसटीएन द्वारा निर्धारित मास्टर डेटा भेजना, एमआईएस रिपोर्ट

यह जांच करने पर कि क्या प्रतिदाय मॉड्यूल की कार्यात्मकताएं कानून की आवश्यकता के अनुसार विकसित की गई थी, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रतिदाय आवेदनों के प्रसंस्करण से संबंधित फॉर्म अर्थात्, फॉर्म- जीएसटी आरएफडी -01 करदाता द्वारा दायर प्रतिदाय के लिए ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म- जीएसटी आरएफडी -02- पावती, फॉर्म- जीएसटी आरएफडी -03- कमी ज्ञापन, फॉर्म- जीएसटी आरएफडी -04- अनंतिम प्रतिदाय आदेश, फॉर्म - जीएसटी आरएफडी -06- प्रतिदाय स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश, फॉर्म -

जीएसटी आरएफडी -05- भुगतान आदेश, फॉर्म - जीएसटी आरएफडी -08- रिफंड के लिए आवेदन की अस्वीकृति की सूचना, फॉर्म- जीएसटी आरएफडी -09- कारण बताओ नोटिस का उत्तर, फॉर्म जीएसटी-पीएमटी -03- प्रतिदाय दावे की अस्वीकृति पर नकद या क्रेडिट लेजर में राशि के पुनः क्रेडिट के लिए आदेश का प्रतिचित्रण किया गया था और एप्लीकेशन में काम कर रहा था।

जीएसटीएन पोर्टल पर करदाताओं द्वारा भरे गए फॉर्म बैकएंड प्रसंस्करण के लिए सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी पोर्टल पर सफलतापूर्वक प्रेषित किए जा रहे थे और प्रतिदाय प्रसंस्करण अधिकारी (आरपीओ) के डैशबोर्ड पर ठीक से दृष्टिगत थे। प्रतिदाय प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पावती, कमी ज्ञापन, कारण बताओ नोटिस (एससीएन) आदि जारी करने जैसी कार्यात्मकताएं मौजूद और कार्य करती पाई गईं। अर्हक प्रतिदाय दावों के लिए अनंतिम प्रतिदाय के लिए कार्यात्मकता, और आईटीसी लेजर के तुल्यकालन और आरपीओ द्वारा सत्यापन विकसित और कार्य करते पाए गए। तथापि, एसआरएस, यूएटी परीक्षण और डेटा प्रश्नों के परिणामों की जांच के दौरान कुछ कमियां पाई गईं, जिन्हे आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

### **3.5.1 सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में अधिसूचित व्यक्ति को प्रतिदाय के प्रसंस्करण की कार्यात्मकता विकसित नहीं की गई थी**

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 95 के उप-नियम 1 के अनुसार, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 55 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी आवक आपूर्ति पर उसके (अधिसूचित व्यक्तियों) द्वारा भुगतान किए गए कर प्रतिदाय का दावा करने के लिए अर्हक है, उसे माल या सेवाओं या दोनों की आवक आपूर्ति के विवरण के साथ, सामान्य जीएसटीएन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक तिमाही में एक बार प्रतिदाय के लिए आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त, नियम 95 के उप-नियम 4 यह प्रावधान करता है कि नियम 92 के प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों-सहित, इस नियम के अंतर्गत प्रतिदाय की स्वीकृति और भुगतान के लिए लागू होंगे।

एसआरएस (संस्करण 1.4) की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सीबीआईसी ने अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा दायर प्रतिदाय आवेदनों को प्रसंस्कृत करने का प्रावधान किया लेकिन इसे "भविष्य में अनुसरण किए जाने के लिए" टिप्पणियों के साथ रोक दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि बैकएंड एप्लीकेशन विकसित नहीं जा सकी क्योंकि जीएसटीएन द्वारा प्रतिदाय दावों की इस श्रेणी के लिए ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए एपीआई साझा किया जाना शेष है। एक बार जीएसटीएन द्वारा फ्रंटएंड पर इस कार्यात्मकता को विकसित करने के पश्चात, उसे बैकएंड पर भी विकसित कर लिया जाएगा।

**सिफारिश 29: विभाग को एसआरएस में यथा परिकल्पित अधिसूचित व्यक्तियों के लिए यूआईएन श्रेणी के प्रतिदाय आवेदनों को प्रसंस्कृत करने के लिए कार्यात्मकता विकसित करने के लिए जीएसटीएन के साथ मामले का अनुसरण करना चाहिए।**

**3.5.2 अनंतिम प्रतिदाय आदेश (आरएफडी-04) में अधिनियम या किसी मौजूदा कानून के अंतर्गत बकाया मांग के समायोजन के लिए कार्यात्मकता विकसित नहीं की गई थी**

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54 की उप-धारा 6 के अनुसार, उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उचित अधिकारी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के निर्यात के मामले में शून्य-श्रेणीकृत आपूर्ति और एसईजेड इकाई या डेवलपर को आपूर्ति के कारण इस प्रकार दावा की गई कुल राशि का नब्बे प्रतिशत अनंतिम आधार पर प्रतिदाय कर सकता है और उसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद प्रतिदाय दावे के अंतिम निपटान के लिए उप-धारा (5) के अंतर्गत एक आदेश दे सकता है।

इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप-धारा 10 (बी) में प्रावधान है कि उचित अधिकारी शोध्य प्रतिदाय में से किसी ऐसे कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए

कराधेय व्यक्ति दायी है किन्तु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत्त रहती है, कटौती कर सकेगा। तथापि, एसआरएस में सीजीएसटी अधिनियम के इन प्रावधानों की मैपिंग के अभाव में, सीबीआईसी आईटी प्रणाली करदाता के देय प्रतिदाय से देनदारी रजिस्टर-II में लंबित बकाया देयकों की वसूली के लिए अभिकल्पित नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, मांग को समायोजित किए बिना प्रतिदाय दावे के 90 प्रतिशत तक अनंतिम प्रतिदाय को संस्वीकृति दी गई। इस तथ्य की संपुष्टि 01 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए आंकड़ों की पूछताछ के परिणाम (जुलाई 2021) के साथ की गई थी। 552 मामलों में, देयता रजिस्टर-II में वसूली के लिए लंबित बकाया मांग को समायोजित किए बिना अनंतिम प्रतिदाय को संस्वीकृति दी गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार कर लिया और कहा (अगस्त 2022) कि अनंतिम आदेश जारी करते समय दायित्व के समायोजन की कोई सुविधा नहीं है क्योंकि यह व्यवस्था जीएसटीएन द्वारा जारी एपीआई की विशेषताओं में उपलब्ध नहीं है। यदि जीएसटीएन जीएसटीएन पोर्टल में कोई कार्यात्मकता विकसित करता है, वही बैकएंड में भी विकसित कर लिया जाएगा।

**सिफारिश 30: विभाग को बकाया मांग के समायोजन के लिए कार्यात्मकता विकसित करने के लिए जीएसटीएन के साथ मामले का अनुसरण करना या अनंतिम प्रतिदाय को स्वीकृति देते समय उचित अधिकारी को कम से कम ऐसी बकाया मांग के बारे में सचेत करना चाहिए।**

**3.5.3 अधिनियम अथवा किसी मौजूदा कानून के अंतर्गत बकाया मांग के समायोजन पर ब्याज की वसूली के लिए अंतिम प्रतिदाय आदेश में कार्यात्मकता विकसित नहीं की गई थी**

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 (1) यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या

उसके भाग का भुगतान नहीं किया जाता, स्वयं, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो अठारह प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त धारा 50 (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत ब्याज की गणना, जिस प्रकार से निर्धारित किया गया हो, उस दिन के बाद के दिन से जिस दिन ऐसे कर का भुगतान किया जाना था, की जाएगी।

यूएटी वातावरण में प्रतिदाय बैकएंड प्रक्रियाओं के परीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि बकाया मांग के समायोजन के लिए अधिनियम के प्रावधान को अंतिम प्रतिदाय आदेश जारी करने के चरण में कार्यान्वित किया गया था। तथापि, करदाताओं को देय अंतिम प्रतिदाय से बकाया मांग (मांग की तिथि (मांग आईडी तिथि) से प्रतिदाय देय राशि से समायोजित राशि की तिथि तक ब्याज) के भुगतान पर ब्याज की वसूली/समायोजन कि कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि एसआरएस तैयार करते समय इस पहलू पर विचार नहीं किया गया था। इसकी पुष्टि 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए 170 मामलों वाले डेटा क्वेरी के परिणाम के साथ की गई थी, जहां बकाया मांग को प्रतिदाय प्रसंस्करण अधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिदाय आदेश (आरएफडी-06) से समायोजित किया गया था। 52 मामलों में, स्वीकृत प्रतिदाय से मांग के समायोजन में 1 से 601 दिनों तक का विलंब था। तथापि, समायोजित राशि पर विलंबित अवधि के लिए ब्याज पर विचार नहीं किया गया था। 52 मामलों में, ₹43.05 लाख रुपये की अनुमानित ब्याज राशि लगाने पर इस संबंध में विचार नहीं किया गया था। 61 मामलों में, मांग आईडी सृजन की तिथि प्रदान नहीं की गई थी जबकि शेष 57 मामलों में मांग की तिथि और प्रतिदाय संस्वीकरण तिथि समान थी।

**सिफारिश 31: विभाग को जीएसटीएन के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बकाया मांग पर ब्याज की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में एक कार्यात्मकता विकसित और परिनियोजित की जाए।**

मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि जीएसटीएन के मौजूदा एपीआई के प्रावधानों के अनुसार, ब्याज लघु शीर्ष के

अंतर्गत देयता को उस राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जा सकता है जो कर लघु शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत है क्योंकि प्रणाली इस तरह के समायोजन को अस्वीकार करती है। तथापि, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए इस मुद्दे को जीएसटीएन के साथ उठाया गया था। मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है। प्रतिदाय आदेश में देय प्रतिदाय के प्रति बकाया ब्याज देनदारी को समायोजित करने का प्रावधान है। तथापि, प्रणाली में उठाई गई मांग की तिथि (मांग आईडी तिथि) से अंतिम प्रतिदाय देय राशि से समायोजित राशि की तिथि तक की अवधि के लिए बकाया मांग के विलंब से समायोजन पर अर्जित ब्याज को समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

#### 3.5.4 प्रतिदाय रोक कार्यात्मकता विकसित नहीं की गई

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54 की उप-धारा 10 के अनुसार, जहां कोई प्रतिदाय उप-धारा (3) के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति को देय है, जिसने कोई रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक की है या जिसके द्वारा किसी भी कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान किया जाना है, जिसे किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक स्थगित नहीं किया गया है, तो उचित अधिकारी-

- जब तक उक्त व्यक्ति ने रिटर्न प्रस्तुत न की हो, या कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान नहीं किया हो, या जैसा भी मामला हो, प्रतिदाय का भुगतान रोकें;
- देय प्रतिदाय से, किसी प्रकार का कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या कोई अन्य राशि जो कर योग्य व्यक्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है लेकिन जिसका इस अधिनियम के अंतर्गत या मौजूदा कानून के अंतर्गत भुगतान नहीं किया गया हो, की कटौती करें।

इसके अतिरिक्त, धारा 54 (11) यह प्रावधान करती है कि जहां प्रतिदाय देने वाला आदेश अपील या आगे की कार्यवाही का विषय है या जहां इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अन्य कार्यवाही लंबित है और आयुक्त का यह मत हो कि उक्त अपील में इस तरह के प्रतिदाय की मंजूरी से राजस्व पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या कदाचार या धोखाधड़ी से संबंधित अन्य कार्यवाही लंबित हों, वह उस समय तक प्रतिदाय को रोक सकता है जब तक वह उचित समझे।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए एसआरएस दस्तावेज की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्रतिदाय के लिए रोक (विदहोल्ड) कार्यात्मकता (आरएफडी-07 भाग बी) को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

**सिफारिश 32: विभाग को बिना किसी विलंब के प्रतिदाय रोक कार्यात्मकता के विकास और परिनियोजन को सुनिश्चित करना चाहिए।**

जब लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति को इंगित किया गया (सितम्बर 2021), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि प्रतिदाय रोक कार्यात्मकता को 03.08.2022 को उत्पादन में परिनियोजित किया गया था। इसके कार्यान्वयन की समीक्षा बाद की लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

### 3.6 जांच मॉड्यूल

आरएफपी के अनुसार जांच मूल रूप से डीएसआर मॉड्यूल के एक भाग के रूप में परिकल्पित की गयी थी, लेकिन इसे एक अलग मॉड्यूल के रूप में विकसित किया गया। जांच मॉड्यूल की प्रक्रियाओं को सूचना/आसूचना दाखिल करने, जांच की प्रक्रिया और कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने और अभियोजन के लिए मंजूरी तक की प्रक्रियाओं को अभिग्रहित करने और प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद की प्रक्रिया जैसे की एससीएन के अधिनिर्णयन, देय राशियों की वसूली आदि डीएसआर मॉड्यूल से जुड़ी हुई है। जांच मॉड्यूल विभागीय अधिकारियों द्वारा मामलों की जांच में शामिल प्रक्रियाओं को अभिग्रहित करता है, जिसका उपयोग अपवंचन-रोधी विंग और जीएसटी जांच महानिदेशक द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जांच मॉड्यूल के विकास को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना बनाई गई थी। चरण I में जांच शुरू होने से लेकर सभी जांच गतिविधियों को अभिलेखित करना शामिल था। मॉड्यूल में पश्च जांच, भुगतान और परिमाणीकरण को छोड़कर जांच

प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं। दूसरे चरण में अभियोजन, समझौता (कम्पाउंडिंग), पारगमन में माल का अवरोधन शामिल है, जिनका विकास किया जा रहा है।

तालिका 3.6 - सारांशित लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

उप-उद्देश्य	परीक्षित / अपरीक्षित	सफल / असफल / सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच का सार	अभ्युक्तियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
क्या एसआरएस जीएसटी अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, विभागीय निर्देशों और परिपत्रों के आधार पर तैयार किया गया है?	परीक्षित (24)	सफल (20)	जीएसटी आईएनएस-01 से 05 तक का सृजन, माल का सुरक्षित रख-रखाव, जब्त किए गए सामानों की सूची, भुगतान का विवरण अभिग्रहित करना, बॉन्ड/प्रतिभूति, जांच रजिस्टर, खुफिया सूचना की स्वीकृति और प्राधिकरण, सिस्टम रिपोर्ट, एसीएल, कार्यप्रवाह, घटना/अपराध/ जांच रिपोर्ट और कारण बताओ नोटिस जारी करना, 335जे रजिस्टर	-
		असफल (4)	रिटर्निंग दस्तावेज की शर्त को मान्य करना, यदि कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है तो विवरण अभिग्रहित करना, माल जारी करने की समय-सीमा, विशेष लेखापरीक्षा, विशिष्ट भूमिका मैट्रिक्स	2.5.3
क्या जांच से संबंधित फॉर्म और कार्यात्मकताएं एसआरएस के अनुसूचित सृजित होती हैं?	परीक्षित (150)	सफल (133)	मॉड्यूल के गो-लाइव से पहले दर्ज मामलों को अपलोड करना, जांच दल, करदाता के साथ संचार, जीएसटीआई-01, जांच प्रशासन, कमांड चैन अधिकारियों का सेटअप, अनिवार्य केस लीड, जांच मॉड्यूल में अतिरिक्त अधिकारी, फ़िल्ड भरने के लिए "सूचना का स्रोत" और "कमांड चैन", जांच प्रस्ताव को मंजूरी/अस्वीकार/स्पष्ट करने के लिए उच्च अधिकारी, तलाशी और जब्ती परिणामों का अद्यतन, ऐतिहासिक डेटा की उपलब्धता, प्राधिकरण और प्रतिसंहरण, मामले और फाइलों का स्थानांतरण, अधिकारियों का इतिहास, स्वीकृति/निरस्त प्राधिकरण पृष्ठ पर केवल पढ़ने के लिए पहुंच, खुफिया अधिकारी, एक विशिष्ट मामला संख्या का आवंटन, ऑफलाइन मामलों की स्वीकृति, दस्तावेजों को अपलोड करना, जानकारी प्राप्त करना, विशिष्ट जांच केस आईडी, अलर्ट तंत्र, फॉर्म जीएसटीआई-02, 05, 08, 09, करदाता से उत्तर, एपीआई के	-

उप-उद्देश्य	परीक्षित / अपरीक्षित	सफल / असफल / सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच का सार	अभ्युक्तियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
			<p>माध्यम से जीएसटीएन को सूचना, मैन्युअल मेल प्रेषण, दस्तावेजों को कई बार अपलोड करना, जीएसटीआई -10, सम्मन का विवरण, आईएनएस -01 और 01 ए, खोज फॉर्म और खोज कार्यवाही, आईएनएस- 02, जब्ती कार्यवाही का तलाशी कार्यवाही से संबंध, निष्पादन का विवरण, महाजर, रिकॉर्डिंग, निषेध कार्यवाही, आईएनएस-03, रिलीज कार्यवाही, वैधीकरण प्रमाण पत्र, कार्यवाही को बंद करने के लिए, आईएनएस-04, आईएनएस-05ए, गिरफ्तारी कार्यवाही, जीएसटीआई-11 , 12, 15, 16, और 26, जमानत की कार्यवाही, जीएसटीआई -13, 14, 17, 18 और 20, डेटा की प्री-पोपयुलेशन, एससीएन, निर्देश देने के लिए प्राधिकार, सूचनाएं, जांच मामले का त्वरित अवलोकन, ऑटो-अपडेशन, केस फाइल समापन, जांच प्रशासन को प्राधिकरण सुविधा देना/निरस्त करना, फाइलों का स्थानांतरण, मामलों की समीक्षा करना, समीक्षा बैठकों को सहेजना, एक ही केस चेन के लिए अलग-अलग जीएसटीआईएन के लिए डुप्लीकेट प्रस्ताव शुरू करना</p>	
		असफल (17)	<p>पुरस्कार, अभियोजन और समझौते से संबंधित कार्य, डीआरसी-03, डीआरसी-04, जांच के बाद की कार्यकलापों तक पहुंच/देखना, सम्मन कार्यवाही का ट्रिगर तंत्र, भुगतान और मात्रा का निर्धारण, जीएसटीआई-19 वसूली विवरण, जांच को बंद करना, जारी किए गए एस सी एन की जानकारी कैप्चर करना, जी एस टी आई-21, जी एस टी आई -22, डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा मान्य संचार, डेटा प्रतिधारण</p>	<p>2.5.4.1 3.12.2</p>

उप-उद्देश्य	परीक्षित / अपरीक्षित	सफल / असफल / सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच का सार	अभ्युक्तिताँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
	अपरीक्षित (9)	सत्यापित नहीं किया जा सका (9)	जांच मामलों का स्थानांतरण, दूरस्थ जांच कार्य असाइनमेंट, कार्य सौंपना, दूरस्थ अधिकार क्षेत्र अधिकारी	-
क्या जीएसटीएन के अतिरिक्त किसी अन्य इंटरफेस तंत्र को जांच मॉड्यूल के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है?	परीक्षित (1)	असफल (1)	विशेष रूप से जांच मुद्दों से संबंधित किसी भी अन्य बाहरी प्रणाली के साथ इंटरफेस	4.2

### 3.7 विवाद निपटान और समाधान (डीएसआर) मॉड्यूल

डीएसआर मॉड्यूल में प्रक्रियाओं को गतिविधियों के विस्तार के अंतर्गत प्रक्रियाओं को अभिग्रहित करने और प्रभावित करने के लिए अभिकल्पित किया जाना था जिसमें किसी विवाद के जीवनचक्र में बकाया राशि की वसूली तक एससीएन/मांगों का विवरण (एसओडी), एससीएन/एसओडी का अधिनिर्णयन, अपील, समीक्षा और संशोधन शामिल है।

#### 3.7.1 अधिनिर्णयन मॉड्यूल

अधिनिर्णयन मॉड्यूल को मांग के लिए नोटिस जारी करने और अधिनिर्णयन के लिए सशक्त विभागीय अधिकारियों - रैंज अधिकारियों से लेकर आयुक्त, जीएसटी जांच महानिदेशक, अपवंचन-रोधी और लेखापरीक्षा स्कन्ध द्वारा निर्णय लेने में शामिल प्रक्रियाओं को अभिग्रहित करने की आवश्यकता थी।

अधिनिर्णयन मॉड्यूल में तीन भाग शामिल हैं - एससीएन जारी करना, अधिनिर्णयन और ओआईओ जारी करना, जो फॉर्म डीआरसी-01, डीआरसी-02, डीआरसी-03, डीआरसी-04, डीआरसी-05, डीआरसी-06, डीआरसी-07 और डीआरसी 08 द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं।

हालांकि एससीएन संक्षिप्त निर्धारण, संवीक्षा, विशेष लेखापरीक्षा सहित लेखापरीक्षा, प्रतिदाय और अपवंचन-रोधी से सृजित हो सकते हैं, फिर भी केवल प्रतिदाय और अपवंचन-रोधी के लिए सृजित एससीएन जारी करने की कार्यात्मकता आरंभ की गई है। ओआईओ जारी करने के लिए डीआरसी-02 को छोड़कर उपर्युक्त सभी फॉर्म को लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत सुनवाई के निर्धारण और कॉल बुक के सभी मामलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है।

तालिका 3.7 - संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

उप-उद्देश्य	परीक्षित/अपरीक्षित	सफल/असफल/सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच का सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
क्या एसआरएस जीएसटी अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, विभागीय निर्देशों और परिपत्रों के आधार पर तैयार किया गया था?	परीक्षित (50)	सफल (46)	एससीएन से संबंधित मामले, आदेशों का सुधार, विवाद जीवनचक्र रजिस्टर, अपुष्ट मांग, पुष्टि की गई मांग, वसूली, स्वैच्छिक भुगतान, अपील रजिस्टर, एसीएल, शक्तियों का प्रत्यायोजन, देयता रजिस्टर भाग-II, व्यक्तिगत सुनवाई विवरण, फॉर्म डीआरसी -01, 02, 04, 05, 07, 20 तैयार करना, भुगतान के लिए समय बढ़ाना, क्षेत्राधिकार प्राधिकरण, कर योग्य व्यक्ति के चूककर्ता होने की जांच, चालू वसूली प्रक्रिया	-
		असफल (4)	मासिक क्रिस्त, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डीआरसी -21	3.7.3.1 3.12.2
क्या विवाद समाधान से संबंधित फॉर्म और कार्यात्मकता एसआरएस के अनुसार तैयार की गयी हैं?	परीक्षित (135)	सफल (98)	एससीएन का मसौदा तैयार करना, शक्तियों का प्रत्यायोजन, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना, मसौदे को अनुमोदित/अस्वीकार/ संशोधित करने का प्राधिकार, आदेश/सुधार की शुरुआत, आदेश में सुधार, व्यक्तिगत सुनवाई का विवरण, जीएसटीएन को एससीएन अग्रेषित करना, विशिष्ट पहचान संख्या, डीआरसी -01, एससीएन सृजित होने पर डेटा कैचर करना, अपुष्ट मांग रजिस्टर, एससीएन को ऑफलाइन जारी करने का विवरण दर्ज करना, एससीएन को निर्णायक प्राधिकारी को अग्रेषित करना, डीआरसी -03, सचेत तंत्र, डीआरसी -06, व्यक्तिगत सुनवाई	-

उप-उद्देश्य	परीक्षित/ अपरीक्षित	सफल/असफल/ सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच का सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
			संख्या और डेटा, व्यक्तिगत सुनवाई निर्दिष्ट करना, अनुस्मारक तंत्र, देयता रजिस्टर - II, डीआरसी -03, डीआरसी -04, डीआरसी -05, स्वैच्छिक भुगतान रजिस्टर, कार्यवाही का समापन, पुष्टि की गई मांग, डीआरसी -07, एक ओआईओ का सृजन, करदाता के साथ संपर्क, डीआरसी -02, कॉल बुक, डी नोवो अधिनिर्णयन प्रक्रिया, अपेक्षित अवधि के लिए डेटा प्रतिधारण	
		असफल (37)	वसूली रजिस्टर, विवाद जीवनचक्र रजिस्टर, कर दरें, ब्याज और शास्ति, एससीएन का आवधिक निर्गमन, डीआरसी -02, डिजिटल हस्ताक्षर का अनुलग्नक, एससीएन जारी करने के लिए समय सीमा की गणना, लेखापरीक्षा प्रशासन द्वारा डीआरसी -03 का विवरण प्राप्त करना, वसूली रजिस्टर का अद्यतन करना, ओआईओ और डीआरसी-07 के साथ जारीकर्ता प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का अनुलग्नक, अपील दायर करने पर मांग का अद्यतन करना, डीआरसी-01 द्वारा ब्याज और शास्ति की गणना करना, डीआरसी-02 में जीएसटीआईएन का विवरण शामिल है	3.7.1.1 3.7.1.2 3.12.2 3.12.3
	अपरीक्षित (12)	सीमा प्रतिबन्ध (12)	डीआरसी-03 के सत्यापन के लिए 30 दिनों की सीमा, जीएसटीएन को डीआरसी-04 और डीआरसी-05 अद्येष्टित करना, सृजित किए गए और जीएसटीएन को भेजे गए डीआरसी -05 के लिए मामला संदर्भ संख्या जारी करना, विभिन्न एससीएन के आधार पर एक ओआईओ का सृजन, जहां डीआरसी -06 प्राप्त नहीं हुआ है वहां एक ओआईओ जारी करना, सृजित ओआईओ को अनुमोदित/संशोधित/हटाने के लिए अनुमोदन का प्राधिकार, एससीएन जारी करने की तिथि से ओआईओ जारी करने की समय सीमा का प्रवर्तन	-

लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ पाई गईं:

### 3.7.1.1 विवाद जीवनचक्र रजिस्टर का अभाव

एसआरएस के अनुसार, डीएसआर मॉड्यूल के भाग के रूप में एक विवाद जीवनचक्र रजिस्टर की परिकल्पना की गई थी। इसमें पांच रजिस्ट्रों अपुष्ट मांग रजिस्टर, पुष्ट मांग रजिस्टर, अपील रजिस्टर, वसूली रजिस्टर और एक स्वैच्छिक भुगतान रजिस्टर का विवरण शामिल किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विवाद जीवनचक्र रजिस्टर आज तक विकसित नहीं किया गया था और इसलिए प्रणाली ने विवाद मामले का दृष्टिकोण खंडों में प्रस्तुत किया। वर्तमान में, अपील और वसूली मॉड्यूल में केवल पृथक संग्रह सूचियों का अनुरक्षण किया जाता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन संग्रह सूचियों के डेटा को विवाद जीवनचक्र रजिस्टर विकसित होने पर इस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा या नहीं। लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संग्रह सूचियों से डेटा की पुनर्प्राप्ति परीक्षण किया गया था या नहीं।

विवाद जीवनचक्र रजिस्टर विकसित करने में निरंतर विलंब के कारण मामलों के डेटा का जीवनचक्र जांच के बिना प्रणाली में संचय होने का अंतर्निहित जोखिम है।

**सिफारिश 33: विभाग को डीएसआर (अधिनिर्णयन) मॉड्यूल के अंतर्गत विवाद जीवनचक्र रजिस्टर का विकास सुनिश्चित करना चाहिए।**

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति की ओर ध्यान दिलाए जाने पर (सितंबर 2021), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि विभिन्न मॉड्यूल में सभी कार्यात्मकताओं के विकास के बाद विवाद जीवनचक्र रजिस्टर विकसित किया जाएगा।

### 3.7.1.2 नियत तिथियों की निगरानी के लिए कार्यविधि का अभाव

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 और 74 के अनुसार, भुगतान नहीं किए गए या कम भुगतान किए गए या गलत तरीके से प्रतिदायित कर का अधिनिर्णयन आदेश, वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि या गलत प्रतिदाय की तिथि, जो भी लागू हो, से तीन साल की अवधि के भीतर

जारी किया जाएगा, और जानबूझकर गलत विवरण देने के मामले में, अधिनिर्णयन आदेश जारी करने की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ जाती है। इन मामलों के संबंध में एससीएन अधिनिर्णयन आदेश के लिए निर्धारित नियत तिथि से कम से कम तीन महीने पहले जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जीएसटी परिषद दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि को बदल सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कानून/जीएसटी परिषद द्वारा अधिदेशित संशोधन/विस्तार सहित इन नियत तिथियों को संशोधित/ अद्यतित करने के लिए कोई अंतर्निहित तंत्र नहीं था। जनवरी 2021 से जुलाई 2021 की अवधि से संबंधित शिकायत टिकटों पर डेटा की नमूना जांच से पता चला कि अधिकारी इस कार्यात्मकता की कमी के कारण धारा 73 के अंतर्गत मांग नोटिस (फॉर्म डीआरसी -01 में) जारी करने में सक्षम नहीं थे।

**सिफारिश 34: विभाग को रिटर्न मॉड्यूल के साथ एकीकरण में तिथियों को संशोधित/अद्यतित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की तकनीकी व्यवहार्यता पर चर्चा करनी चाहिए और मॉड्यूल में इसके लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।**

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (सितंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि जनवरी-2021 से जुलाई-2021 के दौरान डीआरसी-01 तैयार करने में अधिकारी को होने वाली कठिनाई से संबंधित टिकट, नियत तिथियों को संशोधित/अद्यतित करने के लिए कार्यात्मकता की अनुपलब्धता, के कारण नहीं थे। सभी टिकटों का निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा, नियत तिथियों को स्वचालित करने के लिए रिटर्न मॉड्यूल के साथ डीआरसी -01 कार्यात्मकता को एकीकृत करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा।

### **3.7.2 अपील, समीक्षा और संशोधन मॉड्यूल**

अपील मॉड्यूल में क) विभागीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के लिए आयुक्तालय स्तर पर समीक्षा और संशोधन करने ख) आयुक्त (अपील) के समक्ष- या तो विभाग द्वारा या करदाता द्वारा अपील दायर करने ग)

आयुक्त (अपील) द्वारा अपील में आदेश पारित करने और सहायक प्रक्रिया और घ) अपीलीय न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय आदि में दायर अपीलों के विवरण को अभिग्रहित करने की प्रक्रिया शामिल है।

अपील मॉड्यूल के विकास पर चरणबद्ध तरीके से विचार किया गया था। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के अंतर्गत कार्य (एपीएल 01 से 04) और अधिनिर्णयन आदेशों की समीक्षा से संबंधित चरण-। कार्यात्मकताएं आरंभ कर दी गई है। 21 उपयोग मामलों, अंतिम संस्करण - संशोधन प्रक्रिया और प्रतिप्रेषण निर्देश आदेश (एपीएल 05 से 08, आरवीएन 01) के साथ चरण II कार्यात्मकताओं के विकास के अधीन हैं।

तालिका 3.8 - संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

उप-उद्देश्य	परीक्षित/अपरीक्षित	सफल/असफल/सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच का सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
क्या एसआरएस जीएसटी अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, विभागीय निर्देशों और परिपत्रों के आधार पर तैयार किया गया है?	परीक्षित (12)	सफल (12)	फॉर्म जीएसटी एपीएल 02, दायर की गई अपील पर की गई कार्रवाई, अपील दायर करने से पहले की व्याप्त स्थितियां, पुनरीक्षण प्राधिकरण प्रक्रिया, शक्तियों का प्रत्यायोजन, फॉर्म जीएसटी एपीएल -04, अपील में कालानुक्रमिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए अपील रजिस्टर, समयसीमा का पालन	-
क्या अपील से संबंधित फॉर्म और कार्यात्मकताएं एसआरएस के अनुसार सृजित की गयी हैं?	परीक्षित (12)	सफल (5)	अपील मॉड्यूल डीएसआर चरण I (प्राथमिकता 1) का हिस्सा है, अपील की कार्यात्मक आवश्यकता, अपील से डी नोवो कार्यात्मकता, प्रतिदाय एकीकरण, डेटा प्रतिधारण	-
		असफल (7)	वसूली रजिस्टर, प्रतिदाय आदेश पर अपील दायर करने का तरीका, समीक्षा के लिए समय सीमा, यूसीडी और सीडी रजिस्टर और देयता रजिस्टर देखने का प्राधिकार	3.7.1.1 3.7.2.1 3.7.2.2

लेखापरीक्षा के दौरान अपील, समीक्षा और संशोधन मॉड्यूल के संबंध में निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ पाई गईं:

### 3.7.2.1 प्रतिदाय आदेश पर हस्त्य-रूप से अपील दायर करना

एसआरएस के अनुसार, आयुक्त (समीक्षा) के निर्णय के आधार पर, कार्यप्रवाह में दो विकल्प शामिल हैं- आदेश को स्वीकार करना और अपील दायर करना। परिकल्पित कार्यप्रवाह हस्त्य-रूप से हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले प्रतिदाय आदेशों की समीक्षा के मामले को छोड़कर, मांग आदेशों की समीक्षा के लिए कार्य कर रहा है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि प्रतिदाय आदेश की समीक्षा की प्रक्रिया ऑनलाइन तैयार की जाती है, परंतु समीक्षा प्रक्रिया के बाद, अधिकारी को हस्त्य-रूप से प्रतिदाय आदेश के विरुद्ध अपील दायर करनी होती है, जो एसआरएस प्रावधान के अनुरूप नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति दिए जाने पर (सितंबर 2021), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि (i) एपीएल-03 और (ii) प्रतिदाय आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की कार्यात्मकताएं आरंभ कर दी गयी थी।

इसके कार्यान्वयन की समीक्षा अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

### 3.7.2.2 समीक्षा के लिए समय सीमा का अभाव

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 109 के उप-नियम (ए) के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत पारित किए गए किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति के पास अपील दायर करने के लिए तीन महीने की समय सीमा होती है। इसी प्रकार, विभाग के पास अपील दायर करने के लिए छह महीने की समय सीमा होती है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि अपील मॉड्यूल प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार विकसित किया गया है कि करदाता और विभागीय अधिकारी क्रमशः 3 महीने और 6 महीने के बाद प्रणाली के माध्यम से अपील दायर नहीं कर सकते। तथापि, समीक्षा की निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रयोक्ता को सचेत करने के लिए प्रणाली में कोई तंत्र नहीं बनाया गया है, जिससे समीक्षा प्रक्रिया में विलंब का संभावित जोखिम होता

है, जो अपील के लिए निर्धारित सांविधिक समय-सीमा को प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (सितंबर 2021) के उत्तर में, विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि सीजीएसटी अधिनियम/नियम केवल उपयुक्त अपीलीय मंचों के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हैं, जिसे एप्लीकेशन में बनाया जा चुका है; हालांकि, अधिनिर्णय या अपील आदेशों की समीक्षा के लिए कोई अलग समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

महानिदेशक (सिस्टम्स) बंगलुरु ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को जीएसटी नीति विंग को सूचित किया जाएगा ताकि समय पर समीक्षा करने के संबंध में सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को समान दिशानिर्देश जारी किए जा सकें।

### 3.7.3 वसूली मॉड्यूल

वसूली मॉड्यूल जीएसटी और विरासती व्यवस्था के अंतर्गत पुष्ट मांग की वसूली में शामिल प्रक्रियाओं को अभिग्रहित करना था, जिसका उपयोग वसूली के लिए अधिकृत विभागीय अधिकारियों - रेंज अधिकारी से आयुक्त तक, महानिदेशक जीएसटी जांच, अपवंचन-रोधी और लेखापरीक्षा विंग द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कर की वसूली शामिल है जो अप्रदत्त रहता है और संवीक्षा, निर्धारण, अधिनिर्णयन और अपील प्रक्रिया के कारण करदाता द्वारा देय होता है। कर प्राधिकारी जीएसटी कानूनों में दिए गए वसूली के विभिन्न तरीकों को अपनाकर वसूली प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं।

तालिका 3.9 - संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

उप-उद्देश्य	परीक्षित/ अपरीक्षित	सफल/असफल/ सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच का सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
डीआरसी - 20 और डीआरसी - 21	परीक्षित (39)	सफल (22)	फॉर्म डीआरसी -20 भरना, क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को संबोधित करने के लिए तंत्र, पच्चीस हजार रुपये से कम की किस्त राशि की जांच, प्राधिकृत अधिकारी की जांच करना, आस्थगित भुगतान का आवेदन/सीबीआईसी - जीएसटी	-

उप-उद्देश्य	परीक्षित/ अपरीक्षित	सफल/असफल/ सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच का सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
			बैंकएंड एप्लिकेशन पर किस्त में भुगतान का अवतरण , वैध क्रेडेंशियल , वसूली की स्थिति, डीआरसी -07 ए के इनपुट की शुरुआत करना, कार्य का दायित्व सौंपना, "मार्क टू" विकल्प, क्षेत्राधिकार रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना, क्षेत्राधिकार रिपोर्ट उप टैब पर सीधे पहुंचना, "पुट अप" कार्यात्मकता का कार्यचालन, किस्त/आस्थगित भुगतान का अद्यतित खाता-बही और रजिस्टर देखने का अभिगम, मामले के विवरण की उपलब्धता, संग्रह सूची की दृश्यता, पुरालेख में प्रत्येक डीआरसी -21 आदेश का पूरा विवरण देखना	
		असफल (17)	स्वतः संज्ञान लेते हुए समय का विस्तार, डीआरसी-21 के अधिकृत निर्गमन की जांच, चूककर्ता की जांच, वसूली के संबंध में अंतर्निहित तंत्र, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किस्त का भुगतान, वसूली रजिस्टर का अद्यतन, कार्य सूची प्रदर्शित करना, विवाद जीवनचक्र के पूर्ण आदेश विवरण को देखना, नई क्षेत्राधिकार रिपोर्ट जोड़ना, सत्यापन रिपोर्ट प्रश्नावली को सक्षम करना, रिटर्न देखने की पहुंच, करदाता द्वारा की गई मांग का इतिहास, सारांश लिंक खंड के अंतर्गत अतिरिक्त फोल्डर "डीआरसी -21" जोड़ना, डीआरसी -21 हाइपरलिंक, ट्रिगर तंत्र, भुगतान में चूक पर विचार करना	3.7.3.1
	अपरीक्षित (2)	सत्यापित नहीं किया जा सका (2)	चौबीस से कम मासिक किस्तों की जांच करना, जीएसटीएन पोर्टल में लॉग इन करने और किस्तों में	-

उप-उद्देश्य	परीक्षित/ अपरीक्षित	सफल/असफल/ सीमा प्रतिबन्ध	लेखापरीक्षा जांच का सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
			आस्थगित भुगतान / भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम करदाता (डीआरसी - 20)	
डीआरसी - 07 ए	परीक्षित (8)	सफल (7)	मौजूदा कानूनों के अंतर्गत बकाया की वसूली की प्रक्रिया, आदेश की मांग को दर्ज करना, विरासती बकाया मॉडल के अंतर्गत डेटा दर्ज करना, डीआरसी-07ए के इनपुट को प्रणाली में आरंभ करना, मांग के विवरण और ईसीएल को अद्यतित करना, अपील जैसे अन्य मॉड्यूल में सृजित की गई मांग आईडी/वसूली आईडी का एकीकरण, जीएसटी कानूनों के अंतर्गत वसूली के लिए केवल वसूली योग्य मांगों को दर्ज किया जाएगा	-
		असफल (1)	वसूली रजिस्टर का अद्यतन	3.7.1.1
डीआरसी - 08 ए	परीक्षित (6)	सफल (6)	आवेदन पत्र डीआरसी-08ए को सीबीआईसी पोर्टल में प्रस्तुत करने के लिए कार्यात्मकता, मांग का विवरण और ईसीएल को अद्यतित करना, अपील जैसे अन्य मॉड्यूल में सृजित की गई मांग आईडी/वसूली आईडी का एकीकरण, फॉर्म जीएसटी डीआरसी-08ए के माध्यम से स्थिति में संशोधन, सामान्य पोर्टल पर सार अपलोड करना, इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के भाग II का अद्यतन करने की कार्यात्मकता	-

वसूली मॉड्यूल में डीआरसी 09 से डीआरसी 25 और डीआरसी 07 ए, डीआरसी 08 ए के फॉर्म द्वारा दर्शाए गए वसूली और विरासती बकाया शामिल हैं। डीआरसी 07ए, डीआरसी 08ए, डीआरसी 20 और डीआरसी 21 के लिए दो आयामों - विरासती बकाया की वसूली (डीआरसी 07 ए और 08

ए) और किस्तों में बकाया की वसूली (डीआरसी 20 और 21) को दर्शाने वाली कार्यात्मकताएं लेखापरीक्षा के समय ही आरंभ की गई थीं।

बकाया राशि की वसूली अन्य साधनों से- तीसरा पक्ष, कर योग्य वस्तुओं की बिक्री, अचल और चल संपत्तियों की कुर्की, जुर्माने के रूप में वसूली आदि, जो फॉर्म डीआरसी 9 से डीआरसी 19, डीआरसी 22 से डीआरसी 25 द्वारा दर्शाए जाते हैं, से संबंधित कार्यात्मकताओं के लिए एकीकरण प्रगति पर था। महत्वपूर्ण वसूली रजिस्टर विकसित नहीं किया गया था, हालांकि एसआरएस में इसकी परिकल्पना की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति की ओर इंगित किए जाने पर (सितंबर 2021) मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार (अगस्त 2022) करते हुए कहा कि अन्य स्रोतों (डीआरसी फॉर्म 9 से 19, 22 से 25) से उत्पन्न होने वाली वसूली प्रक्रिया को प्रस्तुतीकरण के लिए परिनियोजित/कार्यान्वित कर दिया गया था। महत्वपूर्ण वसूली रजिस्टर को एमआईएस के एक भाग के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसके कार्यान्वयन की समीक्षा अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

### 3.7.3.1 लेखापरीक्षा में वसूली माँड्यूल के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- (i) डिमांड हिस्ट्री टैब को हाइपरलिंक जैसा कि परिकल्पित किया गया था के बिना प्रदान किया गया था, जिससे निम्न का विवरण प्रदान नहीं किया गया:
  - डिमांड आईडी के लिए किस्त भुगतान/आस्थगित भुगतान विवरण के साथ डीआरसी 20 की स्थिति
  - डिमांड आईडी के लिए संग्रह सूची में भुगतान अद्यतन स्थिति के साथ डीआरसी 21 की स्थिति
  - कुल मांग, देय शेष राशि के साथ भुगतान की गई राशि को केवल कुल राशि के रूप में उल्लेख किया गया है

- (ii) डीआरसी 21 के मामले में करदाता की सामान्य जानकारी के लिए हाइपरलिंक भी विकसित नहीं किए गए थे
- डीआरसी 21 के मामले में करदाता द्वारा किशतों में किए गए भुगतान का विवरण देखने की कार्यात्मकता लागू नहीं की गई थी
  - डीआरसी 21 के मामले में नई क्षेत्राधिकार रिपोर्ट बनाने के विकल्प को कार्यान्वित नहीं किया गया था
  - प्रत्येक अधिकारी की कार्यसूची डैशबोर्ड पर डीआरसी 20 (आस्थगित भुगतान/किशतों में भुगतान के लिए आवेदन) के प्रसंस्करण के लिए आयु-वार लंबन को इंगित करने के लिए कलर कोडिंग कार्यान्वित नहीं की गई थी

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (सितंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार (अगस्त 2022) कर लिया।

### 3.8 निर्यात मॉड्यूल

तालिका 3.10 - संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

उप-उद्देश्य	परीक्षित/अपरीक्षित	सफल/असफल/सीमा प्रतिबंध	लेखापरीक्षा जांच का सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
क्या निर्यात की कार्यात्मकताओं को परिकल्पना के अनुसार डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है	अपरीक्षित (5)	-	अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार एसआरएस तैयार करना, समय-सीमा का पालन करना, फॉर्म और कार्यात्मकताओं में एसआरएस का प्रभाव, जीएसटीएन और अन्य इंटरफेस	अभी तक विकसित नहीं किया गया है

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्यात मॉड्यूल का विकास आरंभ नहीं हुआ था और डीजी (सिस्टम्स), विप्रो और आईसगेट/आईसीईएस के साथ तकनीकी व्यवहार्यता और पूर्ण एक्जिम डेटा हस्तांतरित करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा के चरण में था।

**सिफारिश 35: विभाग को समय पर निर्यात मॉड्यूल के विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।**

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति की ओर इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि उन्होंने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया है।

### 3.9 लेखापरीक्षा मॉड्यूल

तालिका 3.11 - संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

उप-उद्देश्य	परीक्षित/ अपरीक्षित	सफल/असफल/सीमा प्रतिबंध	लेखापरीक्षा जांच का सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
क्या लेखापरीक्षा मॉड्यूल की कार्यात्मकताओं को परिकल्पना के अनुसार डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है	परीक्षित (5)	सफल (1)	अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार एसआरएस तैयार करना	-
		सीमा प्रतिबंध (4)	समयसीमा का पालन, फॉर्म और कार्यात्मकताओं में एसआरएस का प्रभाव, जीएसटीएन और अन्य इंटरफेस	3.9

लेखापरीक्षा मॉड्यूल के लिए एसआरएस की तैयारी मई 2017 में आरंभ हुई थी और लेखापरीक्षा के समय मॉड्यूल अभी भी विकास के अधीन था।

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति की ओर इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने कहा कि लेखापरीक्षा मॉड्यूल 1 अप्रैल 2022 को आरंभ किया गया था।

इसकी (लेखापरीक्षा मॉड्यूल) समीक्षा अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं में की जाएगी।

### 3.10 करदाता एक नज़र में - टीएजी

तालिका 3.12 - संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

उप-उद्देश्य	परीक्षित/ अपरीक्षित	सफल/असफल/ सीमा प्रतिबंध	लेखापरीक्षा जांच का सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
क्या टीएजी मॉड्यूल की कार्यात्मकताओं को परिकल्पना के अनुसार डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है	अपरीक्षित (5)	-	अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार एसआरएस तैयार करना, समय-सीमा का पालन करना, फॉर्म और कार्यात्मकताओं में एसआरएस का प्रभाव, जीएसटीएन और अन्य इंटरफेस	अभी तक विकसित नहीं हुआ है

लेखापरीक्षा ने पाया कि मॉड्यूल का विकास आरंभ नहीं हुआ था। विभाग ने कहा कि विक्रेता को एसआरएस तैयार करने के लिए सितंबर 2020 में टीएजी आवश्यकताएं दी गई थीं। विक्रेता द्वारा एसआरएस का मसौदा प्रस्तुत किया जाना शेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि टीएजी के विकास की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी क्योंकि महानिदेशक सिस्टम के अधीन अद्वैत परियोजना ने पहले ही इसी तरह का डैशबोर्ड "अपने करदाता को जानें" कार्यान्वित किया था।

### 3.11 मोबाइल एप्लीकेशन

तालिका 3.13 - संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स

उप-उद्देश्य	परीक्षित/ अपरीक्षित	सफल/असफल/ सीमा प्रतिबंध	लेखापरीक्षा जांच का सार	टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
क्या मोबाइल ऐप मॉड्यूल परिकल्पना के अनुसार डिजाइन और कार्यान्वित किए गए हैं	परीक्षित (5)	सफल (1)	अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के अनुसार एसआरएस तैयार करना	-
		असफल (4)	समयसीमा का पालन, परिचालन के पूरे स्पेक्ट्रम का कवरेज, जीएसटीएन और अन्य इंटरफेस	विकास के अधीन

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि मोबाइल एप्लीकेशन विकास के अधीन था।

**सिफारिश 36: विभाग को समय पर मोबाइल एप्लीकेशन के विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि मोबाइल एप्लीकेशन के विकास और परिनियोजित करने में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

### 3.12 क्रॉस-कटिंग मामले

#### 3.12.1 मॉड्यूल में उपयोगकर्ता गतिविधि विवरण

आरएफपी (खंड 7.1 (2 जे)) के अनुसार, परिकल्पित उपयोगकर्ता गतिविधि विवरण को पोर्टल में एक व्यापक ऑडिट ट्रेल सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए जैसे कि:

- दैनिक गतिविधियों के विवरण को पूर्व वृत्त विवरण फाइलों के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए
- दिनांक, समय और उपयोगकर्ता-मुद्रांकित संव्यवहार जांच-सूची को विभिन्न संव्यवहारों के लिए ऑनलाइन सृजित किया जाना चाहिए
- सभी संव्यवहारों के स्क्रीन पर सिस्टम की जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए
- दिन के दौरान संसाधित किए जा रहे सभी संव्यवहारों को उजागर करने के लिए दैनिक गतिविधि रिपोर्ट प्रदान की जानी चाहिए

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि एप्लीकेशन में विभिन्न फॉर्म के ट्रेल्स अनुरक्षित किए जा रहे थे, फिर भी मसौदा चरण में पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर फॉर्म में अलग से किए गए परिवर्तनों की विषय वस्तु को दर्ज और संग्रहीत नहीं किया जा रहा था। मसौदे को प्रस्तुत करने/वापसी/प्रत्यायोजन के समय टिप्पणियाँ दर्ज करने के लिए एक इनपुट फील्ड 'टिप्पणियाँ' मौजूद है। टिप्पणियों के लिए बनाया गया यह फील्ड संस्करण नियंत्रण के लिए एक वैकल्पिक तंत्र नहीं हो सकता।

इसलिए, केवल अंतिम अनुमोदन की विषय वस्तु दर्ज की गई थी और फॉर्म के अनुमोदन/अस्वीकृति से पहले अधिकारियों द्वारा अद्यतन (संवर्धन/विलोपन/संशोधन) को न तो उनके संबंधित एसएसओआईडी में चित्रित किया गया था और न ही अभिलेख का हिस्सा बनाया गया था। कार्यप्रवाह गतिविधि में संस्करण नियंत्रण सुविधा अनुपस्थित पाई गई।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (सितंबर 2021) जारी की गई थी। मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार कर लिया और उत्तर दिया (अगस्त 2022) कि

सुझाए गए संस्करण नियंत्रण कार्यात्मकता का कार्यान्वयन तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन किया जाएगा।

**सिफारिश 37: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोर्टल उपयोगकर्ता गतिविधि विवरण के हिस्से के रूप में कार्यप्रवाह में प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों/संशोधनों या कम से कम महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अभिग्रहित कर सकता है।**

### 3.12.2 किसी भी मॉड्यूल में डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर का कार्यान्वयन न होना

डिजिटल हस्ताक्षर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया का उपयोग करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रमाणीकरण के साधन के रूप में अधिदेशित किया गया है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करती है या जानकारी की शुद्धता को प्रमाणित करती है, जिसके परिणामस्वरूप गैर-अस्वीकृति जिम्मेदारी को अस्वीकार करने में असमर्थता होती है।

सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 26 (3) के अनुसार, सीजीएसटी नियमावली, 2017 के अध्याय-III के प्रावधानों के अंतर्गत सभी नोटिस, प्रमाण पत्र और आदेश उचित अधिकारी द्वारा या ऐसे नोटिस या प्रमाण पत्र या आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से अथवा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के माध्यम से या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन के किसी अन्य विधि द्वारा सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, विक्रेता (प्रमुख सेवा करार - एमएसए) के साथ की गई संविदा में निम्नलिखित अनुबंध किए गए हैं:

- करदाताओं के साथ सभी संचार के लिए सुरक्षित प्रमाणीकरण के लिए समर्थन सुरक्षा प्रोटोकॉल, डिजिटल प्रमाणपत्र और ई-हस्ताक्षर की

तकनीकी आवश्यकता का अनुपालन किया जाना है (एमएसए का पैरा 7.2 - समाधान की गैर-कार्यात्मक आवश्यकताएं) ।

- पंजीकृत करदाताओं और विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा अभिगम के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को सक्षम बनाने वाली प्रणाली के संबंधित मॉड्यूल को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (एमएसए का पैरा 1.1 (ई) एसीएल की मुख्य विशेषताएं) में बनाया जाना है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि डिजिटल हस्ताक्षरों को किसी भी मॉड्यूल में शामिल और अपनाया नहीं गया है। इसे स्थापित करने के लिए, लेखापरीक्षा ने यादृच्छ रूप से पंजीकरण प्रमाण पत्रों की नमूना जांच की और पाया कि नियमों द्वारा अधिदेशित उचित अधिकारी के हस्ताक्षर/ई-सत्यापन कोड पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, डीमंड अनुमोदित माने गए पंजीकरणों के संबंध में, यद्यपि उचित अधिकारी से डीमंड माने गए अनुमोदन के लिए निर्धारित अवधि के बाद तीन दिनों के भीतर प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से प्रमाणित करना अपेक्षित है, फिर भी उचित अधिकारी द्वारा इस प्रकार के प्रमाणीकरण करने का कोई साक्ष्य नहीं था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में (सितंबर 2021), विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि वर्तमान में सर्वर-आधारित डीएससी लागू किया गया है और सभी मॉड्यूल के संबंध में डिजिटल हस्ताक्षर के मामले पर कार्य किया जा रहा है और शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा। हालांकि, डीमंड मानित पंजीकरण के मामले में यह सूचित किया गया था कि किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

इस संबंध में, उत्तर प्राप्त होने पर (मार्च 2021), लेखापरीक्षा ने पंजीकरण प्रमाण पत्र के सर्वर स्तर के प्रमाणीकरण/सत्यापन की अनुमति देने वाली बोर्ड की अधिसूचना की प्रति मांगी थी (जून 2021)। हालांकि, लेखापरीक्षा को प्रति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

इसके अलावा, विभाग का यह तर्क मान्य नहीं है कि नियम 10 (5) के अंतर्गत जारी आरसी के लिए किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नियम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि नियम 9 के उप-नियम (5) के अंतर्गत प्रदान किए गए पंजीकरण इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित किए जाएंगे और नियम में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर आवेदक को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है कि बोर्ड ने सर्वर आधारित डीएससी की अनुमति दी थी क्योंकि यह वैधानिक दस्तावेजों और पंजीकरण प्रमाणपत्रों के लिए पर्याप्त नहीं है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी (अप्रैल 2022) की गई थी और मंत्रालय ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कहा (सितंबर 2022) कि वह अपने उत्तर (अगस्त 2022) "सीबीआईसी एसएसओआईडी आधारित लॉगिन का उपयोग करके सर्वर स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करता है" को संशोधित करने पर विचार करेगा; यह प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

तथ्य यह है कि आईटी अधिनियम 2000 और विक्रेता (प्रमुख सेवा करार - एमएसए) के साथ की गई संविदा में डिजिटल हस्ताक्षर कार्यात्मकता या ई-हस्ताक्षर का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार का डीएससी या ई-हस्ताक्षर (आमतौर पर आधार आधारित) एक गैर-अस्वीकार्य, सत्यापन योग्य तरीके से एक एकल अधिकारी की पहचान की पुष्टि करता है, जिसे सर्वर आधारित डीएससी के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

**सिफारिश 38: विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एकल अधिकारी द्वारा गैर-अस्वीकार्य तरीके से वैधानिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए उचित डिजिटल हस्ताक्षर कार्यात्मकता को सभी मॉड्यूल में शामिल किया और अपनाया जाए।**

### 3.12.3 ब्याज की हस्त्य-रूप से गणना

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के साथ पठित धारा 73 और 74 के अनुसार, जब भी मांग की वसूली की जाती है तो कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज उद्ग्रहणीय है। ब्याज की गणना कर भुगतान की देय

तिथि के अगले दिन से भुगतान की तिथि तक की जाएगी। अधिसूचित ब्याज दर 1 जुलाई 2017 से 18 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी माँड्यूल में ब्याज की गणना हस्त्य-रूप से करने की अभिकल्पना की गई थी, जिससे इसमें गणना संबंधित गलतियाँ होने का जोखिम था। यह देखते हुए कि मांग की पुष्टि होने के बाद देय कर निर्धारित किया जाता है और ब्याज की गणना में आमतौर पर त्रुटियों की संभावना होती है, तो सर्वोत्तम पद्धति देय कर, अवधि और इनपुट के रूप में प्रदान की जा रही ब्याज दर के अपेक्षित विवरण के साथ ब्याज की गणना को स्वचालित करने के लिए एक सुविधा को शामिल करना होगा।

***सिफारिश 39: विभाग को यथापरिकल्पित ब्याज की स्वचालित गणना के लिए कार्यात्मकता के विकास में तेजी लानी चाहिए।***

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (सितंबर 2021) के उत्तर में, मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2022) कि इस मामले को जीएसटीएन के समक्ष उठाया जा रहा है।



## अध्याय IV: अन्य आईटी एप्लीकेशन के साथ इंटरफ़ेस

लेखापरीक्षा उद्देश्य में आश्वासन मांगा गया था कि क्या अन्य एप्लीकेशन के साथ इंटरफ़ेस के लिए प्रौद्योगिकी समाधान प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं और परिकल्पित व्यावसायिक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर रहे हैं। प्रलेखन, एकीकरण और कार्यात्मकताओं की प्रभावशीलता, सुरक्षा और ऑडिट ट्रेल के संदर्भ में सभी आयामों के लिए लेखापरीक्षा जांच (ऑडिट चेक) विकसित किये गए थे।

सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन की कल्पना करते समय, यह परिकल्पना की गई थी कि सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से अन्य प्रणालियों/एप्लीकेशन के साथ इंटरफ़ेस प्रदान करेगा। बाह्य इंटरफ़ेस जीएसटीएन, राज्य प्रणालियों, आरबीआई, बैंकों, डीजीएफटी, एमसीए 21, सीबीडीटी, यूआईडीएआई, आइसगेट, आईसीईएस, आरएमएस, एसीईएस, ईडीडब्ल्यू आदि के साथ होना चाहिए। आंतरिक रूप से, इंटरफ़ेस एप्लीकेशन के विभिन्न मॉड्यूलों के अंतर्गत होना चाहिए।

यह पाया गया कि जीएसटीएन के साथ सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन इंटरफ़ेस स्थापित किया गया है, परंतु अन्य बाह्य प्रणालियों और एजेंसियों जैसे राज्य प्रणालियों, आरबीआई, बैंकों, डीजीएफटी, एमसीए 21, सीबीडीटी, यूआईडीएआई, आइसगेट, आईसीईएस, आरएमएस, एसीईएस, ईडीडब्ल्यू आदि के साथ इंटरफ़ेस तंत्र का विकास अभी तक आरंभ नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आधार प्रमाणीकरण और पंजीकरणों में संशोधनों के कार्यान्वयन के मामले में सामान्य पोर्टल से डेटा स्वीकार करते समय सत्यापन नियंत्रण अपर्याप्त थे।

मिलान की कमी के कारण जीएसटी सामान्य पोर्टल और सीबीआईसी एप्लीकेशन के बीच डेटा के बेमेल होने के दृष्टांत थे।

## 4.1 विभाग के प्रमुख निर्णयों को प्रभावित करने वाले इंटरफेस से

### संबंधित मामले

सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी का प्राथमिक इंटरफेस, जीएसटीएन द्वारा विकसित एपीआई के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली जीएसटी प्रणाली के साथ है। जीएसटी सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करदाता से संबंधित डेटा/सूचना जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, फाइल किए गए रिटर्न आदि का वास्तविक समय के आधार पर अन्यत्र संबंधित स्थानों पर प्रवाह होना चाहिए।

डेटा विश्लेषण का उपयोग करते हुए लेखापरीक्षा के दौरान मौलिक परीक्षण के आधार पर, लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए इंटरफेस से संबंधित मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

#### 4.1.1 अपर्याप्त वैधीकरण नियंत्रणों के परिणामस्वरूप अनिवार्य फ़िल्ड में रिक्त मान प्रदर्शित

'आधार से जुड़े पंजीकरण आवेदनों के भौतिक सत्यापन' पर एसआरएस संस्करण 1.0 निर्दिष्ट करता है कि आधार सत्यापन के आधार पर जीएसटी पोर्टल, नीचे सूचीबद्ध परिदृश्यों के अनुसार आगे के प्रसंस्करण के लिए पंजीकरण की जानकारी सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन को भेजेगा:

तालिका 4.1 - आधार परिदृश्य

चुना हुआ आधार सत्यापन का विकल्प	आधार सत्यापन की स्थिति	अनिवार्य भौतिक सत्यापन
हाँ	सत्यापित	नहीं
हाँ	असफल	हाँ
नहीं	लागू नहीं	हाँ

इसके अलावा, एसआरएस यह भी निर्दिष्ट करता है कि असफल आधार सत्यापन/ आधार सत्यापन के लिए विकल्प चयन नहीं किए जाने पर आरईजी - 01 नए पंजीकरण आवेदनों को जीएसटी पोर्टल पर "अनिवार्य भौतिक सत्यापन" के लिए चिह्नित किया जाएगा और इसे परिसर के भौतिक सत्यापन के बाद ही संसाधित होने दिया जाएगा।

नियमों में उपरोक्त परिवर्तन जीएसटीएन द्वारा लागू किए गए थे (21 अगस्त 2020)। एपीआई में परिवर्तन का उपयोग तत्काल प्रभाव से सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन द्वारा किया गया था और एआरएन को उनकी इस स्थिति के साथ सीपीसी अधिकारियों के डैशबोर्ड पर दर्शाया गया था कि इन एआरएन को पीवी के लिए चिह्नित किया गया था या नहीं (डीजी सिस्टम एडवाइजरी संख्या 26/2020 दिनांक 12 अक्टूबर 2020)।

लेखापरीक्षा ने 21 अगस्त 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच दायर पंजीकरण प्रदान किए गए आवेदनों (एआरएन), के लिए सीबीआईसी डेटाबेस से निकाले गए अखिल भारतीय डेटा की जांच की। ऐसे 6,60,263 मामलों में से 25,864 मामलों में यह पाया गया कि अनिवार्य 'आधार सत्यापन स्थिति' फ़ील्ड और 'अनिवार्य भौतिक सत्यापन' फ़ील्ड में रिक्त मान प्रदर्शित हो रहा था। जीएसटीएन पोर्टल से 'आधार सत्यापन स्थिति' के लिए चेन्नई से संबंधित 75 मामलों की नमूना जांच पर यह पाया गया कि 35 मामलों में सत्यापन की स्थिति 'प्रमाणीकृत नहीं' थी, जिससे यह अर्थ निकलता है कि इन मामलों में सीजीएसटी नियमों के अनुसार भौतिक सत्यापन अनिवार्य था। हालांकि, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में यह पाया गया कि इन 35 मामलों के लिए कोई अनिवार्य भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

अनिवार्य के रूप में चिह्नित किए गए फ़ील्ड के लिए सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन द्वारा रिक्त मान की स्वीकृति सत्यापन नियंत्रण में कमियों को दर्शाती है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति को इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि उन्होंने अनुपालन के लिए अभ्युक्ति को नोट कर लिया है।

**4.1.2 स्वतः संज्ञान पंजीकरण के अंतर्गत अस्थायी पंजीकरण संख्या (टीआरएन) के सृजन पर उचित अधिकारियों को अलर्ट देने की कार्यविधि का अभाव**

नियम 16 (1) के अनुसार, जहां अधिनियम के अंतर्गत किसी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या किसी अन्य कार्यवाही के आधार पर, उचित अधिकारी को पता चलता है कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए दायी व्यक्ति इस प्रकार के पंजीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहा है, तो ऐसा अधिकारी उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर पंजीकृत कर सकता है और आरईजी -12 में एक आदेश जारी कर सकता है। ऐसा अस्थायी पंजीकरण प्रदान किए गए व्यक्ति को अस्थायी पंजीकरण प्रदान किए जाने के 90 दिनों की अवधि के भीतर आरईजी -01 प्रस्तुत करके नियमित पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए (नियम 16 (3))। ऐसे मामलों में पंजीकरण की प्रभावी तिथि अस्थायी पंजीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तिथि होगी (नियम 16 (5))।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि पूर्वोक्त नियम 16 के अंतर्गत पारित किए गए आदेश के आधार पर प्राप्त नए पंजीकरण के एआरएन को मान्य करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, टीआरएन को, क्षेत्राधिकार से जोड़ने के लिए कार्यविधि, ताकि कर अधिकारी यह निगरानी करने में सक्षम हो सके कि करदाता द्वारा स्वतः संज्ञान आदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं, का अभाव था।

इसके अलावा, पर्याप्त लिंकेज के अभाव में स्वतः संज्ञान आदेश के विरुद्ध अपील पर प्रतिदाय की स्वीकृति, यदि कोई हो, संभव नहीं हो सकती। स्वतः संज्ञान पंजीकरण के मामलों में पंजीकरण की प्रभावी तिथि को मान्य किया जाना चाहिए क्योंकि जीएसटी के प्रति देयता आदेश जारी होने की तिथि से उत्पन्न होती है।

अखिल भारतीय स्तर पर स्वतः संज्ञान पंजीकरणों के लिए निकाले गए डेटा से पता चला कि 01 जून 2019 से 31 मई 2021 की अवधि के दौरान 61 मामलों में स्वतः संज्ञान के आधार पर पंजीकरण प्रदान किया गया था।

**सिफारिश 40:** *विभाग को इस मामले पर जीएसटीएन और पॉलिसी विंग के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि क्षेत्राधिकार को टीआरएन के साथ जोड़ने के लिए एक उपयुक्त कार्यविधि तैयार की जा सके।*

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति को इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि उन्होंने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया है।

#### **4.1.3 एक ही पैन के साथ किए गए पंजीकरणों में संशोधनों को लागू करने के लिए अपर्याप्त वैधीकरण**

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 28 के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 19 (1) (ए) (बी) में पंजीकरण प्राप्त करते समय या समय-समय पर संशोधित सभी प्रकार के पंजीकरणों के लिए आवेदन में प्रस्तुत किसी भी विवरण में किसी भी परिवर्तन के लिए प्रावधान किया गया है। परंतुक में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्यवसाय के कानूनी नाम से संबंधित परिवर्तन एक ही स्थायी खाता संख्या (पैन) पर प्राप्त पंजीकृत व्यक्ति के सभी पंजीकरणों के लिए लागू होगा।

01 जुलाई 2017 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के लिए सीबीआईसी डेटाबेस से 32,152 मामलों का अखिल भारतीय डेटा निकाला गया था, जिसमें एक ही पैन के अंतर्गत जीएसटीआईएन के लिए विभिन्न कानूनी नाम शामिल थे। 25 विशिष्ट पैन की यादृच्छ नमूना जांच पर यह पाया गया कि 10 मामलों में एक ही पैन के अंतर्गत प्राप्त पंजीकरणों में से एक में व्यवसाय के कानूनी नाम में संशोधन उसी पैन पर प्राप्त अन्य सभी पंजीकरणों पर लागू नहीं किया गया था।

***सिफारिश 41: विभाग को एक ही पैन के अंतर्गत अन्य सभी पंजीकरणों के लिए व्यवसाय के कानूनी नाम में किए गए संशोधनों को लागू करने के लिए कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए।***

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति को इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि उन्होंने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया है।

#### 4.1.4 जीएसटी सामान्य पोर्टल और सीबीआईसी डेटाबेस के बीच डेटा के बेमेल होने के दृष्टांत

यादृच्छ रूप से चुने गए 50 मामलों<sup>25</sup> के लिए आधार सत्यापन स्थिति फील्ड की तुलना जीएसटीएन पोर्टल में उपलब्ध आधार सत्यापन डेटा के साथ की गई और यह पाया गया कि 21 मामलों में डेटा बेमेल था। इसी प्रकार, 25 मामलों के लिए 'करदाता प्रकार' फील्ड में निहित डेटा की तुलना से 15 मामलों में डेटा के बेमेल होने का पता चला। इसके अलावा, भुगतान एडवाइजरी 3 में यह कहा गया था कि खाता-बही में प्रविष्टियां अद्यतित नहीं हो रही हैं और इसलिए खाता-बही के डेटा में अंतर हैं। सामान्य पोर्टल और सीबीआईसी डेटाबेस के बीच डेटा का बेमेलता डेटा की विश्वसनीयता पर चिंता/ प्रश्न पैदा करती है तथा गलत एमआईएस रिपोर्टिंग की संभावना की ओर संकेत करती है।

**सिफारिश 42: विभाग को सभी माँड्यूल के लिए दिन के अंत में मिलान तंत्र (इंटरफ़ेस आधारित) लागू करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीबीआईसी डेटाबेस में डेटा हमेशा जीएसटीएन डेटाबेस के अनुरूप है।**

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति को इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि उन्होंने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया है।

#### 4.1.5 सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन और जीएसटीएन पोर्टल में उपलब्ध स्थायी खाता संख्या (पैन) के बीच विसंगतियां

पंजीकरण पर जीएसटीएन एसआरएस संस्करण 7.00 के अनुसार, पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले नए आवेदक को पंजीकरण फॉर्म के भाग-ए को भरना आवश्यक है, जिसमें राज्य और जिले के साथ कानूनी नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन), ईमेल पता और मोबाइल नंबर शामिल हैं। जीएसटी पोर्टल यह मान्य करेगा कि भाग-ए में उल्लिखित पैन और कानूनी नाम सीबीडीटी डेटाबेस से मेल खाते हैं या नहीं। इसके सफल वैधीकरण पर, एक अस्थायी संदर्भ संख्या (टीआरएन) सृजित होती है और आवेदक को भेजी जाती है। टीआरएन का उपयोग आवेदन को पुनः प्राप्त करने और

<sup>25</sup> चेन्नई ज़ोन की लेखापरीक्षा को प्रदान किये हुए एसएसओआईडी के माध्यम से सत्यपित

जीएसटीआईएन के अनुमोदन और सृजन के लिए पंजीकरण फॉर्म के भाग बी को भरने के लिए किया जाता है।

सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 10 के अनुसार, जहां नियम 9 के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन को मंजूरी दे दी गई है, वहां फॉर्म जीएसटी आरईजी -06 में पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र, जिसमें व्यवसाय का प्रमुख स्थान और व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शाते हुए, आवेदक को सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा और एक माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) निम्नलिखित अंकों/वर्णों के अधीन सौंपी जाएगी, निम्नानुसार:

- राज्य कोड के लिए दो अंक/वर्ण
- स्थायी खाता संख्या या कर कटौती के लिए दस अंक/वर्ण
- संग्रह खाता संख्या
- इकाई कोड के लिए दो अंक/वर्ण
- एक चेकसम अंक/वर्ण

सीबीआईसी डेटाबेस से एक अखिल भारतीय डेटा निकाला गया था जिसमें सीबीआईसी डेटाबेस में उपलब्ध पैन के साथ जीएसटीआईएन (तीसरे अंक/वर्ण से 12 वें अंक/वर्ण तक) में पैन बेमेल था। सीबीआईसी डेटाबेस से 01 जुलाई 2017 से 01 अक्टूबर 2021 की अवधि के लिए इस प्रकार की बेमेलता वाले कुल 57,693 जीएसटीआईएन निकाले गए थे। इन 57,693 मामलों में से, चेन्नई से संबंधित 8 मामलों को लेखापरीक्षा एसएसओआईडी का उपयोग करके सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के साथ प्रति सत्यापित किया गया था और पैन के बीच बेमेल की पुष्टि की गई थी। इसके अलावा, जीएसटीएन पोर्टल में उपलब्ध विवरण के साथ आठ में से दो मामलों की जांच से पता चला कि कानूनी नाम गलत थे और जीएसटीआईएन से संबंधित नहीं थे।

एक ही जीएसटीआईएन के लिए सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन में दो पैन का होना अर्थात्, सीबीआईसी डेटाबेस में उपलब्ध पैन नंबर के साथ जीएसटीआईएन (तीसरे अंक/वर्ण से 12 वें अंक/वर्ण तक) में पैन का बेमेल

होना और यह तथ्य कि आरसी (जो जीएसटीएन प्रणाली से सीबीआईसी डेटाबेस में एकत्रित गैर-संपादन योग्य पीडीएफ दस्तावेज हैं) जीएसटीआईएन की तुलना में गलत कानूनी नामों को दर्शाती है, सीबीआईसी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा की विश्वसनीयता पर प्रश्न पैदा करती हैं। उपर्युक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, लेखापरीक्षा को यह स्पष्ट नहीं था कि सीबीडीटी डेटाबेस में अनुमोदन और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वास्तव में कौन सा पैन सत्यापित किया गया था।

**सिफारिश 43: विभाग को पैन में बेमेल होने, आरसी में गलत कानूनी नामों की मौजूदगी और सही पैन के विवरण, जिसके आधार पर आरसी जारी किए गए थे, के मामलों का मिलान करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।**

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति को इंगित किए जाने पर (नवंबर 2021) मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि उन्होंने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया है।

#### 4.2 अन्य आईटी एप्लीकेशन के साथ इंटरफ़ेस

जीएसटीएन के अतिरिक्त, सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन का उद्देश्य वेब सेवाओं द्वारा एंटरप्राइज सर्विस बस लेयर के माध्यम से सीबीआईसी के भीतर विभिन्न एप्लीकेशन और बाह्य एजेंसियों के साथ इंटरफ़ेस करना था। जिन एप्लीकेशन को सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के साथ एकीकरण की आवश्यकता होगी, उनमें आइसगेट, एसीईएस, आईसीईएस, सीपीजीआरएएमएस, एनएसडीएल, आरबीआई, एमसीए 21, राज्य स्तरीय एप्लीकेशन मुख्य रूप से शामिल हैं।

निविदा चरण में ही यह स्पष्ट था कि जीएसटीएन के साथ एकीकरण जीएसटीएन द्वारा जारी किए गए एपीआई के माध्यम से होगा, अन्य एप्लीकेशन के संबंध में यह माना गया था कि इंटरफेसिंग प्रणाली की परिपक्वता के स्तर के आधार पर, फाइल शेयरिंग, फाइल स्थानांतरण, डीबी शेयरिंग आदि के माध्यम से एकीकरण को लागू करने की आवश्यकताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि, यह परिकल्पना की गई थी कि सभी डेटा

विनिमय सुरक्षित तरीके से किए जाएंगे, डेटा और संदेशों का विनिमय एसएसएल द्वारा सक्षम तरीकों से किये जाने की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भले ही जीएसटीएन के साथ इंटरफेस स्थापित किया जा चुका है, फिर भी अन्य बाह्य प्रणालियों और एजेंसियों के साथ इंटरफेस कार्यविधि का विकास अभी तक आरंभ नहीं किया गया है।

**सिफारिश 44: विभाग को अन्य एप्लीकेशन के साथ सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी एप्लीकेशन के इंटरफेस के विकास की शुरुआत करनी चाहिए।**

लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्ति को इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022) मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि उन्होंने अनुपालन के लिए सिफारिश को नोट कर लिया है।



(सिद्धार्थ बोनडाडे)

नई दिल्ली

दिनांक: 01 मार्च 2023

प्रधान निदेशक (माल एवं सेवा कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

नई दिल्ली

दिनांक: 02 मार्च 2023

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



---

---

# शब्दावली

---

---



## शब्दावली

एसीएल	अभिगम नियंत्रण तर्क
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस
अद्वैत	अप्रत्यक्ष कराधान में उन्नत विश्लेषिकी
सेएबी	परिवर्तन सलाहकार बोर्ड
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीडीआर	डिवीजन रेंज आयुक्तालय
सीई	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सीपीसी	केंद्रीय प्रसंस्करण प्रकोष्ठ
सीएलएस	संयोजन उद्ग्रहण योजना
डीसी	डेटा केंद्र
डीईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीआर	आपदा बहाली
डीएससी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र
एक्जिम	आयात निर्यात
जीएसटीआईएन	माल एवं सेवा कर पहचान संख्या
जीएसटीएन	माल एवं सेवा कर नेटवर्क
जीएसटीपी	माल एवं सेवा कर व्यवसायी
आईएफयू	एकीकृत वित्तीय इकाई
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीसी	इनपुट कर जमा
एलएएन	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एलडी	परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएसए	प्रमुख सेवा करार
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण
एनआरटीपी	अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
ओआईओ	मूल आदेश
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीवी	भौतिक सत्यापन
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
आरएफपी	प्रस्ताव निवेदन

आरटीजीएस	वास्तविक समय सफल निपटान
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
सेज़	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसआई	प्रणाली समेकक
एसएलए	सेवा स्तर करार
एसआरएस	सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश
एसएसएल	सिक्क्योर सॉकेट लेयर
एसएसओ आईडी	सिंगल साइन-ऑन
एसटी	सेवा कर
टीसीएस	स्रोत पर एकत्रित कर
टीडीएस	स्रोत पर की गई कर कटौती
यूएम	उपयोगकर्ता अभिगम प्रबंधन
यूटी	उपयोगकर्ता स्वीकरण परीक्षित
यूआई	यूजर इंटरफेस
यूआईएन	विशिष्ट पहचान संख्या
वीएपीटी	भेद्यता निर्धारण और भेदन परीक्षित
डब्ल्यूएन	वाइड एरिया नेटवर्क
एक्सएमएल	एक्स्टेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज। एक्सएमएल एक फ़ाइल प्रारूप है
जेडसीडीआर	डिवीजन रेंज जोन आयुक्तालय

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)